

उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केन्द्र  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्तशासी संस्था,  
भारत सरकार

# वार्षिक रिपोर्ट

2024-2025

# वषिय-सूची

क्र. सं.	वविरण	पृष्ठ संख्या
1.	नेक्टर के बारे में	7
2.	उदेश्य, लक्ष्य , प्रौद्योगिकी क्षेत्र	7
3.	नेक्टर समितियाँ (वित्तीय वर्ष 2024-2025)	8
4.	पूर्वोत्तर भारत में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देना	9
5.	मूल्य वर्धति उत्पादों के लिए केले के छदम तने उपयोग पर मूल्य शृंखला	22
6.	सौर नरिजलीकरण तकनीक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत को सशक्त बनाना	32
7.	नेक्टर द्वारा की गई भू-स्थानिक मानचित्रण एवं ड्रोन गतिविधियाँ	36
8.	नेक्टर, मुख्यालय शलांग में विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनरिंग और गणति प्रयोगशाला	44
9.	राष्ट्रीय पशुधन मशिन के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण चारे के बीज उत्पादन में सहायता	48
10.	असम में पारंपरिक टेराकोटा एवं मट्टी के बर्तनों के व्यवसाय की स्थिति में सुधार	52
11.	नेक्टर द्वारा समर्थति परियोजनाएँ	54
12.	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	63
13.	कार्यशालाएँ एवं विविध गतिविधियाँ	74
14.	समाचारों में नेक्टर	83
15.	लेखा-परीक्षण एवं लेखा वविरण	102

### महानिदेशक, नेक्टर की कलम से संदेश

उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केन्द्र (नेक्टर) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, राज्य सरकार के विभागों के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी वितरण एवं प्रसार के साथ-साथ विभिन्न तकनीकों पर क्षमता निर्माण की गतिविधियों में गहनता से कार्य किया है। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्य सरकार के विभागों तथा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कई स्थानों पर प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। नेक्टर के सभी कार्यक्रमों का संचालन संबंधित राज्यों के सभी हितधारकों के परामर्श भी से किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य नेक्टर के कार्यों के प्रसार में बढ़ोत्तरी करना है। इसमें प्रौद्योगिकी प्रसार, कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण तथा विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र को अत्यधिक लाभ प्राप्त हो।

नेक्टर ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण आजीविका के उन्नयन हेतु विभिन्न नवीन एवं चुनौतीपूर्ण तकनीकों के माध्यम से अनेक गतिविधियाँ प्रारंभ की हैं। संगठन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लगभग सभी कोनों में कृषि एवं बागवानी, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य एवं फल प्रसंस्करण, शिक्षा, अपशिष्ट से संसाधन, ड्रोन आदि जैसे क्षेत्रों में अपनी पहुँच बनाई है।

गत वित्तीय वर्ष के दौरान 13 फरवरी, 2025 को माननीय डॉ. जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा न्यू शिलांग में नेक्टर कार्यालय का शिलान्यास समारोह था। नेक्टर की यह सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सम्पूर्ण निर्माण कार्य सी पी डब्लू डी, शिलांग, मेघालय द्वारा किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान, नेक्टर ने पहले से निर्दिष्ट कई क्षेत्रों में और कौशल-आधारित प्रशिक्षण पहलों पर विभिन्न परियोजनाओं को वित्त पोषित किया। परियोजनाओं को पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में वितरित किया गया था। गत वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 3681 लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 40048 छात्रों को विभिन्न तकनीक के बारे में जानकारी दी गई और नेक्टर द्वारा विभिन्न स्थानों पर 3207 जनसम्पर्क कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान नेक्टर के नेतृत्व में इन सभी पहलों से 4500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ और लगभग 15,550 व्यक्तियों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा, जिनमें मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल हैं।

गत वित्तीय वर्ष के दौरान नेक्टर द्वारा दो प्रमुख आंतरिक गतिविधियाँ शुरू की गईं और सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गईं। (i) (आई आई एस ई आर) पुणे और मेघालय सरकार के स्मार्ट विलेज मूवमेंट के सहयोग से नेक्टर के शिलांग स्थित मुख्यालय में एक स्टैम शिक्षा प्रयोगशाला का विकास। इस पहल और स्कूल के भीतर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के साथ, छात्रों को STEM (अर्थात विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ करने का अवसर प्राप्त होता है।

(ii) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मेघालय सरकार के सम्मानित मुख्य सचिव द्वारा 'वसुंधरा' नामक किसानों के लिए मृदा परीक्षण किट का निर्माण भी किया गया था। किटों का इन-हाउस उत्पादन शुरू कर दिया गया है और पीएम-डिवाइन परियोजना के तहत पूर्वोत्तर के किसानों को वितरित किया गया है। हमारा लक्ष्य लगभग 25000 मृदा परीक्षण किटों का निर्माण करना है ताकि हमारे किसानों की सुविधा हो सके जो सीधे चल रहे पीएम-डिवाइन परियोजना 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैज्ञानिक जैविक खेती को बढ़ावा' से जुड़े हैं। पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए नेक्टर ने 9 कार्यान्वयन एजेंसियों (सार्वजनिक और निजी दोनों) पर विचार किया है। पहले से ही लगभग 155 कृषि प्रयोगशालाओं का निर्माण पूरा हो चुका है और प्रत्येक प्रदर्शन कृषि प्रयोगशाला में किसानों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। असम के 39 समूहों ने असम में तीसरे पक्ष के माध्यम से अपनी भूमि के लिए पीजीएस ग्रीन प्रमाणन भी प्राप्त किया इसका संस्करण तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि इसे आगामी वित्तीय वर्षों में लॉन्च कर दिया जाएगा। डैशबोर्ड में प्रत्येक कृषि प्रयोगशाला और प्रत्येक किसान समूह से जुड़े उत्पाद की पूरी जानकारी होगी। परियोजना के एक भाग के रूप में, नेक्टर ने सभी मास्टर किसानों को एक एंड्रॉइड मोबाइल भी वितरित किया है।

पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान, पूर्वोत्तर में केसर की खेती का नेक्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट भी जारी रहा। इसके तहत दो और राज्यों, मणिपुर और नागालैंड को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अन्य राज्यों में मौजूदा साइटों के साथ जोड़ा गया। यह बहुत आशाजनक है और संभावित है कि निकट भविष्य में पूर्वोत्तर का केसर एक बड़े बाजार में प्रवेश करेगा। हमने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मणिपुर में फाली, चिलाओ, लाई, चिंगमाई, खुनोउ, मरम, खुल्लेन, पुरल, चौन्नामई, तुंगजॉय, पुननामेई, लियाई और माओ में केसर की खेती शुरू की है और इनमें से लीलाई और माओ बड़े पैमाने पर खेती के लिए बहुत उपयुक्त पाए गए हैं। इसी तरह, नागालैंड में हमने खोनोमा, थानामीर, किफिर और लॉन्गटोकर में केसर की खेती शुरू की है और इन सभी में किफिर बहुत अच्छा पाया गया है।

अरुणाचल प्रदेश में मधुमक्खी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए नेक्टर को राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड से एक अतिरिक्त भित्तिचित्र परियोजना मिली है। यह परियोजना राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से पहले ही शुरू हो चुकी है।

पीएम-डिवाइन के अंतर्गत दो परियोजनाएँ परियोजना के उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर शुरू हो चुकी हैं और इनकी प्रगति काफी संतोषजनक है। पहले चरण में, 'मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए केले के छद्म तने के उपयोग' के 6 संयंत्रों का निर्माण पहले ही हो चुका है और इन संयंत्रों से संबंधित सभी मशीनें खरीद ली गई हैं। नागालैंड के चुमुकुदिमा संयंत्र में विभिन्न उत्पादों का उत्पादन शुरू हो चुका है और इसका संचालन उद्यमी संघ नामक एक स्थानीय एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। दूसरे चरण के लिए, पूर्वोत्तर के विभिन्न स्थानों पर 6 और संयंत्रों का निर्माण शुरू हो चुका है और आशा है कि यह इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा।

डीजीसीए द्वारा अनुमोदित नेक्टर के रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) ने एक उचित आकार ले लिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत 12 उम्मीदवारों के साथ 10 से अधिक बैच पूरे हो चुके हैं। आरपीटीओ पूर्वोत्तर के युवाओं को आजीविका का एक बहुत अच्छा विकल्प प्रदान कर रहा है।

अपनी पूरी टीम के सदस्यों के पूर्ण सहयोग से, नेक्टर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तकनीकी उद्यमिता, बांस उत्पाद उत्पादन, मधुमक्खी पालन, एकीकृत खेती, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, ड्रोन निर्माण और पीएमकेवीवाई-4, पीएम विश्वकर्मा आदि के अंतर्गत विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों पर केंद्रित विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए हैं। इन कार्यक्रमों ने 3,500 से अधिक व्यक्तियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है, जिसमें व्यावहारिक कौशल विकास, उत्पाद निर्माण और प्रमाणन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य सरकार के विभागों, एजेंसियों और संगठनों के साथ सहयोग कार्यक्रमों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में सहायक रहा है।

नेक्टर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और विस्तार परियोजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इसके अतिरिक्त, नेक्टर विभिन्न कार्यशालाओं और आयोजनों के माध्यम से हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने को बढ़ावा दे रहा है।

आंतरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए और सहयोग से, नेक्टर ने मेघालय जैव विविधता बोर्ड (एन बी बी), मेघालय सरकार द्वारा समर्थित, 'कार्बन वित्तपोषण और पादप-विविधता हीट मैप का विश्लेषण करने के लिए संकर प्रणालियों का उपयोग करते हुए मेघालय में वन सर्वेक्षण और मानचित्रण' नामक एक बड़ी परियोजना पूरी की है। इसके साथ ही, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 'स्वामित्व' के अंतर्गत कुछ अन्य परियोजनाएँ भी पूरी की गई हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, नेक्टर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) में पहलों और परियोजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न संगठनों और संस्थानों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

अंत में, मैं नेक्टर के विजन और मिशन को साकार करने में दिए गए उनके भरपूर सहयोग के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं नेक्टर की शासन परिषद, कार्यकारी परिषद, वित्त समिति और परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के सम्मानित सदस्यों को भी नेक्टर की गतिविधियों का मार्गदर्शन और आलोचनात्मक निगरानी करने और हमेशा सर्वोत्तम संभव सुझाव प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं पीएम-डिवाइन दोनों परियोजनाओं के सभी विशेषज्ञ



सदस्यों को भी परियोजना की नियमित निगरानी करने और परियोजना के उद्देश्यों के परिणामों में मूल्य जोड़ने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव प्रदान करने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ। सभी पूर्वोत्तर राज्य सरकार के विभागों और मूल मंत्रालय के समर्थन और शुभकामनाओं से पिछले 2-3 वर्षों के दौरान नेक्टर की गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हुई है, और मैं सभी हितधारकों को उनके अमूल्य समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं पीएम- डिवाइन के अंतर्गत दो परियोजनाओं में सहयोग देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

नेक्टर टीम के सभी सदस्यों की सराहना करता हूँ, जिन्होंने संगठन की भावना को गतिमान बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम किया है। मुझे विश्वास है कि उनके योगदान और सच्ची भागीदारी से, नेक्टर पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नवीन तकनीकी सीमाओं को उजागर करने की अपनी यात्रा जारी रखेगा। इसी आशा के साथ, मैं आपके समक्ष नेक्टर की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।

डॉ. अरुण कुमार शर्मा

वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025



## नेक्टर के बारे में

उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (नेक्टर) की स्थापना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत शिलांग, मेघालय में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। नेक्टर के निर्माण को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 7 जून, 2012 को मंजूरी दी थी और इसे 30 नवंबर, 2012 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया था। मंत्रिमंडल के एक निर्णय के बाद, दो पूर्व प्रौद्योगिकी मिशनों, 2004 में शुरू किए गए राष्ट्रीय बांस अनुप्रयोग मिशन (NMBA) और 2009 में शुरू किए गए भू-स्थानिक अनुप्रयोग मिशन (MGA) को 1 जनवरी, 2014 से उनकी परिसंपत्तियों और देनदारियों सहित नेक्टर में विलय कर दिया गया।

नेक्टर का लक्ष्य सार्वजनिक और सामाजिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के प्रचार, पोषण और अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने वाला एक प्रमुख संस्थान बनना है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों, संस्थानों और सरकारों तक प्रौद्योगिकी की पहुँच और लाभों का विस्तार करना है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में समतामूलक और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। यह केंद्र क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वैज्ञानिक विभागों और संस्थानों की उन्नत तकनीकों का लाभ उठाएगा।

नेक्टर कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जल स्वच्छता, जैव विविधता, जलग्रहण प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, बागवानी, बुनियादी ढाँचे की योजना और विकास, तथा टेली-स्कूलिंग के माध्यम से शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों के साथ उपयुक्त तकनीकों के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। केंद्र का लक्ष्य रोजगार सृजन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देना है।

नेक्टर का मुख्यालय शिलांग में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक पट्टे पर दिए गए भवन में स्थित है, जिसके गुवाहाटी में दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेक्टर अगरतला, त्रिपुरा में भी कार्यरत है और बांस एवं बेंत विकास संस्थान (BCDI) का प्रबंधन करता है। जहाँ नेक्टर के अधिकांश कर्मचारी पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं पर काम करते हैं, वहीं कुछ प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी आईआईटी - दिल्ली परिसर के विश्वकर्मा भवन स्थित दिल्ली कार्यालय से काम करते हैं। मेघालय सरकार द्वारा आवंटित 5 एकड़ भूमि पर, न्यू शिलांग टाउन एरिया में एक स्थायी नेक्टर परिसर की योजना बनाई गई है, जो वर्तमान में एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार की सहायता से निर्माण योजना के चरण में है।

**लक्ष्य :** सार्वजनिक और सामाजिक भलाई के लिए स्थापित प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने, पोषित करने और सुनिश्चित करने के लिए अग्रणी केंद्र बनना, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के न्यायसंगत और समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लोगों, समुदायों, संस्थानों और सरकारों के बीच प्रौद्योगिकी के लाभों का विस्तार करना।

### उद्देश्य:

- अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और अन्य प्रतिष्ठित स्रोतों से प्राप्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग और लाभ उठाना
- स्थानीय, प्राकृतिक और अन्य संसाधनों का उपयोग
- अनुकूलनीय प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन
- उद्यमिता और आजीविका के लिए संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम
- समस्या की पहचान और समाधान के हेतु कार्यशालाएं, सम्मेलन और गोष्ठियां

### प्रौद्योगिकी क्षेत्र:

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
- बांस एवं संबद्ध क्षेत्र
- संचार एवं आईटी

- पर्यावरण एवं स्थिरता
- खाद्य प्रसंस्करण
- भू-स्थानिक
- स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र
- आजीविका
- प्राकृतिक रेशे एवं वस्त्र

### नेक्टर समितियाँ वित्तीय वर्ष 2024-2025

#### ● नेक्टर की शासी परिषद (GC)

1.	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
3.	मुख्य सचिव, असम सरकार	सदस्य
4.	मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार	सदस्य
5.	मुख्य सचिव, मेघालय सरकार	सदस्य
6.	मुख्य सचिव, मिजोरम सरकार	सदस्य
7.	मुख्य सचिव, नागालैंड सरकार	सदस्य
8.	मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार	सदस्य
9.	मुख्य सचिव, त्रिपुरा सरकार	सदस्य
10.	सचिव, उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी)	सदस्य
11.	महानिदेशक, नेक्टर	सदस्य सचिव

#### ● नेक्टर की कार्यकारी परिषद (EC)

1	महानिदेशक, नेक्टर	अध्यक्ष
2	श्रीमती एस. लालथांगजो , आर्थिक सलाहकार एवं प्रभारी निदेशक (एस एंड टी), एनईसी	सदस्य (पूर्वोत्तर परिषद के प्रतिनिधि)
3	श्रीमती जेनेइखुनओ विमेरो , संयुक्त सचिव एवं निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , नागालैंड सरकार	सदस्य (पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि)

#### ● नेक्टर की वित्त समिति (FC)

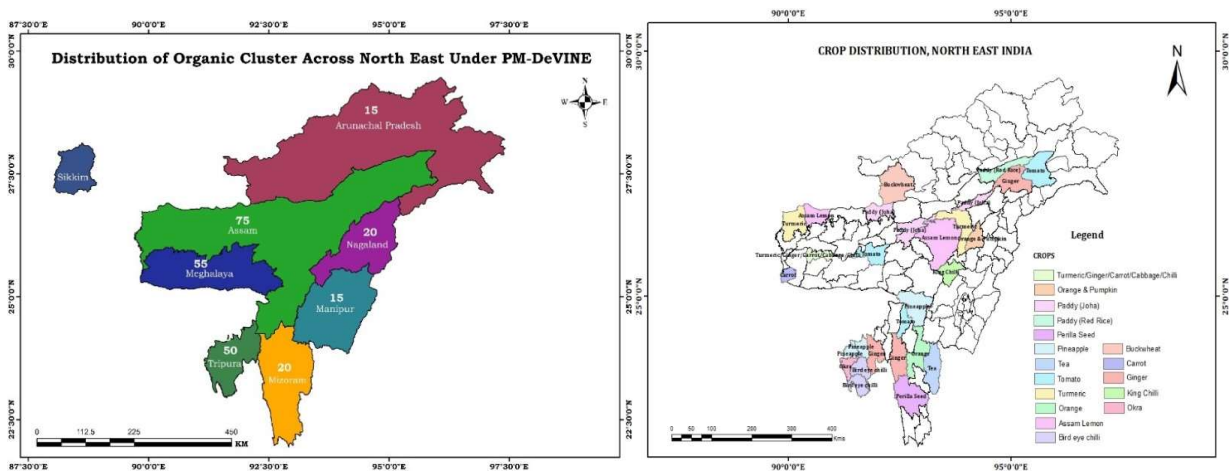
1	डॉ. अरुण कुमार शर्मा , महानिदेशक, नेक्टर	अध्यक्ष
2	श्री विश्वजीत सहाय, आईडीएएस, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, डीएसटी	सदस्य
3	श्रीमती एस. लालथांगजो , आर्थिक सलाहकार एवं प्रभारी निदेशक (एस एंड टी), एनईसी	सदस्य
4	श्रीमती जेनेइखुनओ विमेरो , संयुक्त सचिव एवं निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , नागालैंड सरकार	सदस्य (पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि)
5	डॉ. कृष्ण कुमार, सलाहकार (तकनीकी ), नेक्टर	सदस्य
6	श्री सिमोन फुकन, वरिष्ठ । प्रशासनिक अधिकारी, नेक्टर	सदस्य सचिव

## पूर्वोत्तर भारत में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देना

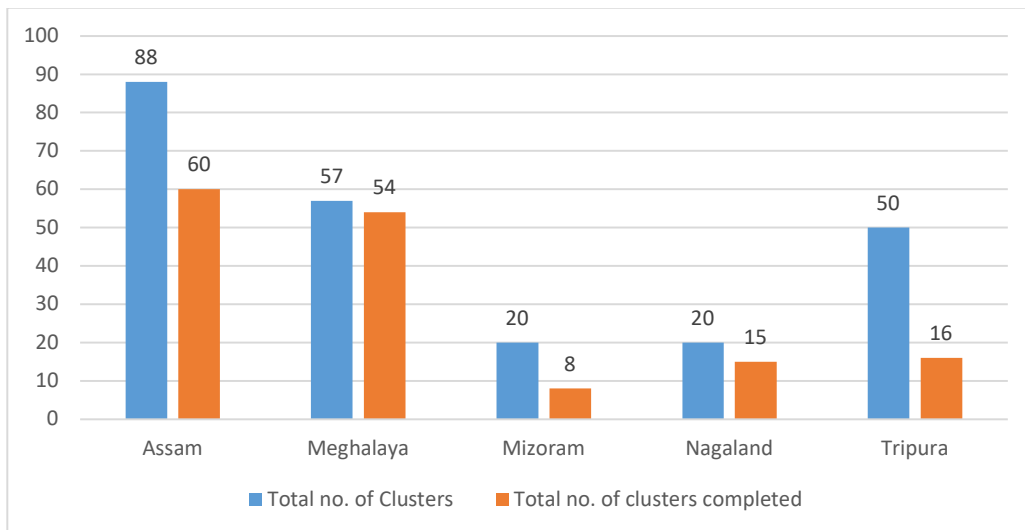
### ➤ पृष्ठभूमि

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पीएम-डिवाइन योजना के तहत स्वीकृत परियोजना "पूर्वोत्तर भारत में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देना" का उद्देश्य जैविक खेती पर तकनीकी विशेषज्ञता, प्रदर्शनकारी कृषि प्रयोगशालाओं का विकास, रोपण सामग्री की आपूर्ति, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, ड्रोन डेटा प्रबंधन और एमआईएस और डिजिटल कृषि के माध्यम से पूरे पूर्वोत्तर में 250 जैविक प्रमाणित क्लस्टर बनाना है, जिसका उद्देश्य खेत को बाजार से जोड़ना और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इसके लाभों को सुनिश्चित करना है।

### ➤ ड्रोन सर्वेक्षण और क्लस्टर स्तरीय मानचित्रण



चित्र: पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक समूहों का वितरण और समूह स्तर पर फसल वितरण

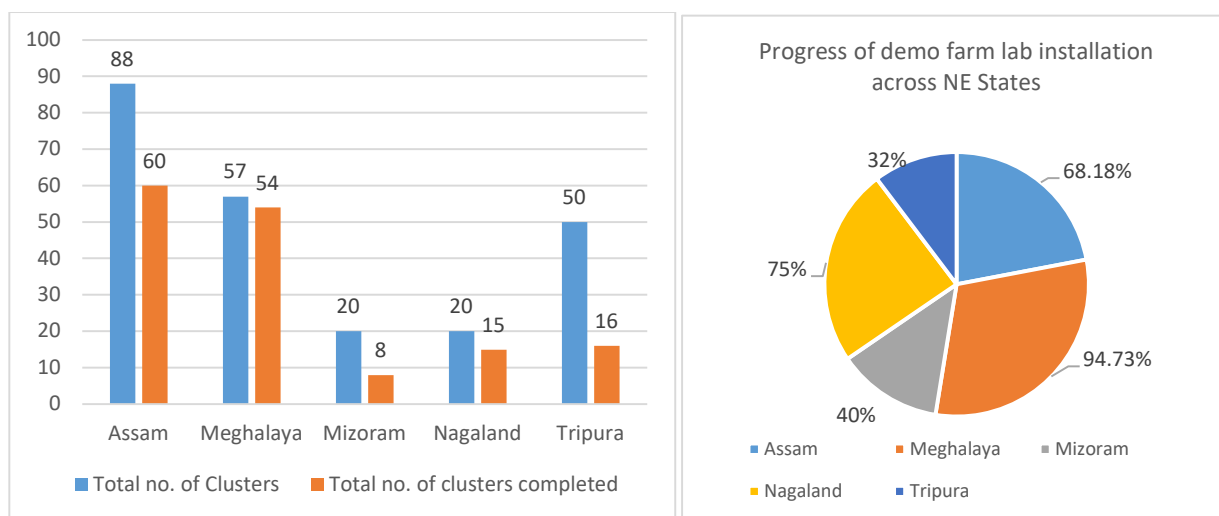


### ➤ ☐ प्रदर्शन कृषि प्रयोगशाला की स्थापना

प्रदर्शन कृषि प्रयोगशाला परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। यह किसानों के लिए एक फील्ड स्कूल के रूप में कार्य करता है जहाँ क्लस्टर स्तर पर 100 किसानों को मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा जैविक खेती के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदर्शन कृषि प्रयोगशाला में खेती के दौरान उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जैविक आदानों को तैयार करने की भी व्यवस्था होगी। अब तक, विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन स्थलों पर 150 कृषि प्रयोगशालाएँ पूरी हो चुकी हैं।



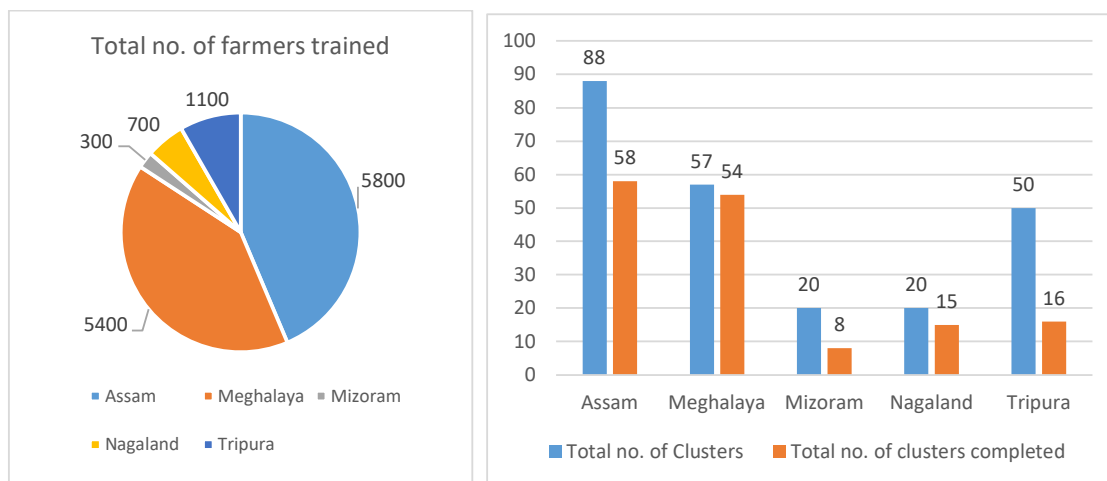
चित्र: प्रदर्शन कृषि प्रयोगशाला का उद्घाटन



#### □ समूह स्तर पर किसानों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा समूह में किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक असम में 58 क्लस्टर, मेघालय में 54 समूह, नागालैंड में 7 समूह, त्रिपुरा में 11 समूह और मिज़ोरम में 3 समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले किसानों की कुल संख्या 13300 है। प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों के निर्माण, पीजीएस जागरूकता, विपणन संपर्क और फसल-विशिष्ट जैव इनपुट अनुशंसाओं पर केंद्रित था।





➤ चित्र: क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षु किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम

### बीज वितरण

प्रस्तावित फसल वस्तुओं, आधारभूत सर्वेक्षण और फसल चक्र के अनुसार किसानों को जैविक रोपण सामग्री प्रदान की गई, जिसमें धान (जोहा, लाल और काला चावल), असम नींबू, कुट्टू, अनानास, अदरक, हल्दी, संतरा, केला, लौकी और मौसमी सब्जियां जैसी विभिन्न फसलें शामिल हैं।





चित्र: किसानों को रोपण सामग्री का वितरण

### □ वसुंधरा मृदा कार्बनिक कार्बन जांच किट

नेक्टर ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के तकनीकी सहयोग से "वसुंधरा" मृदा कार्बनिक कार्बन जांच किट विकसित की है। पीएम-डिवाइन योजना के तहत कुल 25,000 किट का निर्माण और वितरण किसानों को निःशुल्क किया जाएगा। इसके लिए, शिलांग स्थित नेक्टर परिसर में एक लघु प्रयोगशाला-सह-निर्माण इकाई की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन श्री डी. पी. वहलांग, मुख्य सचिव, मेघालय सरकार



ने डॉ. एम. मोहंती, प्रमुख, स्वायत्त विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की उपस्थिति में किया। अब तक, नागालैंड के 100 किसानों को मृदा परीक्षण किट प्राप्त हो चुकी है और जुलाई के अंत तक 5,000 और किसानों को किट प्राप्त होने की संभावना है।



चित्र: श्री डी पी वाहलांग मुख्य सचिव मेघालय सरकार द्वारा नेक्टर, शिलांग में वसुंधरा मृदा कार्बनिक कार्बन जांच प्रयोगशाला सह विनिर्माण इकाई का उद्घाटन।

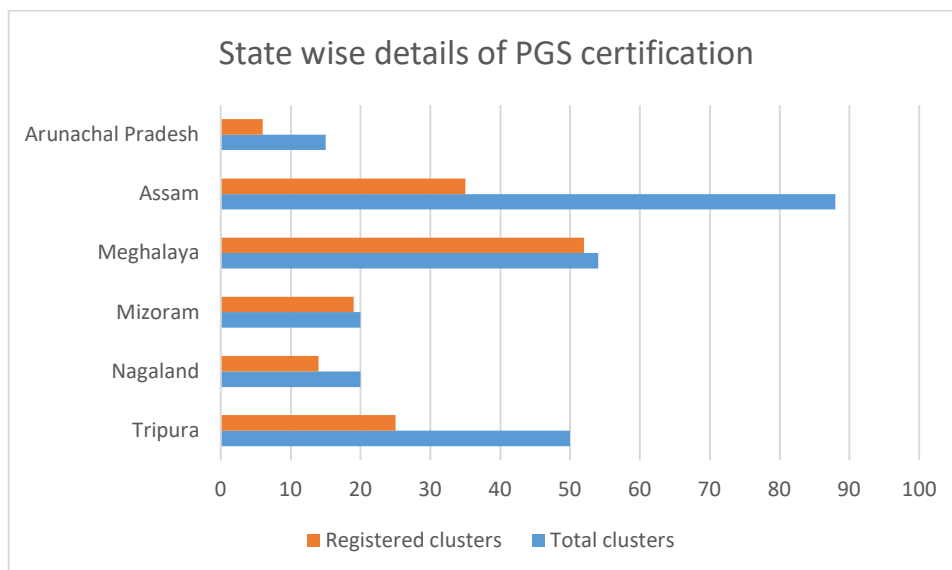




चित्र: नेक्टर के महानिदेशक और सलाहकार (तकनीकी) द्वारा नागालैंड में किसानों को मृदा परीक्षण किट और प्रशिक्षण सामग्री का वितरण

#### □ पीजीएस प्रमाणन

अब तक, 41 स्थानीय समूहों (4100 किसानों) को अपना पहला पीजीएस ग्रीन 1 स्कोप प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, इसके अलावा, 151 क्लस्टर (15100 किसान) पहले ही पीजीएस ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं और इन क्लस्टरों के लिए पहला स्कोप प्रमाण पत्र आगामी खरीफ सीजन तक मिलने की संभावना है।



### PGS - India

A Participatory Organic Guarantee Programme  
Department of Agriculture & Farmer Welfare  
Govt. of India

Certificate No.: 20250516120841  
Date of Issue (DD/MM/YYYY) - 16/05/2025

### Scope Certificate

This is to certify that the product(s) and areas(s) belonging to PGS-India  
HAKUA ABADARI NECTAR PGS GROUP  
Registered with Regional Council No PGSI/NEC/RC-4635  
QMARK INTERNATIONAL CERTIFICATIONS PVT LTD  
are in accordance with requirements of  
**PGS-India National Standards For Organic Production**  
For the process of :  
"Crop Production"  
This Scope Certificate  
valid from (DD/MM/YYYY) 16/05/2025 until 16/05/2026  
for those farmers product(s) and area(s) specified in the annexure 257354

The validity of this certificate solely depends on the continued compliance with the required standards  
and PGS-India guidelines.

Signature of PGS India Group Leader  
Local Group No. LG61158692013

Authorised by : QMARK INTERNATIONAL CERTIFICATIONS PVT LTD  
Regional Council for PGS in ASSAM  
Authorization No. - PGSI/NEC/RC-4635  
Date - 16/05/2025

*Fig: GS-1 Scope certificate*

### □ सूचना प्रणाली प्रबंधन

सूचना प्रणाली के प्रबंधन हेतु, एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल आधारित ऐप विकसित किया गया है जो मृदा आँकड़े, किसानों का विवरण, फसल विवरण, भौगोलिक विशिष्टताओं आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। यह सभी हितधारकों, सरकारी विभागों और



उद्यमियों के लिए भविष्य के संदर्भ हेतु एक संग्रह और डेटाबेस के रूप में भी काम करेगा। इस मोबाइल आधारित ऐप का हाल ही में गृह मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा शुभारंभ किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक क्लस्टर डिजिटल कृषि और डेटाबेस से अच्छी तरह जुड़ा हो, सभी मास्टर प्रशिक्षकों को स्मार्ट फोन वितरित किए जा रहे हैं।



चित्र: नेक्टरस्थायी परिसर के शिलान्यास समारोह के दौरान मोबाइल ऐप का शुभारंभ

**Dr Jitendra Singh** @DrJitendraSingh  
 Distributed Smartphones and Vasundhara Kits to Agri-#StartUps and farmers who are being supported technically and otherwise by "North East Center for Technology Application & Reach" #NECTAR. #Shillong.





चित्र: नेक्टर द्वारा विभिन्न अवसरों पर मास्टर प्रशिक्षकों को स्मार्ट फोन का वितरण

#### □ प्रशिक्षण सामग्री का विमोचन एवं वितरण

नेक्टर ने "पूर्वोत्तर में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देने" के लिए दो प्रशिक्षण सामग्री (खंड I और II) संकलित की हैं। प्रशिक्षण सामग्री में जैविक खेती के व्यापक क्षेत्र को शामिल किया गया है, जैसे जैविक कृषि का अवलोकन, विभिन्न प्रकार के जैव-सामग्री (जीवामृत, बीजामृत, वर्मीकम्पोस्ट, अग्निहोत्र, नीमोष्ठ आदि) तैयार करने की विधियाँ, फसल चक्र और क्षेत्र की प्रत्येक संभावित फसल की खेती की रूपरेखा। इस प्रशिक्षण सामग्री का विमोचन श्री अभय करंदीकर, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा आईआईटी-गुवाहाटी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के दौरान किया गया।





चित्र: आईआईटी-गुवाहाटी में आईआईएसएफ 2024 के दौरान प्रशिक्षण सामग्री का विमोचन



चित्र: किसानों को प्रशिक्षण सामग्री का वितरण



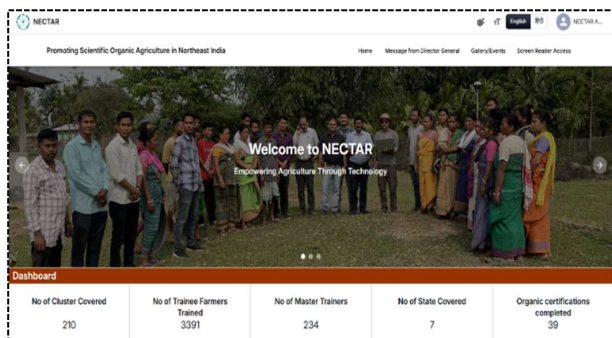


चित्र: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के माननीय निदेशक श्री विजय गोयल द्वारा नेक्टर अधिकारियों की उपस्थिति में डेमो फार्म लैब का उद्घाटन।

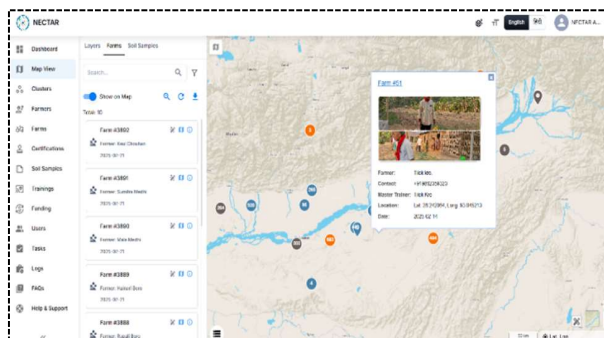
#### □ डिजिटल कृषि डेटा प्रबंधन

• पीएम-डिवाइन योजना के अंतर्गत "पूर्वोत्तर भारत में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देना" परियोजना के अंतर्गत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है, ताकि परियोजना को वास्तविक समय के आधार पर देखा और मॉनिटर किया जा सके। मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके किसान स्तर के डेटा को संग्रहीत किया जा रहा है और सीधे नेक्टर कार्यालय, गुवाहाटी में स्थित सुरक्षित सर्वर पर भेजा जा रहा है, जिसे डैशबोर्ड का उपयोग करके वास्तविक समय के आधार पर देखा और विश्लेषण किया जा सकता है। किसान स्तर की जानकारी जैसे कि उनके खेतों का संबंधित जियोटैग किया गया स्थान, अक्षांश-देशांतर, ली गई तिथि और समय, व्यक्तिगत खेत क्षेत्र की गणना, किसान जीवनवृत्त आदि कुछ ऐसी जानकारी हैं जिन्हें मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके संग्रहीत किया जाएगा।

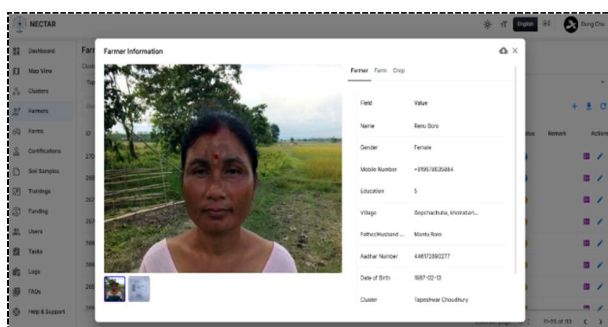
• प्रबंधन सूचना प्रणाली सांख्यिकीय और ग्राफिकल इंटरफ़ेस से सुसज्जित है जो उपयोगकर्ता को इच्छित जानकारी को देखने और मॉनिटर करने के साथ-साथ इच्छित उपयोग के लिए डाउनलोड करने में मदद करेगा। एमआईएस डैशबोर्ड और मोबाइल एप्लिकेशन उन प्रमुख घटकों में से एक है जो परियोजना के लिए विशिष्ट प्रासंगिक जानकारी को कैप्चर, ट्रैक और संग्रहीत करने में मदद करेंगे।



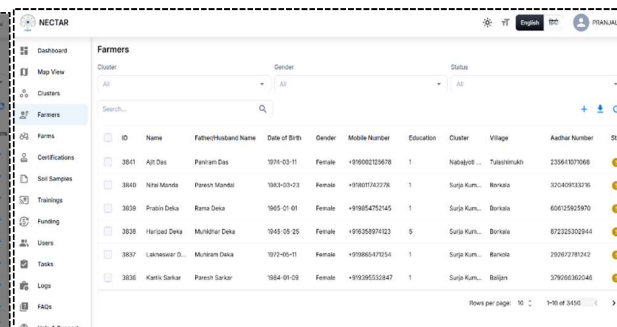
Home Page



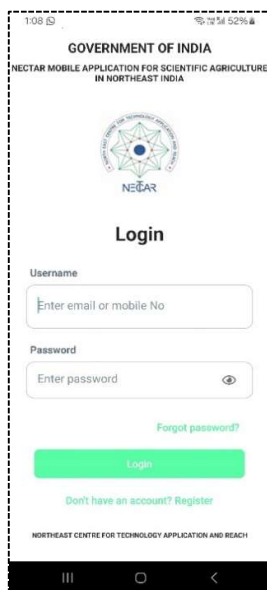
Geo Tagged locations



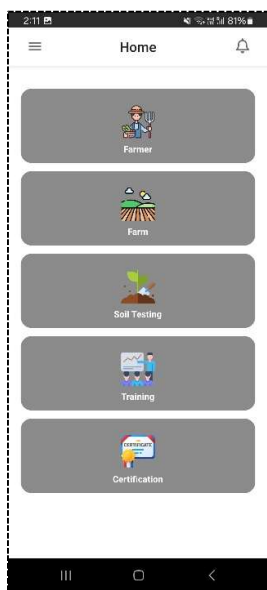
Farmer Database entry



चित्र : प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड (डेस्कटॉप वेबसाइट दृश्य)



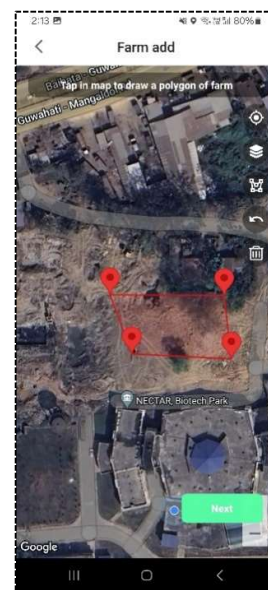
Login Page



Homepage



Farmer details



Geotagging feature

चित्र : मोबाइल दृश्य में प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड



## NECTAR Launches Organic Agriculture Project In Arunachal Under PM-DevINE Scheme

By Admin · JUN 5, 2025

SHARE NEWS



Share Facebook Twitter Google+ YouTube Pinterest Email

205 0

East Kameng/West Kameng, June 5, 2025 – In a significant step towards advancing organic agriculture in Arunachal Pradesh, the North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), an autonomous body under the Department of Science and Technology, Government of India, has initiated key interventions under the project "Promoting Scientific Organic Agriculture in the North East Region."

Funded by the Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER) under the PM-DevINE scheme, the project is being implemented in 15 clusters across East Kameng and West Kameng districts.

The PM-DevINE Organic Scheme aims to create a robust organic farming ecosystem throughout the Northeastern states by focusing on farmer training and capacity building, facilitating organic certification, establishing demonstrative farm labs at the cluster level, developing community seed banks, and creating a digital architecture using modern technologies such as UAVs. This digital system will integrate key components such as farmers' details, yield, soil characteristics, and more for data-driven decision-making. It also emphasizes market linkage of organic produce through e-marketing platforms and dedicated organic outlets.

The scheme envisages the establishment of 250 organic-certified clusters, each guided by a Master Trainer and involving 100 trainee farmers. The overall goal is to train 25,000 farmers across the Northeast, ensuring their produce is certified and connected to viable markets. The state-wise distribution of these clusters is as follows: Assam (75), Meghalaya (55), Tripura (50), Mizoram (20), Nagaland (20), Manipur (15), and Arunachal Pradesh (15).

In Arunachal Pradesh, the project targets 1,500 farmers across 15 clusters. The focus areas include scientific capacity building, land certification under the Participatory Guarantee System (PGS), and digital monitoring of progress.

To enhance field coordination and digital data management, 15 smartphones were distributed to Master Trainers in East and West Kameng districts. These devices will be used to track farming activities, collect field-level data, and ensure efficient communication among trainers, farmers, and agricultural experts to address on-ground challenges effectively.

Additionally, Master Trainers received training materials to support farmer education sessions within the clusters. These materials include modules on organic practices, composting techniques, and natural pest management—designed to strengthen grassroots knowledge on sustainable farming practices.

As part of the seed support initiative, buckwheat seeds were distributed in several clusters: four clusters in Shergaon, one in Jigaon, one in Membachur, and four clusters in Rupa and Thongre.

The distribution ceremony was graced by several senior NECTAR officials, including Shri Rakesh Kumar Sarmah (Chief Coordinator, Technical), Dr. Prabhat Borpuza (Regional Officer), Shri Pranjal Saikia (MIS Coordinator), Shri Dharmendra Kumar Jha (Senior Analyst), and Shri Bipul Sinha (Junior Analyst).

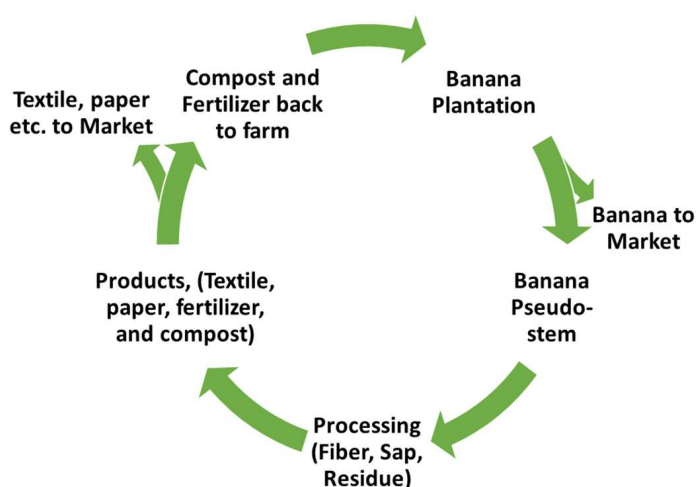
Share Facebook Twitter Google+ YouTube Pinterest Email

205 0

## मूल्य-वर्धित उत्पादों के लिए केले के छद्म उपयोग पर एक मूल्य श्रृंखला

### परियोजना अवलोकन

पीएम- डिवाइन योजना के अंतर्गत नेक्टर की आजीविका सुधार परियोजना, केले के छद्म तने - एक पारंपरिक रूप से त्यागे जाने वाले कृषि उपोत्पाद - के इर्द-गिर्द एक स्थायी, समावेशी मूल्य श्रृंखला का निर्माण करने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में कार्यान्वित, यह परियोजना प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमिता, हरित नवाचार और ग्रामीण आय वृद्धि को बढ़ावा देती है। अपने मूल में, यह पहल शून्य-अपशिष्ट प्रौद्योगिकी को एकीकृत करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि केले के छद्म तने का प्रत्येक भाग मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित हो जाए और कोई अवशेष न बचे। यह दृष्टिकोण पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम रखते हुए संसाधन दक्षता और मूल्य सृजन को अधिकतम करता है।



### छद्म तने पर आधारित शून्य-अपशिष्ट वृत्तीय अर्थव्यवस्था मॉडल

केले के छद्म तने को रेशे, जैविक जैव-उर्वरक, कागज, सूत, शाकाहारी चमड़ा और खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करके, यह पहल किसानों, कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए आय के नए स्रोत खोलती है। यह परियोजना न केवल टिकाऊ कृषि और अपशिष्ट से धन रूपांतरण पर जोर देती है, बल्कि स्थानीय समुदायों को चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल और आत्मनिर्भर विकास में भाग लेने के लिए सशक्त भी बनाती है।

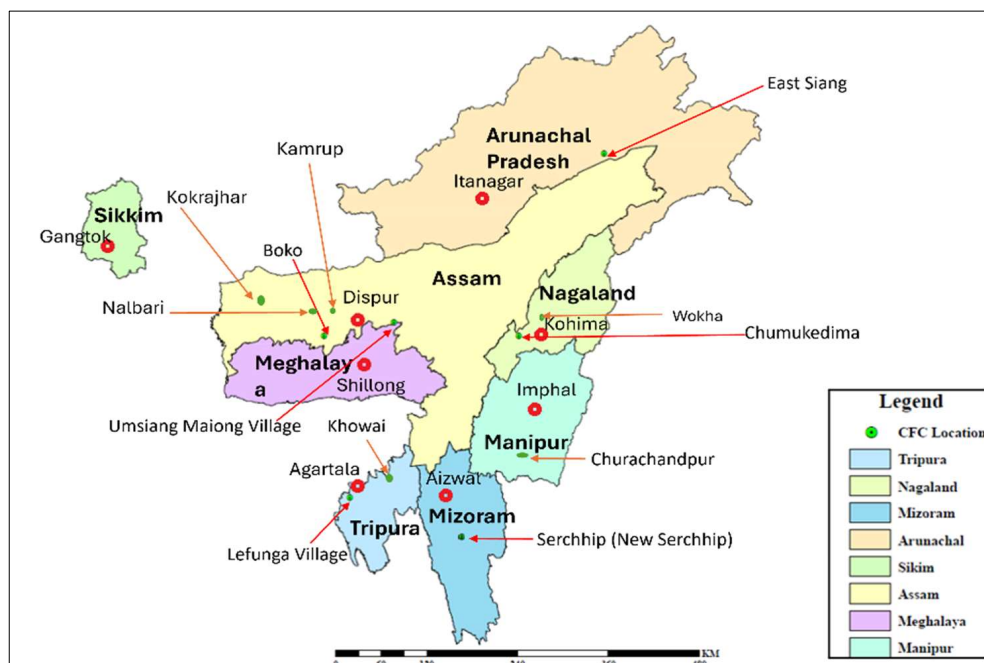
### परियोजना के उद्देश्य

पूर्वोत्तर में बारह स्थानों पर सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करना है ताकि केले के छद्म तने को विविध मूल्यवर्धित उत्पादों में संसाधित किया जा सके। इनमें गैर-बुने हुए कपड़े और हस्तशिल्प के लिए रेशा निष्कर्षण, रस-आधारित जैविक तरल उर्वरक, खाद्य कोर-आधारित खाद्य पदार्थ, कागज उत्पाद, और शाकाहारी चमड़ा और धागा जैसी अन्य नवीन सामग्रियाँ शामिल हैं। यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक सीएफसी ग्रामीण रोजगार, प्रशिक्षण और औद्योगिक उत्पादन का केंद्र बनेगा, जिससे 175 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से और द्वितीयक रोजगार तथा उद्यम विकास के माध्यम से कई अन्य लोगों को लाभ होगा। किसानों को केले के पौधे के प्रत्येक घटक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे उस पदार्थ से, जिसे कभी कृषि अपशिष्ट माना जाता था, काफ़ी अधिक कमाई कर सकेंगे।

## कार्यान्वयन स्थल

परियोजना दो चरणों में शुरू की गई है - चरण I में छह स्थानों को शामिल किया गया है: पूर्वी सियांग (अरुणाचल प्रदेश), बोको (असम), री-भोई (मेघालय), सेरछिप (मिजोरम), चुमौकेदिमा (नागालैंड) और अगरतला (त्रिपुरा)।

दूसरे चरण का विस्तार अन्य छह जिलों में किया जाएगा: असम में कोकराझार, कामरूप और नलबाड़ी ; मणिपुर में चुराचंदपुर ; नागालैंड में वोखा ; और त्रिपुरा में लुफंगा

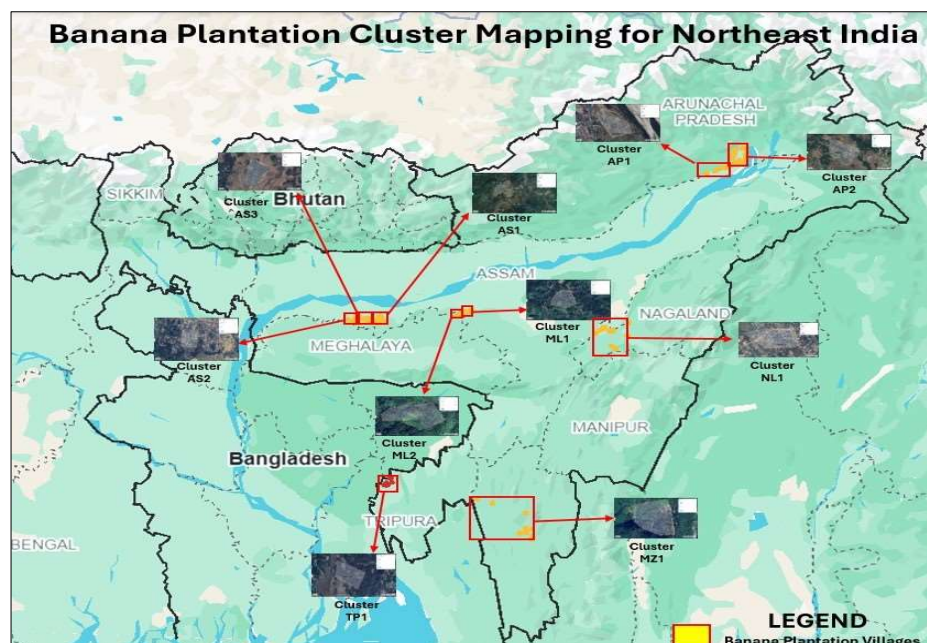


चित्र: पूर्वोत्तर क्षेत्र में 12 सीएफसी के लिए प्रस्तावित स्थल

## क्लस्टर पहचान और खेती मानचित्रण

पीएम- डिवाइन आजीविका सुधार परियोजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना हेतु प्रारंभिक आधारभूत कार्य के एक भाग के रूप में , चरण I के छह राज्यों में गूगल अर्थ-आधारित भू-मानचित्रण और भू-मान्यता सर्वेक्षणों का उपयोग करके एक व्यापक क्लस्टर पहचान अभ्यास किया गया। इस प्रयास का उद्देश्य प्रत्येक सीएफसी के पास कच्चे माल की उपलब्धता और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केले की खेती वाले क्षेत्रों को चिन्हित करना था।

इस अभ्यास के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में रणनीतिक रूप से स्थित क्लस्टरों की पहचान की गई। अरुणाचल प्रदेश (पूर्वी सियांग) में, नगोरलुंग , लिङ्का और नारी जैसे गांवों को आवरित करने वाले दो क्लस्टर लगभग 3.48 वर्ग किमी में फैले हैं। असम (बोको) में तीन क्लस्टर शामिल हैं- जोंगाखुली , मदांग और सिंगरा- जो सामूहिक रूप से लगभग 8.18 वर्ग किमी को आवरित करते हैं। नागालैंड ( चुमकेदिमा ) में चुमू , निउलैंड और मेंगुजुमा सहित दो क्लस्टर हैं , जो 3.68 वर्ग किमी में फैले हैं। त्रिपुरा ( अगरतला ) में, एक एकल क्लस्टर 0.54 वर्ग किमी में फैला है। मिजोरम ( सेरछिप ) में एक क्लस्टर है जो 1.54 वर्ग किमी में फैला है मैयोंग और उमलिंग में कुल 1.48 वर्ग किमी क्षेत्र में केले की खेती की जाती है।



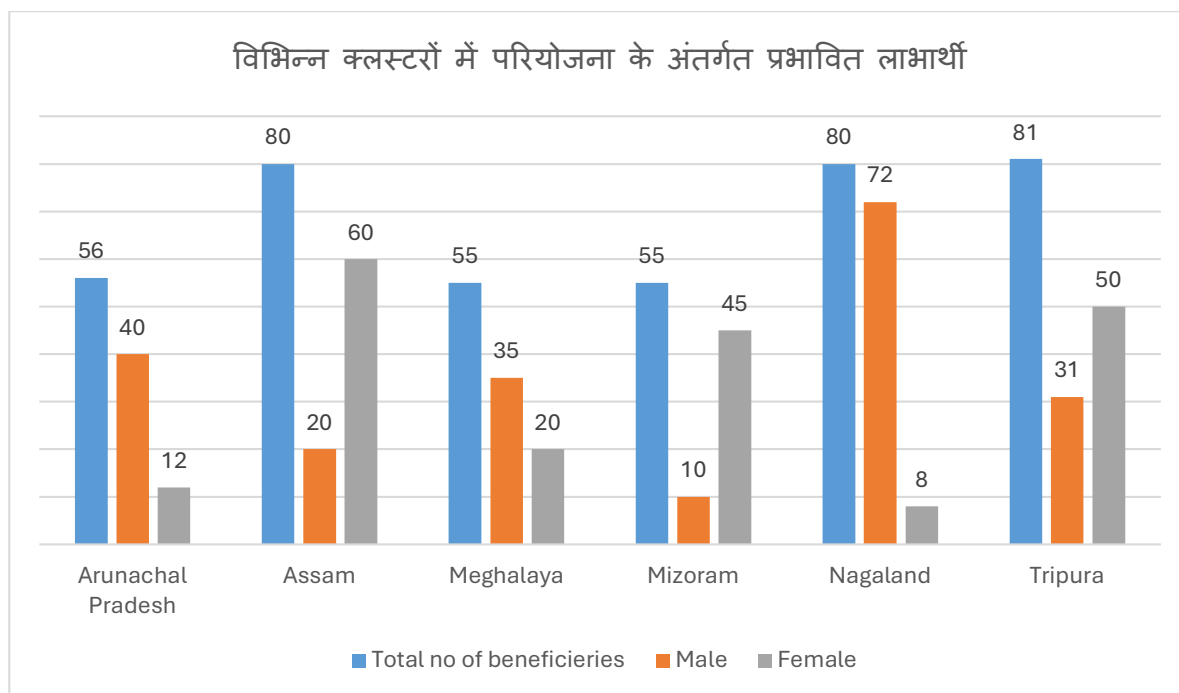
चित्र : पूर्वोत्तर भारत में केले के बागान वाले गांवों का क्लस्टर मानचित्रण।

यद्यपि वर्तमान में चिन्हित कृषि योग्य भूमि कम लग सकती है, फिर भी आगे के सर्वेक्षणों से पता चला है कि इन क्षेत्रों की कृषि - जलवायु परिस्थितियाँ और मृदा संरचना केले की खेती के लिए अत्यधिक अनुकूल हैं। हालाँकि, इन क्षेत्रों की पूरी क्षमता का दोहन करने और खेती का विस्तार करने के लिए, केले की खेती के लाभों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर व्यापक किसान शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाने की अत्यंत आवश्यकता है। यह परियोजना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और मापनीयता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

### प्राप्त की गई उपलब्धियाँ

पीएम -डिवाइन आजीविका सुधार परियोजना ने पहले चरण के छह स्थलों पर उल्लेखनीय प्रगति की है, जो बुनियादी ढाँचे के विकास, उपकरण स्थापना, कौशल निर्माण और स्थानीय सहभागिता के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। प्रत्येक स्थल का विकास उसकी विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक क्षमताओं के अनुरूप किया गया है, जिससे परियोजना समावेशी और क्षेत्र-विशिष्ट दोनों बन पाई है।





प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:

- **बुनियादी ढांचे की तैयारी** : चुमाउकेदिमा और बोको साइट पर सिविल कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अगरतला, पूर्वी सियांग, सेरछिप और उमसियांग में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) या तो लगभग पूरे हो चुके हैं या निर्माण के उन्नत चरणों में हैं।
- **मशीनरी स्थापना और कमीशनिंग** : स्यूडोस्टेम चुमाउकेदिमा और बोको स्थलों पर प्रसंस्करण मशीनें स्थापित कर दी गई हैं और पूरी तरह से काम कर रही हैं। अन्य स्थानों - अगरतला, पूर्वी सियांग, सेरछिप और उमसियांग - के लिए उपकरण चालू होने और खरीद प्रक्रिया के अधीन हैं और जल्द ही स्थापित कर दिए जाएंगे।
- **विविध मूल्य संवर्धन** : प्रत्येक स्थान क्षेत्रीय क्षमता के आधार पर विशेष इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है - **कागज निर्माण**, बेकरी और शाकाहारी चमड़े से लेकर केले के रेशे के धागे के उत्पादन तक - जिससे आय के रास्ते और उत्पाद विविधता का विस्तार होता है।
- **कौशल विकास और सामुदायिक गतिशीलता** मार्च 2025 में, नेक्टर की ओर से प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास केंद्र (CTRD) ने ग्वालपाड़ा (असम) और निउलैंड (नागालैंड) में व्यापक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, ताकि किसानों और स्वयं सहायता समूहों को केले के छद्म तने से बने उत्पादों जैसे रेशे, कागज, जैव-उर्वरक और जैव-निम्नीकरणीय वस्तुओं से प्राप्त आय के अवसरों के बारे में जानकारी दी जा सके। CTRD और नेक्टर के विशेषज्ञों द्वारा समर्थित, 160 से अधिक प्रतिभागियों ने स्थिर खेती और CFC तकनीकों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये प्रयास स्थानीय कौशल निर्माण, पर्यावरण-उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास में सहायक हो रहे हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण** : री-भोई साइट स्थायित्व बढ़ाने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा समाधानों की खोज कर रही है।
- **स्थानीय साझेदारियाँ** : EDII और SFAC जैसी केंद्रीय एजेंसियों, MSRLS और HPDCAP जैसे राज्य संगठनों, और CSIR-NIIST और ICAR-NINFET जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी ने स्थलों की पहचान करने और सही तकनीकों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सहयोगों ने परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन और भविष्य के विस्तार को आसान बनाने में मदद की है।





चित्र: नागालैंड के चुमुओकेदिमा में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)

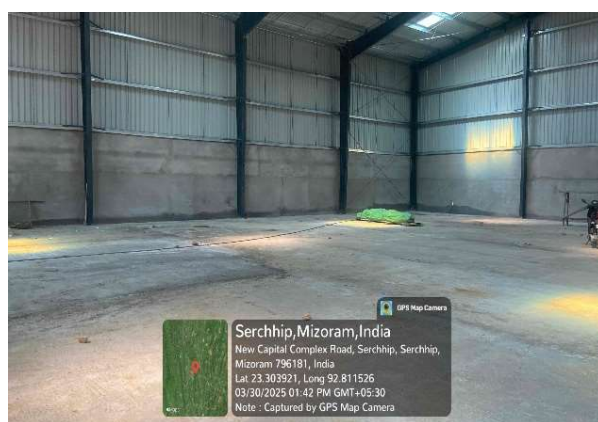


चित्र: बोको, असम में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)





चित्र: अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) का निर्माण



चित्र: सेरछिप, मिजोरम में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) का निर्माण



चित्र: अगरतला, त्रिपुरा में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) का निर्माण





चित्र: री भोई, मेघालय में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) का निर्माण

### सीएफसी में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और मशीनरी परिनियोजित प्रक्रिया

पीएम- डिवाइन परियोजना के कार्यान्वयन चरण के एक भाग के रूप में, केले के छद्मते के प्रसंस्करण उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला को सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) में, विशेष रूप से बोको (असम) और चुमौकेदिमा (नागालैंड) में, सफलतापूर्वक स्थापित और चालू किया गया। प्रक्रिया प्रवाह में केले के छद्मते के कोर का उपयोग करके रेशा निष्कर्षण, रस पाचन और बेकरी उत्पादन जैसे मुख्य कार्य शामिल थे। प्रत्येक इकाई की कार्यक्षमता का परीक्षण किया गया है और प्रशिक्षण एवं उत्पादन के लिए अनुकूलित किया गया है। निम्नलिखित चित्र रेशा निष्कर्षक, रस पाचक और बेकरी प्रणाली सहित विभिन्न इकाइयों की स्थापना, परीक्षण और वास्तविक संचालन को दर्शाते हैं।



चित्र : उपकरण स्थापना और प्रसंस्करण परीक्षणों का दृश्य दस्तावेजीकरण

## क्षमता निर्माण और कौशल विकास

पीएम- डिवाइन आजीविका सुधार परियोजना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, नेक्टर ने पूर्वोत्तर राज्यों में लक्षित किसान जागरूकता और कौशल विकास पहलों के माध्यम से क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दी है। 12 मार्च 2025 को समर्पित किसान जागरूकता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। केले के छद्म तने की मूल्य श्रृंखला क्षमता के बारे में समुदायों को जागरूक करने हेतु 17 मार्च 2025 को ग्वालपाड़ा ज़िले (असम) और 17 मार्च 2025 को निउलैंड ज़िले (नागालैंड) में एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। हमारी प्रशिक्षण साझेदार एजेंसी सीटीआरडी के कृषि अधिकारियों और खाद्य प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य था:

- केले की खेती के लिए स्थिर कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- मूल्यवर्धित केले के छद्म तने उत्पादों से उत्पन्न आर्थिक अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- किसानों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को फाइबर निष्कर्षण, उर्वरक उत्पादन, हस्तनिर्मित कागज और जैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों की प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षित करना।

दोनों कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों सहित विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के 160 से अधिक किसानों और एसएचजी प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।

प्रशिक्षण में प्रमुख चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया - जैसे मृदा क्षरण और रोपण सामग्री की कमी - जिससे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण पौधों की खरीद, उद्यमिता मार्गदर्शन, बाजार संपर्क सुविधा में निरंतर समर्थन की आवश्यकता की जानकारी मिली।

### नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, पृष्ठ 3

## Farmers Mobilization & Awareness Programme under PM-Dev INE Scheme Held in Goalpara

**NE News Goalpara :** Pseudostem for A Farmers Mobilization and Awareness Program was held on 12th March 2025 at the Dhanubhanga Anchalik Unnayan Samiti Conference Hall in Rongjuli Tehsil, Goalpara district, Assam. "It was part of the PM-DevINE Scheme for the project 'A Value Chain on Utilization of Banana



sustainable livelihoods and rural entrepreneurship by encouraging the utilization of banana pseudostem for value addition such as banana fiber, liquid fertilizer, compost, paper, yarn, and vegan leather alternatives. The training was conducted by CTRD, with Ms. Nazneen Rafia Medhi, a food technology expert, who guided the participants on developing market-ready products such as banana fiber, bioenzymes, compost, and food-based innovations. This initiative is expected to boost rural entrepreneurship, reduce agricultural waste, and promote sustainable industrial development in Northeast India. (Press Release)

### असम पोस्ट, पृष्ठ 9

### द हिल्स टाइम्स, पृष्ठ 4

STATE & REGION 9

Farmers Mobilization & Awareness Programme under PM-DevINE scheme held

**Goalpara:** A Farmers Mobilization and Awareness Program was held on 12th March 2025 at the Dhanubhanga Anchalik Unnayan Samiti Conference Hall in Rongjuli Tehsil, Goalpara district, Assam. It was part of the PM-DevINE Scheme for the project "A Value Chain on Utilization of Banana Pseudostem for Value-Added Products" implemented by the North East Center for Technology Application and Reach (NECTAR), an autonomous body under the Department of Science and Technology, Government of India, headquartered at Shillong. The program is a part of the ongoing efforts to promote sustain-

able livelihoods and rural entrepreneurship by encouraging the utilization of banana pseudostem for value addition such as banana fiber, liquid fertilizer, compost, paper, yarn, and vegan leather alternatives. The training was conducted by CTRD, with Ms. Nazneen Rafia Medhi, a food technology expert, who guided the participants on developing market-ready products such as banana fiber, bioenzymes, compost, and food-based innovations. This initiative is expected to boost rural entrepreneurship, reduce agricultural waste, and promote sustainable industrial development in Northeast India.

NECTAR organises Farmers' Mobilization & Awareness Programme in Nagaland

ITL Bureau

**GUWAHATI, March 17:** North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), an autonomous institute under the department of science and technology (DST), with its headquarters in Shillong conducted a Farmers' Mobilization and Awareness Programme on March 17.

The programme was held in Nihoto Village of Dimapur district in Nagaland where representatives from eight villages participated. It was part of the PM-DevINE project "NECTAR livelihood Improvement project (Multi State) – A Value Chain on Utilization of Banana Pseudo Stem for Value-Added Products", which is being implemented by NECTAR. Under this scheme, NECTAR constructed a Common Facility Centre (CFC) in Kukidolong village, Chumukedima in Nagaland.

This project is focused on creating sustainable livelihoods and rural entrepreneurship by encouraging the utilization of Banana Pseudo-stem by converting it into various marketable products, like extraction of fibre from banana pseudo stem, preparing nonwoven fabrics, preparation of organic liquid nutrient using banana pseudo stem and various types of hand-made paper from banana fibre.



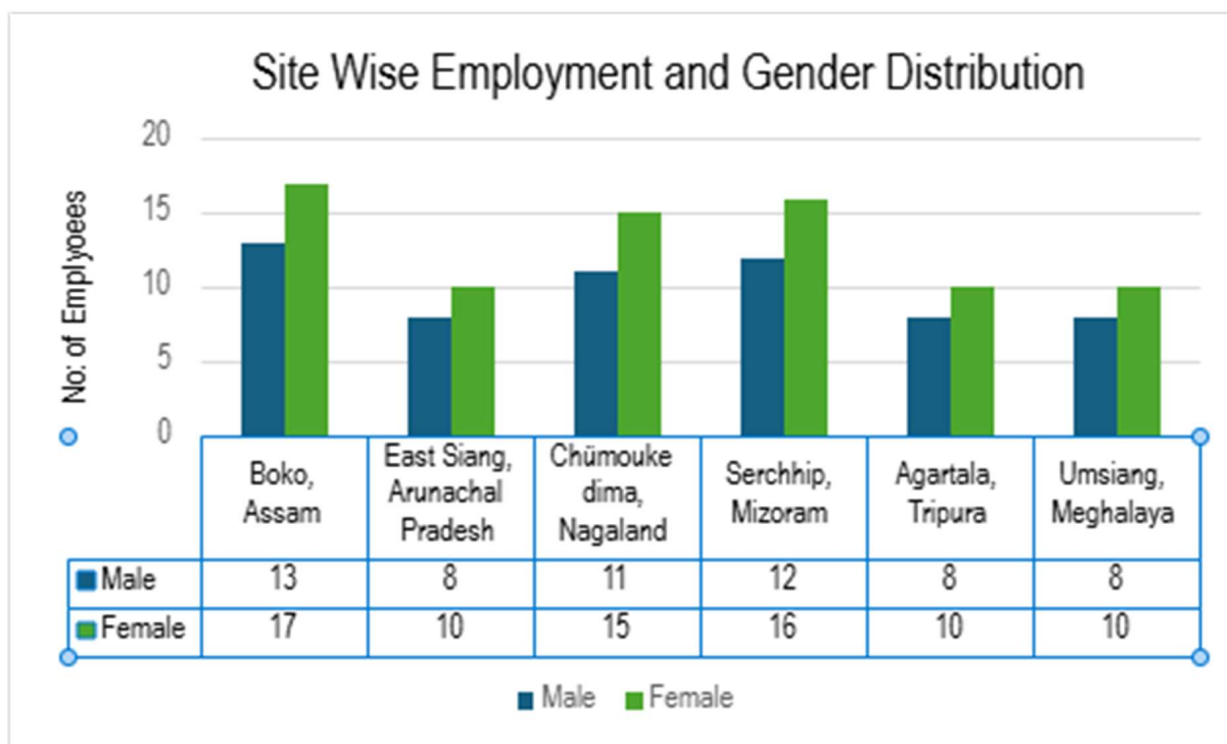
The training was conducted by Consortium for Training, Research and Development (CTRD), Guwahati with support from The Entrepreneurs' Associate, Kohima. The programme also received valuable insights from SDAO Pughoboto, Kitoho Michael Swu of the State Agriculture Department, and progressive farmer Kitoho S Rotkha and officials from NECTAR. They guided farmers on best agricultural practices and emphasised the importance of supporting the Common Facility Center (CFC) for the collective benefit of the community.

This initiative is expected to boost rural entrepreneurship, reduce agricultural waste, and promote sustainable industrial development in North East India.



### रोजगार और लिंग वितरण

इस परियोजना का एक प्रमुख परिणाम विविध जनसांख्यिकीय समूहों में रोजगार सृजन रहा है। प्रत्येक सीएफसी में एक मुख्य प्रसंस्करण इकाई और स्थानीय क्षमताओं के अनुरूप एक अतिरिक्त मूल्य-वर्धित इकाई है। इन केंद्रों में कार्यरत आधे से ज़्यादा कार्यबल महिलाएँ हैं, जो आजीविका के अवसरों और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाने में परियोजना की सफलता को दर्शाता है।



### प्रभाव और आगे की योजना

यह परियोजना पूर्वोत्तर में जैव-संसाधन-आधारित, समुदाय-संचालित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आत्मनिर्भर भारत, सतत कृषि और विकेंद्रीकृत उद्यमिता की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है। बुनियादी ढाँचे और उत्पादन के अलावा, यह पहल ग्रामीण आबादी के बीच नवाचार, कौशल-निर्माण और श्रम की गरिमा की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। आगामी वर्ष में, चरण II स्थलों पर स्थापनाओं को पूरा करने, मूल्यवर्धित उत्पादों के पोर्टफोलियो का विस्तार करने, बाज़ार संबंधों को मज़बूत करने और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए मॉडल को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। निरंतर संस्थागत समर्थन, बेहतर साझेदारी और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ, पीएम- देवाइन आजीविका सुधार परियोजना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में एकीकृत ग्रामीण विकास और हरित उद्यमिता का एक आदर्श बनने की ओर अग्रसर है।

## सौर निर्जलीकरण तकनीक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत को सशक्त बनाना

समावेशी विकास, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, नेक्टर ने मेघालय, नागालैंड और मिज़ोरम में 15 सौर निर्जलीकरण यंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं। यह पहल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में फसल-उपरांत होने वाले नुकसानों को कम करने, कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने और कृषक समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

### पहल का अवलोकन

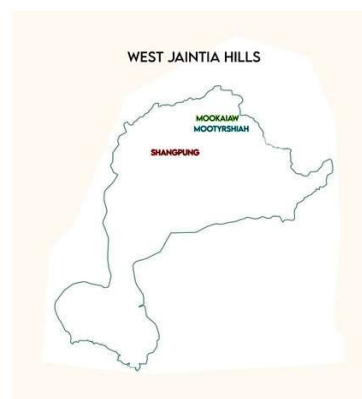
प्रत्येक सौर डिहाइड्रेटर की क्षमता 100 किलोग्राम प्रति बैच है, जिससे हल्दी, अदरक, किंग चिली मिर्च, मिर्च और बांस के अंकुर जैसी उच्च मूल्य वाली कृषि वस्तुओं का कुशल, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल प्रसंस्करण संभव हो पाता है। यह तकनीक उपज का अचल जीवन बढ़ाकर, पारंपरिक ईंधन-आधारित सुखाने के तरीकों पर निर्भरता कम करके और मूल्यवर्धित उत्पादों के माध्यम से बाजार से जुड़ाव को सुगम बनाकर किसानों की मदद करती है।



### परियोजना स्थल एवं लाभार्थी समूह

#### 1. मेघालय - पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला

अपनी अनुकूल जलवायु और जीवंत कृषक समुदायों की विशेषता वाला पश्चिम जयंतिया हिल्स क्षेत्र हल्दी की खेती का केंद्र बनकर उभरा है। मूतिरशिया, शांगपुंग, मोकायाव और नोंसदेर जैसे गाँवों में सौर ड्रायर स्थापित होने से, इस पहल का सहकारी समितियों, उत्पादक समूहों और ग्राम संगठनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है।



#### 2. नागालैंड - वोखा जिला

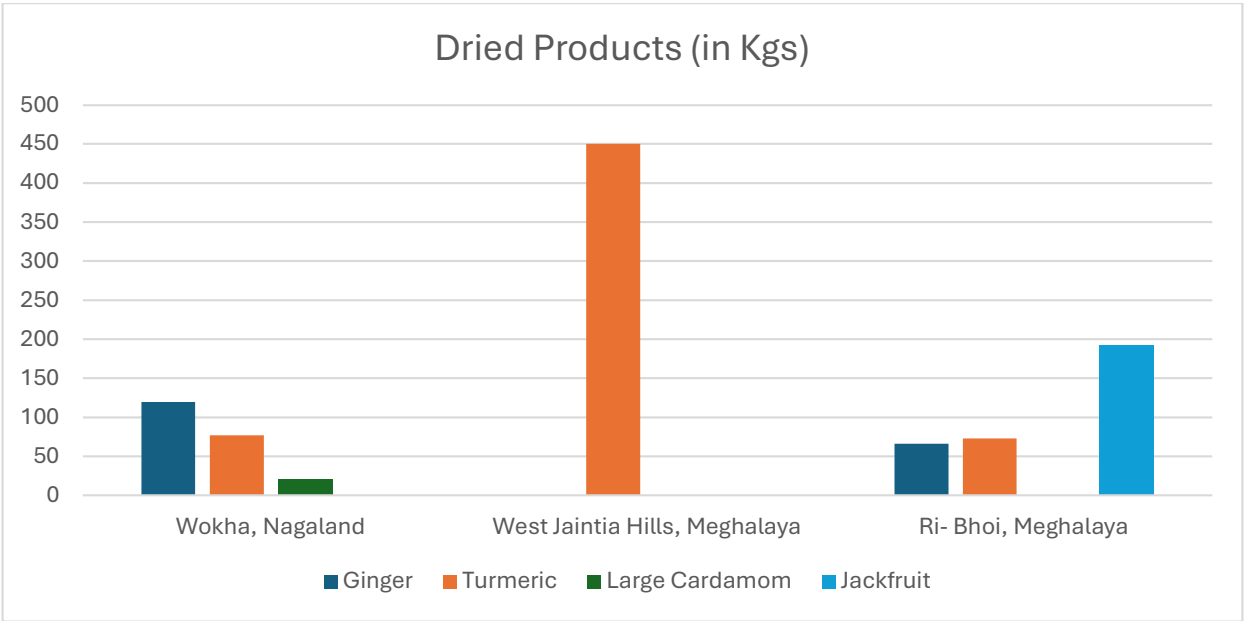
राज्य के मध्य-पश्चिमी भाग में स्थित, वोखा जिला लोथा समुदाय का निवास स्थान है और अदरक, हल्दी और मिर्च की किस्मों के प्रसंस्करण के लिए एक प्रमुख स्थान बन गया है। यह पहल बागती कस्बे और पेरेन कितेउजांग गाँव में लागू की गई है, जिससे दो किसान उत्पादक कंपनियों (FPC) को लाभ हुआ है।



#### 3. मिज़ोरम - ख्वाज़ावल जिला



मिज़ोरम का एक नव-स्थापित ज़िला, ख्वाज़ावल, एक परियोजना स्थल के रूप में कार्य करता है जहाँ बांस के अंकुर—इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण पाक और आर्थिक फसल—को सौर निर्जलीकरण यंत्रों का उपयोग करके संसाधित किया जाता है। यह सुविधा वर्तमान में सात व्यक्तिगत किसानों को लाभान्वित कर रही है, जिससे बेहतर कटाई-पश्चात प्रबंधन और आय विविधीकरण में योगदान मिल रहा है।

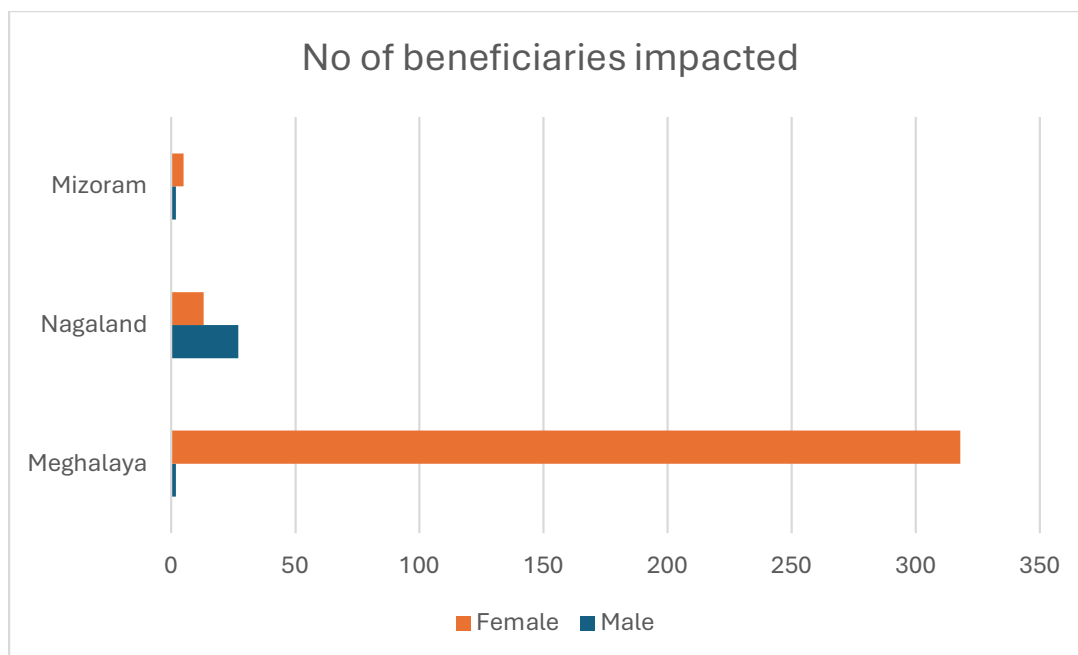




चित्र: सौर निर्जलीकरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुखाए गए उत्पाद



चित्र: निर्जलित उत्पादों का उत्पादन और पैकेजिंग





इन सौर निर्जलीकरण यंत्रों का उपयोग स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों, जैसे हल्दी, अदरक और किंग मिर्च, को सुखाने के लिए किया जा रहा है, जो अपने औषधीय और पाक गुणों के लिए जाने जाते हैं। सौर सुखाने की तकनीक अपनाने से न केवल इन उत्पादों की पोषण सामग्री और गुणवत्ता बरकरार रहती है, बल्कि कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान में भी उल्लेखनीय कमी आती है।



## नेक्टर द्वारा भू-स्थानिक मानचित्रण और ड्रोन गतिविधियाँ

### • डीजीसीए-अनुमोदित रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) के रूप में नेक्टर

नेक्टर (उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र) को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) के रूप में मान्यता दी गई है। आरपीटीओ रणनीतिक रूप से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बोको, असम में स्थित है, जो इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहले समर्पित ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रों में से एक बनाता है। इस पहल का उद्देश्य प्रमाणित ड्रोन पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में यूएवी संचालन की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए एक कुशल कार्यबल विकसित करना है।

नेक्टर का आरपीटीओ उत्तर पूर्व में प्रमाणित यूएवी पायलटों का एक समूह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे की निगरानी और पर्यावरण संरक्षण में ड्रोन परिनियोजन की व्यापक क्षमता वाला क्षेत्र है। स्थानीयकृत, किफायती और सुलभ ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान करके, आरपीटीओ न केवल युवाओं को नौकरी के लिए तैयार तकनीकी कौशल से सशक्त बना रहा है, बल्कि एक जिम्मेदार और सुरक्षा-अनुपालक ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का भी समर्थन कर रहा है।

बोको में नेक्टर आरपीटीओ (RPTO) की उपस्थिति ने दूरदराज और वंचित क्षेत्रों के छात्रों और पेशेवरों के लिए महानगरीय केंद्रों की यात्रा किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली ड्रोन शिक्षा तक पहुंचने के अवसरों का काफी विस्तार किया है। यह पहल ड्रोन नियम 2021 और डिजिटल स्काई पहल के अंतर्गत एक आत्मनिर्भर ड्रोन उद्योग के निर्माण के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है, साथ ही कौशल भारत मिशन के उद्देश्यों का भी समर्थन करती है। नेक्टर अपने आरपीटीओ के माध्यम से ड्रोन पेशेवरों की अगली पीढ़ी को विकसित करने और यूएवी प्रौद्योगिकी और सेवाओं में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उभरने में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।





चित्र: सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, असम सरकार, डॉ. अरुण कुमार शर्मा, महानिदेशक, नेक्टर, विधायक - बोको विधान सभा क्षेत्र द्वारा नेक्टर आरपीटीओ का उद्घाटन और प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरण



चित्र: ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (आरपीसी) का पहला महिला बैच

- हाइब्रिड दृष्टिकोण का उपयोग करके मेघालय के लिए वन सर्वेक्षण और मानचित्रण

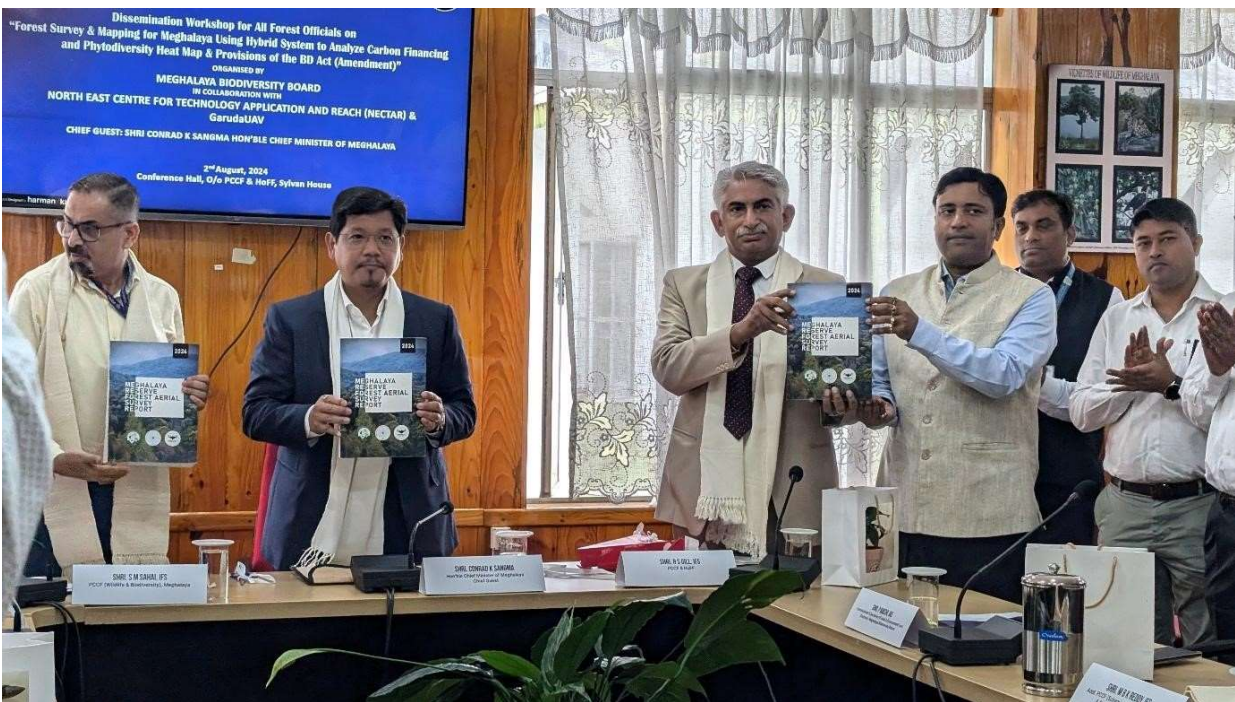
मेघालय जैव विविधता बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त, नेक्टर (उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र) ने "कार्बन वित्तपोषण और पादप-विविधता हीट मैप का विश्लेषण करने के लिए हाइब्रिड दृष्टिकोण (एयरबोर्न सेंसर/हेलीकॉप्टर/यूएवी) का उपयोग करते हुए मेघालय के लिए वन सर्वेक्षण और मानचित्रण" नामक एक अभिनव परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। इस अग्रणी पहल में हेलीकॉप्टर-माउंटेड LiDAR और हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर, ड्रोन-आधारित यूएवी इमेजिंग, और राज्य भर में उच्च-परिशुद्धता वाले वन डेटा उत्पाद प्रदान करने के लिए ऑन-ग्राउंड सत्यापन सहित एक बहु-प्लेटफॉर्म रणनीति अपनाई गई।

यह परियोजना मेघालय के 29 आरक्षित वनों के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन स्थानिक डेटा तैयार करने पर केंद्रित थी। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग और LiDAR डेटा का उपयोग करते हुए, इस परियोजना ने 400 से अधिक वृक्ष प्रजातियों को सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किया, वन स्वास्थ्य का आकलन किया और महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्रों की पहचान की। बाघमारा, तुरा पीक और नोंगखिल्लेम जैसे



आरक्षित वन जैव विविधता से समृद्ध और उच्च बायोमास वाले क्षेत्रों के रूप में उभरे, जबकि क्षरण दर्शाने वाले कुछ क्षेत्रों को पुनर्स्थापन के लिए चिह्नित किया गया। डेटा ने आग-प्रवण और मानव-बाधित क्षेत्रों का पता लगाने में भी मदद की, जिससे वन नियोजन और प्रबंधन में सहायता मिली। इसने एक व्यापक पादप-विविधता हीट मैप भी तैयार किया, जिसमें उच्च प्रजाति समृद्धि और स्थानिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। ये उपलब्धियां REDD+, स्वैच्छिक कार्बन बाजार और अन्य पारिस्थितिकी सेवा मूल्यांकन मॉडल जैसे तंत्रों के अंतर्गत राज्य के लिए कार्बन वित्तपोषण के अवसरों को सक्षम करने में सहायक हैं।

इस परियोजना का औपचारिक शुभारंभ शिलांग में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में किया गया, जिसका उद्घाटन मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जहां अंतिम रिपोर्ट जारी की गई। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह परियोजना विशेष जलवायु कार्रवाई क्षेत्र (एससीएजेड) विकसित करने तथा प्रकृति आधारित समाधान, कार्बन व्यापार और पुनर्योजी वन नीतियों के माध्यम से राजस्व स्रोतों को खोलने के लिए आधारशिला होगी।



चित्र: मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा, वन प्रमुख और पीसीसीएफ जेकेएस गिल, आईएफएस, डॉ. अरुण कुमार शर्मा, नेक्टर के महानिदेशक और मेघालय जैव विविधता बोर्ड के आयुक्त और श्री पी. बख्शी, सचिव, आईएएस द्वारा परियोजना की रिपोर्ट का लोकार्पण

- वन निगरानी और वन्यजीव निगरानी के लिए एयरोस्टैटिक ड्रोन

निगरानी और पर्यावरण निगरानी के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की दिशा में एक अग्रणी कदम के रूप में, नेक्टर (उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र) ने भारत के प्रथम एयरोस्टैटिक ड्रोन के विकास और प्रदर्शन का समर्थन किया है, जिसे एयरबोटिक्स टेक्नोलॉजीज के सहयोग से प्रतिरूपित और विकसित किया गया है। यह पहल नवाचार, स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के रणनीतिक अभिसरण का प्रतिनिधित्व करती है—विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक और सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप।

एयरोस्टैटिक ड्रोन एक संकर मानवरहित हवाई प्लेटफॉर्म है जो न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ लंबी अवधि की उड़ान बनाए रखने के लिए एयरोस्टैटिक लिफ्ट (उछाल गैस) और वायुगतिकीय नियंत्रण सतहों, दोनों का उपयोग करता है। पारंपरिक यूएवी के विपरीत,

जिन्हें निरंतर प्रणोदन की आवश्यकता होती है, यह प्लेटफॉर्म 4 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकता है, जिससे निरंतर, ध्वनिरहित निगरानी संभव होती है—जो वन्यजीव निगरानी, वन निगरानी और सीमा क्षेत्र गश्त के लिए एक आवश्यक विशेषता है। यह नवोन्मेषी ड्रोन प्रणाली कई मॉड्यूलर पेलोड से सुसज्जित है, जिनमें थर्मल और ऑप्टिकल कैमरे, दूरसंचार रिले, आपदा निगरानी सेंसर और एंटीड्रोन डिटेक्शन सिस्टम शामिल हैं। इसका लगभग मूक संचालन, कम रडार दृश्यता और उच्च सहनशक्ति इसे अवैध शिकार विरोधी अभियानों, वन अग्नि-प्रवण क्षेत्रों की निगरानी और पूर्वोत्तर के चुनौतीपूर्ण और दुर्गम इलाकों में सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील अनुप्रयोगों के लिए असाधारण रूप से उपयुक्त बनाती है।

नेक्टर ने तकनीकी सत्यापन, क्षेत्र-परीक्षण के अवसर और अंतर-एजेंसी संपर्क प्रदान करके इस नवाचार को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत एक संस्थान के रूप में, पूर्वोत्तर राज्यों में उपयुक्त और अग्रणी प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए नेक्टर का अधिदेश इस ड्रोन प्रणाली के सफल प्रदर्शन और परिनियोजित योजना के पीछे प्रेरक शक्ति रहा है। यह पहल भारत सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देती है जो सस्ती, अनुकूलनीय और भारतीय परिस्थितियों के लिए क्षेत्र-परीक्षणित हैं। इस परियोजना के माध्यम से, नेक्टर न केवल ड्रोन क्षेत्र में भारत की तकनीकी संप्रभुता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि जलवायु लचीलापन, जैव विविधता संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सार्थक योगदान दे रहा है - जिसमें कम सेवा प्राप्त उत्तर पूर्वी राज्यों पर एक सशक्त क्षेत्रीय फोकस सम्मिलित है।

एयरोस्टेटिक ड्रोन परियोजना ने गृह मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और अर्धसैनिक बलों सहित अनेक हितधारकों के बीच रुचि उत्पन्न की है, तथा आने वाले वर्षों में इसे बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किया जाएगा। नेक्टर डेवलपर्स, अंतिम उपयोगकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना जारी रखता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि यह परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी उन समुदायों और क्षेत्रों तक पहुंचे, जिन्हें इसकी अत्यधिक आवश्यकता है।



चित्र: शिलांग के मलकी वन क्षेत्र में एयरोस्टेटिक ड्रोन का प्रदर्शन, महानिदेशक नेक्टर, पूर्वी खासी हिल्स के डीएफओ, सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों की उपस्थिति में



## स्वामित्व (SVAMITVA) पहल के अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण

स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक से गाँवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन जैसी आधुनिक भू-स्थानिक तकनीकों का उपयोग करके गाँवों में आबादी भूमि का सीमांकन करना है, जिससे सटीक भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार हो सकें। यह पहल ग्रामीण शासन को मजबूत करने, संपत्ति विवादों को कम करने और ग्रामीण संपत्ति धारकों को अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करके औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बनाने के सरकार के व्यापक लक्ष्य का समर्थन करती है। बेहतर नियोजन, राजस्व संग्रह और पारदर्शी शासन की सुविधा प्रदान करके, स्वामित्व "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

भारत के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में भू-स्थानिक नियोजन का समर्थन करने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, नेक्टर ने अरुणाचल प्रदेश के शि-योमी और निचली दिबांग घाटी जिलों के 70 गाँवों में ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण सफलतापूर्वक किए। राष्ट्रीय भू-स्थानिक विकास कार्यक्रमों के तहत बड़े पैमाने पर मानचित्रण को समर्थन देने के अपने अधिदेश के तहत, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने नेक्टर को यह परियोजना सौंपी थी। सर्वेक्षण का उद्देश्य उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले स्थानिक डेटासेट तैयार करना था, जिसमें ऑर्थोमोज़ेक मानचित्र, डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) और 3D भू-भाग मॉडल शामिल थे, ताकि इन रणनीतिक और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, बुनियादी ढाँचे की योजना, आपदा जोखिम मूल्यांकन और संसाधन प्रबंधन में सहायता मिल सके। इस मिशन के दौरान NECTAR की टीम ने कई कठिन चुनौतियों—खराब सड़क संपर्क, प्रतिकूल मौसम की स्थिति और सीमा की निकटता से जुड़ी सुरक्षा संवेदनशीलताओं—को पार करते हुए सफलतापूर्वक क्षेत्रीय अभियानों को अंजाम दिया। विस्तृत योजना, कुशल कर्मियों की तैनाती और ड्रोन तकनीक के अनुकूल उपयोग ने कठिन इलाकों और सीमित परिचालन अवधि में उच्च-सटीक सर्वेक्षणों को पूरा करना संभव बनाया। यह पहल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अत्याधुनिक ड्रोन-आधारित भू-स्थानिक समाधान प्रदान करने में NECTAR की क्षमता को रेखांकित करती है और पूर्वोत्तर में प्रौद्योगिकी-आधारित विकास के एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में इसकी भूमिका को प्रदर्शित करती है। साक्ष्य-आधारित योजना और शासन को समर्थन देने के लिए तैयार किए गए डेटा उत्पादों और मानचित्रों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग और स्थानीय प्रशासनिक निकायों के साथ साझा किया जा रहा है।



चित्र: अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले और शियोमी जिले के सुदूर गाँव में ड्रोन सर्वेक्षण गतिविधियाँ

- पूर्वोत्तर में वैज्ञानिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक क्लस्टरों का मानचित्रण

इस पहल का नेतृत्व नेक्टर के जियोमैटिक्स प्रभाग द्वारा किया जा रहा है, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैज्ञानिक और जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्नत क्षेत्र-स्तरीय हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला का संचालन कर रहा है। इस पहल के एक भाग के रूप में, चयनित जैविक कृषि समूहों में आईओटी-आधारित कृषि-मौसम संबंधी सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर मृदा नमी, वायु तापमान, आर्द्रता, वर्षा, सौर विकिरण और पत्ती नमी जैसे प्रमुख पर्यावरणीय मापदंडों पर वास्तविक समय डेटा एकत्र करते हैं। डेटा को दृश्यीकरण और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रेषित किया जाता है, जिससे किसानों और कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को सिंचाई समय-सारिणी, रोग निवारण और कुशल संसाधन उपयोग से संबंधित सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

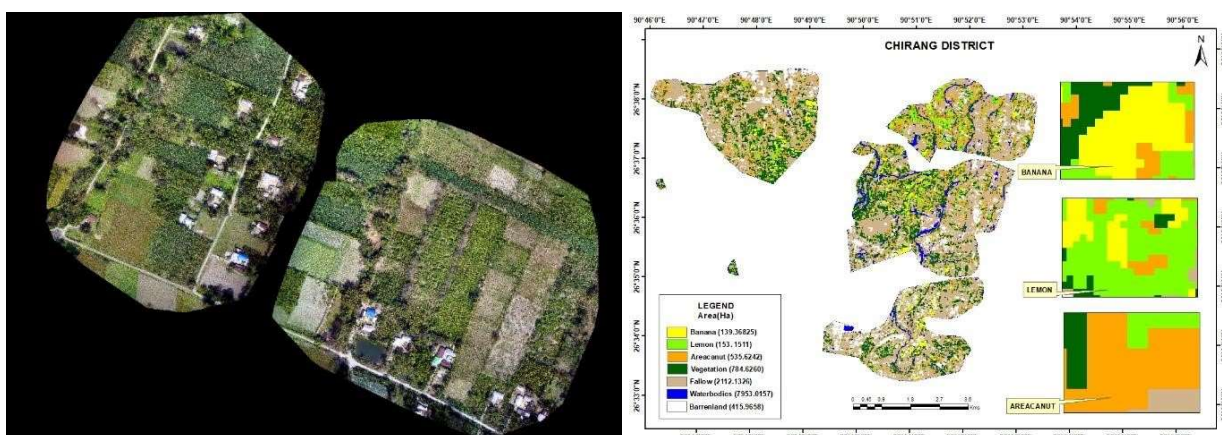
फसल प्रदर्शन की निरंतर और सटीक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक फसल मौसम के दौरान दो बार ड्रोन आधारित सर्वेक्षण किए जाते हैं - एक बार वनस्पतिक अवस्था के दौरान और दूसरी बार कटाई-पूर्व अवस्था में। इन सर्वेक्षणों में उच्च-रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरें प्राप्त करने एनडीवीआई (सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सचकांक) जैसे वनस्पति सचकांकों का आकलन



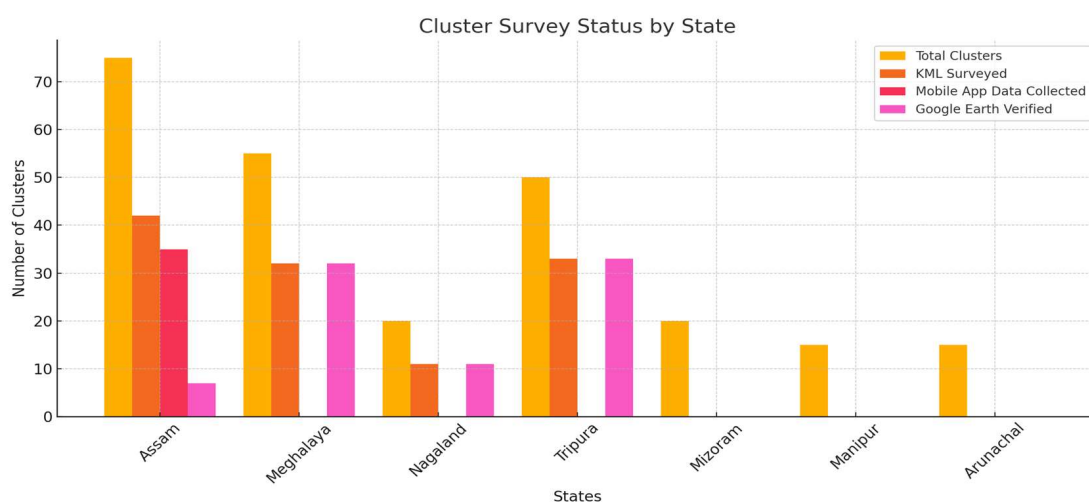
करने और फसल तनाव, कीट संक्रमण या पोषक तत्वों की कमी के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने के लिए मल्टीस्पेक्ट्रल और आरजीबी सेंसर दोनों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, ड्रोन डेटा को ऑर्थोमोजेक मानचित्र, डिजिटल सतह मॉडल और फसल की गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार करने के लिए संसाधित किया जाता है, जिनका उपयोग स्थानीय सलाह जारी करने और खेत-स्तरीय हस्तक्षेपों को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है।

परियोजना का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक केएमएल-आधारित जीपीएस सर्वेक्षणों का उपयोग करके क्षेत्र सीमा का सीमांकन करना है। व्यक्तिगत कृषि भूखंडों का सटीक मानचित्रण बेहतर फसल नियोजन में मदद करता है, जैविक प्रथाओं की निगरानी को सुगम बनाता है, तथा जैविक प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में सहायता करता है। ये स्थानिक डेटासेट भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, डिजिटल कृषि और लक्षित नीति कार्यान्वयन से संबंधित सरकारी प्रयासों में भी सहायक होते हैं।

वास्तविक समय सेंसर नेटवर्क, यूएवी-आधारित फसल विश्लेषण और क्षेत्र-स्तरीय भू-स्थानिक मानचित्रण को संयोजित करके, नेक्टर की पहल वैज्ञानिक, डेटा-संचालित और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार कृषि पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा दे रही है। यह परियोजना न केवल किसानों की उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाती है, बल्कि जैविक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करती है, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा में योगदान देती है।

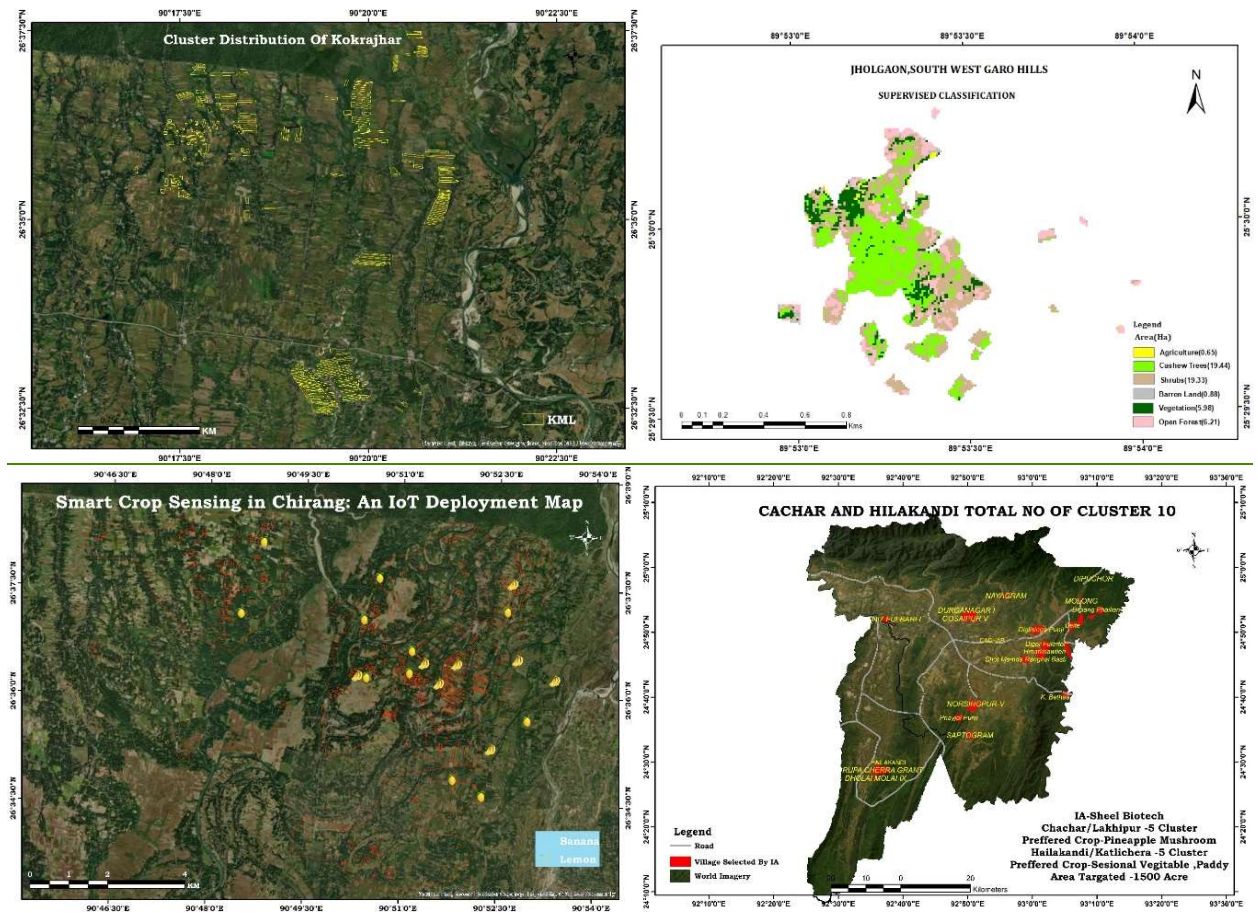


चित्र: असम के चिरांग जिले में क्लस्टर में विभिन्न फसलों के वर्गीकरण को दर्शाता मानचित्र



चित्र: राज्यवार केएमएल क्लस्टर सर्वेक्षण





चित्र: विभिन्न क्लस्टरों पर ड्रोन इमेजरी और फसल मानचित्रण

## नेक्टर मुख्यालय, शिलांग में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रयोगशाला

शिक्षा में बदलाव लाने और छात्रों को 21वीं सदी के आवश्यक कौशल से लैस करने के रणनीतिक प्रयास के अंतर्गत, उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (नेक्टर) ने स्मार्ट ग्राम आंदोलन (SVM) और क्यूरियोसिटी जिम के सहयोग से मेघालय के शिलांग स्थित नेक्टर मुख्यालय में मुक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रयोगशाला की स्थापना की है।

यह अत्याधुनिक सुविधा क्षेत्र में अनुभवात्मक शिक्षा के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है, जो कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, कोडिंग और 3डी प्रिंटिंग जैसे महत्वपूर्ण स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करती है।



### ● उद्देश्य और दृष्टि

मुक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली स्टेम शिक्षा और वास्तविक दुनिया की तकनीकी जानकारी प्रदान करके शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच सीखने की खाई को पाटना है। पारंपरिक कक्षा-आधारित शिक्षण के विपरीत, प्रयोगशाला व्यावहारिक, परियोजना-आधारित और पूछताछ-आधारित शिक्षण पर जोर देती है।

कक्षा 5 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए खुली और सोमवार से शुक्रवार तक संचालित होने वाली यह प्रयोगशाला, प्रशिक्षित स्टेम शिक्षकों और संगठनों की देखरेख में विद्यार्थियों को विविध स्टेम अनुखंडों से जुड़ने के लिए संरचित अवसर प्रदान करती है।

समस्या-समाधान, आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मकता-उन्मुख शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके, इस पहल का उद्देश्य जिज्ञासा जगाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और छात्रों को स्टेम क्षेत्रों में भविष्य के करियर के लिए तैयार करना है।

### ● विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रयोगशाला अनुखंड : जिज्ञासा और रचनात्मकता को प्रज्वलित करना

मुक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रयोगशाला न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ाने के लिए, बल्कि छात्रों में जिज्ञासा जगाने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए भी डिज़ाइन की गई है। प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमुख अनुखंड में शामिल हैं:

- रोबोटिक्स: छात्र रोबोट का डिजाइन, निर्माण और प्रोग्रामिंग करते हैं, तथा स्वचालन, सेंसर और कोडिंग तर्क के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स: सर्किट, सेंसर और आर्दुइनो जैसे माइक्रोकंट्रोलर्स के साथ प्रायोगिक (हैंड्स-ऑन) सीखना।
- 3डी प्रिंटिंग: छात्र डिजिटल मॉडल डिजाइन करते हैं और उन्हें 3डी प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से जीवंत बनाते हैं।
- डिजाइन थिंकिंग: छात्र अपने समुदायों में वास्तविक दुनिया की समस्याओं की पहचान करते हैं और नवीन समाधानों को डिजाइन करने के लिए स्टैम उपकरणों का उपयोग करते हैं।



➤ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित का बाह्य विस्तार : प्रयोगशाला से परे पहुँच का विस्तार

यह समझते हुए कि सभी छात्र व्यक्तिगत रूप से नेक्टर प्रयोगशाला का दौरा नहीं कर सकते, स्टैम संगठकों ने एक कार्यक्रम व्यापक विद्यालय का बाह्य विस्तार लागू किया।

मुख्य विशेषताएँ:

- पंजीकृत छात्रों की संख्या - 43 छात्र
- दौरा किए गए स्कूलों की संख्या - 110 स्कूलों का दौरा किया गया
- छात्रों की परियोजनाओं की संख्या: - 24 (17 पूर्ण परियोजनाएँ और 7 जारी)
- कुल STEM सत्रों के घंटे - STEM सत्रों के 91 घंटे
- बनाए गए छात्रों की प्रोफाइल की संख्या - 11 छात्रों की प्रोफाइल

यह सक्रिय, बहु-चैनल बाह्य विस्तार रणनीति, स्टैम शिक्षा को अधिक से अधिक छात्रों तक, विशेष रूप से दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों तक सुलभ बनाने के लिए नेक्टर की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।



➤ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रयोगशाला मशीन प्रदर्शनी-सह-प्रतियोगिता

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रयोगशाला प्रयोगशाला के गतिविधि कैलेंडर का एक मुख्य आकर्षण STEM मशीन प्रदर्शनी-सह-प्रतियोगिता थी, जो 16 मई 2025 को आयोजित की गई थी। स्मार्ट ग्राम आंदोलन (SVM) द्वारा समर्थित और समन्वित, इस कार्यक्रम ने छात्रों को अपनी रचनात्मकता और STEM नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक जीवंत मंच प्रदान किया। छात्रों ने रोबोटिक मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर 3डी-मुद्रित प्रोटोटाइप और कोडिंग समाधान तक की विस्तृत परियोजनाएं प्रस्तुत कीं। प्रदर्शनी ने सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दिया तथा छात्रों, शिक्षकों और आगंतुकों को विचारों का आदान-प्रदान करने और नवाचार का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित किया।







## राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण चारे हेतु बीज उत्पादन में सहायता

**कार्यान्वयन संस्थाएं :-** केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू), इम्फाल, मणिपुर के सहयोग से उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (नेक्टर)

### परिचय

मणिपुर में गुणवत्तापूर्ण चारे हेतु बीज उत्पादन की पहल, जिसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल और नेक्टर द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया गया है, पशुधन उत्पादकता में सुधार और स्थिर कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। यह परियोजना पशु स्वास्थ्य में सुधार, दूध उत्पादन में वृद्धि, तथा क्षेत्र में डेयरी किसानों की आजीविका को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण उच्च गुणवत्ता वाले चारा बीज और रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने पर केंद्रित है।

### उद्देश्य

- गुणवत्तापूर्ण चारा बीज और रोपण सामग्री उपलब्ध कराना।
- पशुधन उत्पादन बढ़ाने के लिए फार्म पर चारा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना।
- उन्नत चारा उत्पादन पद्धतियों को अपनाने के डेयरी किसानों की क्षमता बढ़ाना।
- किसानों की आजीविका पर हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन करना।



### 1. फसल चयन और रोपण

खरीफ मौसम के दौरान, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए चारा फसलों की विविधतापूर्ण खेती की गई:

- चारा मक्का (Var. J-1006) / Fodder Maize (Var. J-1006)
- लोबिया (Var. CL-367) / Cowpea (Var. CL-367)
- बाजरा नेपियर संकर किस्में: को-4, को-5, सुपर नेपियर और रेड नेपियर / Bajra Napier Hybrid Varieties: Co-4, Co-5, Super Napier, and Red Napier

बीज उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना से निम्नलिखित रोपण सामग्री प्राप्त की गई:



- मक्का का चारा 600 किलोग्राम आधार बीज / 600 kg foundation seed of fodder maize
- लोबिया का 100 किलोग्राम प्रजनक बीज / 100 kg breeder seed of cowpea
- नेपियर हाइब्रिड की 50,000 पर्चियां / 50,000 slips of Napier Hybrid

## 2. किसान चयन और वितरण

किसानों का चयन भूमि की उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं, मिट्टी की उपयुक्तता और चारा बीज उत्पादन में उनकी रुचि के आधार पर किया गया। कुल 30 किसानों ने भाग लिया।



## 3. क्षमता निर्माण

प्रशिक्षण गतिविधियाँ:

सभी चयनित किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन में उनकी क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य था:

- प्रत्येक फसल के लिए कृषि पद्धतियाँ
- कटाई के बाद प्रसंस्करण और हैंडलिंग
- बीज प्रमाणीकरण के लिए गुणवत्ता मानक

सीएयू (CAU) के वैज्ञानिकों और परियोजना कर्मचारियों द्वारा नियमित क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से तकनीकी सहायता, फसल के प्रदर्शन की निगरानी, और प्रसंस्करण एवं भंडारण पर मार्गदर्शन सुनिश्चित किया गया।



#### 4. बीज क्रय एवं गुणवत्ता आश्वासन

समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुरूप:

- काटे गए बीजों और स्लिप की भौतिक शुद्धता और अंकुरण जांच की गई।
- आगे की प्रक्रिया और वितरण के लिए केवल 80% से अधिक अंकुरण वाले बीज ही खरीदे गए।
- गुणवत्ता की अखंडता बनाए रखने के लिए निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री किसानों को वापस कर दी गई।



#### 5. प्राप्त प्रगति

- 30 किसान चारा मक्का, लोबिया और बाजरा नेपियर हाइब्रिड किस्मों के उत्पादन में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।



- मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के किसानों को लगभग 4 लाख नेपियर स्लिप और कटिंग तथा पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित मक्का और लोबिया के बीज वितरित किए गए।
- इस परियोजना से निम्नलिखित उत्पादन की उम्मीद है:
  - 60 क्विंटल प्रमाणित मक्का बीज (किस्म J-1006)
  - 0 2 लाख नेपियर स्लिप/कटिंग
  - 0 5 क्विंटल आधारभूत लोबिया बीज (किस्म CL-367)

यह पहल पूर्वोत्तर में गुणवत्तापूर्ण चारा बीज और रोपण सामग्री की उपलब्धता में सुधार, पशुधन उत्पादकता में वृद्धि, तथा बेहतर प्रथाओं एवं बाजार पहुँच के माध्यम से डेयरी किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्षमता निर्माण, कठोर गुणवत्ता नियंत्रण और सहभागी दृष्टिकोण को एकीकृत करके, यह परियोजना सतत पशुधन विकास का समर्थन करती है और किसानों की आजीविका में सार्थक योगदान देती है।





## असम में धुबरी के अशारीकंडी में पारंपरिक टेराकोटा और मिट्टी के बर्तनों के व्यवसाय की स्थिरता में सुधार



गदाधर नदी का तट सबसे बड़ा केंद्र है जहाँ पारंपरिक टेराकोटा और मिट्टी के बर्तनों की शिल्पकला साथ-साथ फलती-फूलती है। अशारीकंडी के नाम से जाना जाने वाला यह आश्रय स्थल भारत के असम के धुबरी जिले के डेबिटोला विकास खंड में स्थित है। अशारीकंडी में एक अनूठी टेराकोटा शैली है, जो समय के साथ बरकरार रही है। इसकी प्रसिद्धि टेराकोटा और मिट्टी के बर्तनों को गढ़ने की सदियों पुरानी तकनीक से है। इस शिल्प का सार हिरामती नामक मिट्टी में निहित है, 130 से अधिक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले परिवारों और लगभग 500 कारीगरों का घर है जिन्होंने पीढ़ियों से प्राचीन शिल्प को संरक्षित रखा है। गाँव की सांस्कृतिक समृद्धि के बावजूद, समुदाय को पुरानी मैनुअल प्रक्रियाओं, पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों की प्रक्रिया की स्वास्थ्य-जोखिम प्रकृति के कारण बढ़ती चुनौतियों का सामना

करना पड़ा, परियोजना के अंतर्गत ओंकारेश्वर स्वयं सहायता समूह के कुल 16 कारीगरों को सीधे तौर पर प्रशिक्षित किया गया, जबकि लगभग 500 लाभार्थियों को साझा बुनियादी ढांचे और केंद्रीकृत प्रसंस्करण और फायरिंग सेवाओं सहित बेहतर व्यापार मॉडल से लाभ मिलेगा।

पायलट परियोजना की शुरुआती सफलता के बाद, नेक्टर ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के SEED प्रभाग को एक विस्तारित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस परियोजना का उद्देश्य उन्नत मशीनीकृत प्रक्रियाओं का सत्यापन और कार्यान्वयन, कौशल संवर्धन, रोजगार सृजन और क्षेत्र में आय वृद्धि एवं पर्यटन को बढ़ावा देना था।

SEED पहल के तहत, तीन सामान्य सुविधा केंद्रों (CFC) का निर्माण किया गया और उन्हें पारंपरिक शारीरिक श्रम के स्थान पर आधुनिक मशीनों से सुसज्जित किया गया। शुरू की गई तकनीकों में डी-एयरिंग पगमिल, लकड़ी से चलने वाले भट्टे, हाइड्रोलिक प्रेस टाइल बनाने वाली मशीनें, और जिगर-जॉली और डिस्सिंटिग्रेटर जैसे अन्य उपकरण शामिल थे। इन हस्तक्षेपों ने हानिकारक आसन और धुआँ छोड़ने वाले भट्टों को हटाकर कार्य स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार किया, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। प्रौद्योगिकी सहयोगी संस्था टेक्नोलॉजी एंड एक्शन फॉर रूरल एडवांसमेंट (TARA) ने कारीगरों को नई मशीनों और बेहतर उत्पादन तकनीकों से परिचित कराने के लिए बुनियादी और उन्नत दोनों तरह के प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इस पहल के तहत, 10 कारीगरों को खुर्जा स्थित महामना सिरेमिक संस्थान में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया और 53 कारीगरों को पगमिल और भट्टों सहित नई मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण से कारीगरों को उत्पादकता बढ़ाने, उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने और शारीरिक तनाव कम करने में मदद मिली, जिससे उनकी कार्यकुशलता और आय में वृद्धि हुई।



विपणन सहायता एक अन्य अभिन्न अंग थी। अशारीकंडी मिट्टी के बर्तनों के उत्पादों की एक सूची तैयार की गई और ऑनलाइन बिक्री को सुगम बनाने के लिए मार्केट मिर्ची के माध्यम से ई-मार्केटिंग प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सांस्कृतिक प्रदर्शनियों के माध्यम से कारीगरों को अवसर प्रदान किए गए, साथ ही बाजार की माँग के अनुसार नई उत्पाद श्रृंखलाएँ विकसित की गईं। असम राज्य

कार्यालयों को मिट्टी के कुल्हड़ों की आपूर्ति एक प्रमुख विपणन सफलता थी। इसके अतिरिक्त, स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने और इस कला को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने के लिए एक क *शिल्प मेला* भी आयोजित किया गया।



कच्चे माल की उपयुक्तता को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए, स्थानीय मिट्टी के नमूनों का तकनीकी मृदा परीक्षण किया गया। टेराकोटा उत्पादन में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता और स्थिरता की पुष्टि के लिए यह कदम आवश्यक था। निष्कर्षतः, आधुनिक मशीनरी के एकीकरण, क्षमता निर्माण और रणनीतिक बाज़ार सहभागिता ने अशारीकंडी टेराकोटा समुदाय का कार्याकल्प कर दिया है। इस पहल ने न केवल कारीगरों की आजीविका में सुधार किया, बल्कि आस-पास के गाँवों को भी इसी तरह की प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया। हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तनों की बढ़ती वैश्विक माँग और निरंतर संस्थागत समर्थन के साथ, अशारीकंडी पारंपरिक शिल्प पुनरुद्धार और ग्रामीण उद्यमिता के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में उभर रहा है।



## नेक्टर द्वारा समर्थित परियोजनाएँ

मेघालय में फसल की क्षति को कम करने के लिए सौर ऊर्जा चालित शीत भंडारण इकाई की स्थापना हेतु पायलट परियोजना

- **कार्यान्वयनकर्ता:** मेघालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (एमएनआईडीए), मेघालय सरकार
- **परियोजना के उद्देश्य :** मेघालय के पूर्वी खासी पर्वतीय जिले और दक्षिण पश्चिम गारो पर्वतीय जिले में सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज की स्थापना
- **लाभार्थी :**
  - **प्रत्यक्ष:** पूर्वी खासी पर्वतीय जिले में नोंगक्रेम युवा विकास एजेंसी; दक्षिण पश्चिम गारो पर्वतीय जिले में ग्रेटर बेबेलपारा के किसान संघ ।
  - **अप्रत्यक्ष :** आसपास के गांवों के स्थानीय किसान
- **महत्वपूर्ण उपलब्धि :**
  - स्थानों पर दो -दो मीट्रिक टन सौर ऊर्जा भंडारण इकाइयाँ स्थापित की गईं
  - प्राथमिक लाभार्थियों को इकाइयाँ सौंपने का कार्य पूर्ण हुआ
  - दोनों स्थानों पर 200 से अधिक किसानों को द्वितीयक लाभार्थियों के रूप में लाभान्वित होने की संभावना है





### अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्थिर कृषि हेतु माइक्रोबियल कंसोर्टियम द्वारा सहायता प्राप्त जैविक खाद

- **कार्यान्वितकर्ता** : मिजोरम विज्ञान केंद्र, मिजोरम सरकार
- **परियोजना के उद्देश्य** : की स्थापना 2 आसपास के गांवों से जैविक कचरे से खाद बनाने के लिए आइजोल जिले में जैविक अपशिष्ट खाद सुविधा की संख्या
- **लाभार्थी** : श्रीमती रोहलपुइया और 8 अन्य लोग
- **महत्वपूर्ण उपलब्धि** :
  - सेसांग गांव, आइजोल में पहली इकाई का उद्घाटन नेक्टर के महानिदेशक द्वारा मिजोरम सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।
  - 4000 किलोग्राम जैविक खाद का पहला बैच सफलतापूर्वक उत्पादित किया गया और "मावितेई खाद" ब्रांड नाम के तहत विपणन किया गया।
  - लाभार्थियों और स्थानीय किसानों को मृदा जैविक कार्बन परीक्षण किट वितरित किए गए तथा जैविक अपशिष्ट संग्रहण के लिए आस-पास के स्थानीय भागीदारों को अपशिष्ट संग्रहण डिब्बे भी वितरित किए गए।





सरथेबारी गांव में बेल मेटल वस्तुओं के प्रशिक्षण सह उत्पादन इकाई का विकास ।

- कार्यान्वयनकर्ता: कृषि एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी स्कूल , आईआईटी गुवाहाटी
- परियोजना के उद्देश्य : मशीनरी के माध्यम से मानकीकृत प्रक्रिया का उपयोग करके बेल मेटल वस्तुओं का उत्पादन
- महत्वपूर्ण उपलब्धि :
  - नवीनतम कार्य उपकरणों और उपकरणों के साथ कार्य केंद्र की स्थापना पूर्ण की गई
  - आईआईटी परिसर में कारीगरों की प्रशिक्षण कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया
  - प्रतिदिन 50-55 बेल मेटल वस्तुओं की उत्पादन क्षमता
  - लाभार्थियों में श्री अनूप भुयान, स्थानीय बेल मेटल कारीगर और 5 अन्य शामिल हैं







### परियोजना: पर्यावरण-अनुकूल पेपर से बने कपों का बड़े पैमाने पर उत्पादन

- **कार्यान्वयन एजेंसी:** मेसर्स बॉनटन एक्सटेंशन
- **मालिक:** श्री क्रिस्टोफर लालफाकावमा
- **स्थान:** आइजोल, मिज़ोरम

इस परियोजना का उद्देश्य पूरे मिज़ोरम में पर्यावरण-अनुकूल पेपर कप का उत्पादन और वितरण करके प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को कम करना है। ₹25 लाख की बजटीय सहायता से, इस इकाई ने एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक पैकेजिंग को स्थिर विकल्पों से बदलने के लिए विश्वसनीय व्यावसायिक संचालन स्थापित किया है।

यह पहल उत्पादन, वितरण और संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से आइजोल और उसके आसपास के लोगों के लिए महत्वपूर्ण आजीविका के अवसर उत्पन्न करके स्थानीय आर्थिक विकास में भी योगदान देती है।







### परियोजना: अदरक और हल्दी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

- **जगह:** सुखंजन, कार्बी आंगलोंग जिला, असम

यह प्रसंस्करण इकाई स्थानीय रूप से उगाए गए जैविक अदरक और हल्दी के मूल्य संवर्धन पर केंद्रित है। यह इकाई प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से 2-4 श्रमिकों को रोजगार देती है, और कार्बी आंगलोंग जिले के लगभग 800 किसानों को लाभान्वित करती है जो जैविक कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। आज तक, इस इकाई ने लगभग 3-4 टन प्रसंस्कृत अदरक और हल्दी का उत्पादन किया है, जिससे किसानों की बाजार तक पहुँच बढ़ी है और क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है।



### परियोजना: सुपारी के आवरणों से जैव-निम्नीकरणीय कटलरी का निर्माण

- **जगह:** नलबाड़ी, असम

नलबाड़ी में एक युवा महिला उद्यमी द्वारा संचालित यह पहल स्थानीय स्तर पर प्राप्त सुपारी के आवरणों से बायोडिग्रेडेबल कटलरी बनाने के लिए समर्पित है। यह इकाई प्लास्टिक कटलरी के स्थिर विकल्पों को बढ़ावा देती है और साथ ही दो व्यक्तियों को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर प्रदान करती है। पारंपरिक सामग्रियों को पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन तकनीकों के साथ जोड़कर, यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आजीविका सृजन में योगदान देती है।



### परियोजना: मधुमक्खी पालन और एकीकृत कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम

- **जगह:** दलापचंद, पाकयोंग जिला, सिक्किम
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** सिक्किम राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, सिक्किम सरकार
- **सहयोगी एजेंसी:** NECTAR, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार

मधुमक्खी पालन और एकीकृत खेती पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह कार्यक्रम स्थानीय किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों से सशक्त बनाने और मधुमक्खी पालन को एक व्यवहार्य पूरक आजीविका के रूप में बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

महिलाओं और युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी सहित कुल 25 से अधिक स्थानीय किसानों को आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। व्यावहारिक कार्यान्वयन में सहायता के लिए, प्रत्येक प्रतिभागी को एक मधुमक्खी बॉक्स और बस्तियाँ प्रदान की गईं ताकि वे अपना स्वयं का मधुमक्खी पालन उद्यम स्थापित कर सकें।

यह पहल सिक्किम में ग्रामीण विकास, पारिस्थितिक संरक्षण और कृषक समुदायों के लिए आय विविधीकरण के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।





### परियोजना: स्वदेशी और आधुनिक हथकरघा तकनीकों का उपयोग करके रेशम उत्पाद विकास

इस परियोजना का उद्देश्य गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए पारंपरिक शिल्प कौशल को आधुनिक उपकरणों के साथ मिलाकर रेशम उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है।

#### आज तक की प्रगति:

- 11 अर्ध-स्वचालित फ्लाई शटल लूम खरीदे और स्थापित किए गए हैं।
- 1 वार्षिक ड्रम खरीदा और स्थापित किया गया है।
- 5 बुनकरों को करघा संचालन तथा 2 व्यक्तियों को वार्षिक ड्रम के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

पूर्ण कार्यान्वयन के बाद, इस परियोजना से लगभग 22 श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय कौशल विकास और आजीविका सृजन में योगदान मिलेगा।







### परियोजना: मशरूम स्पॉन उत्पादन इकाई

- **स्थान:** खगड़पुर, बोंगाईगांव जिला, असम
- **परियोजना की स्थिति:** पूर्ण
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** मेसर्स डायमंड मशरूम फार्म

बोंगाईगांव जिले में मशरूम की खेती में गुणवत्तापूर्ण स्पॉन की अनुपलब्धता एक बड़ी बाधा रही है, जहाँ लगभग 200 परिवार सर्दियों के दौरान ऑयस्टर मशरूम उगाते हैं और सालाना 15-16 क्विंटल स्पॉन की आवश्यकता होती है। पहले, स्थानीय उत्पादन की कमी के कारण किसानों को दूसरे जिलों और राज्यों के आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता था।

यह परियोजना मेसर्स डायमंड मशरूम फार्म को गुणवत्तापूर्ण स्पॉन उत्पादन हेतु सभी आवश्यक मशीनरी और उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय सहायता के साथ स्वीकृत की गई थी। इस इकाई ने जनवरी 2024 में परिचालन शुरू किया और अब यह प्रति माह लगभग 800 किलोग्राम स्पॉन का उत्पादन कर रही है, जिसकी आपूर्ति न केवल बोंगाईगांव, बल्कि अन्य जिलों और राज्यों को भी की जा रही है।



### परियोजना: ग्रीनहाउस एक्वापोनिक्स इकाई

- **जगह:** लैटकोर, शिलांग, मेघालय
- **परियोजना की स्थिति:** जारी
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** मेसर्स एंजेलग्रीन कृषि उत्पाद

पारंपरिक कृषि के नकारात्मक प्रभावों और घटती कृषि भूमि को देखते हुए, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता लगातार गंभीर चिंताएँ बनती जा रही हैं। एक्वापोनिक्स एक अत्यधिक उत्पादक, संसाधन-कुशल और जैविक विकल्प प्रदान करता है जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है।

नेक्टर ने शिलांग में एक ग्रीनहाउस एक्वापोनिक्स इकाई स्थापित करने के लिए सहयोग दिया है। इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, कीट-मुक्त, अत्यधिक पौष्टिक सब्जियाँ और मछलियाँ पैदा होंगी। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और युवाओं में टिकाऊ, वैकल्पिक कृषि विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।





## प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण

## नेक्टर- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की एक प्रमुख योजना है जिसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, (नेक्टर) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल विकास पहलों के लिए एक प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में उभरी है। इसका व्यापक दृष्टिकोण विभिन्न राज्यों में समावेशी और प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत नेक्टर की भूमिका की मुख्य विशेषताएं:

- क्षेत्रीय फोकस: मेघालय, असम, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में संचालित।
- सहयोगात्मक दृष्टिकोण: उपयुक्त सहयोगी साझेदारों और प्रशिक्षण केंद्रों की पहचान करना और उनके साथ साझेदारी करना।
- समावेशी गतिशीलता: समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को शामिल करना।
- आजीविका संवर्धन: कौशल संवर्धन के माध्यम से स्थायी आजीविका सृजन में योगदान।
- प्रशिक्षण और प्रमाणन

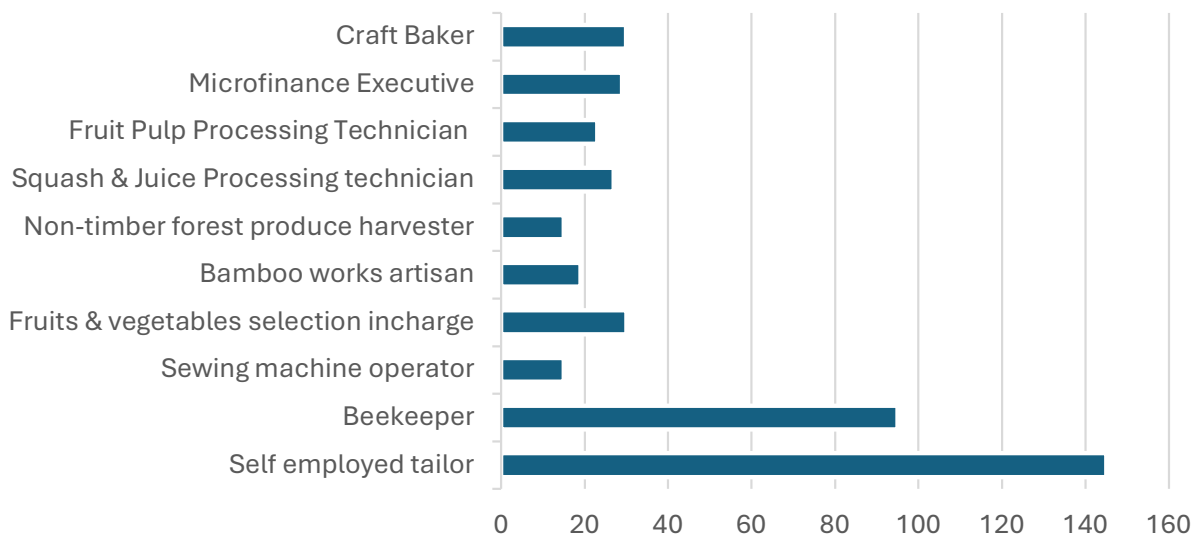
नेक्टर द्वारा एसटीटी कार्यान्वयन की मुख्य विशेषताएं (2024-25):

- एनएसक्यूएफ(NSQF)-संरचित पाठ्यक्रम: पाठ्यक्रम 300 से 600 घंटे तक के होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार डिजाइन किया गया है।
- उम्मीदवार लक्ष्य और क्षेत्र कवरेज:
  - 2023-24 के दौरान लगभग 1,300 उम्मीदवारों को लक्षित किया गया।
  - भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के सहयोग से आयोजित किया गया।
  - प्रशिक्षण में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और पारंपरिक कौशल जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया।

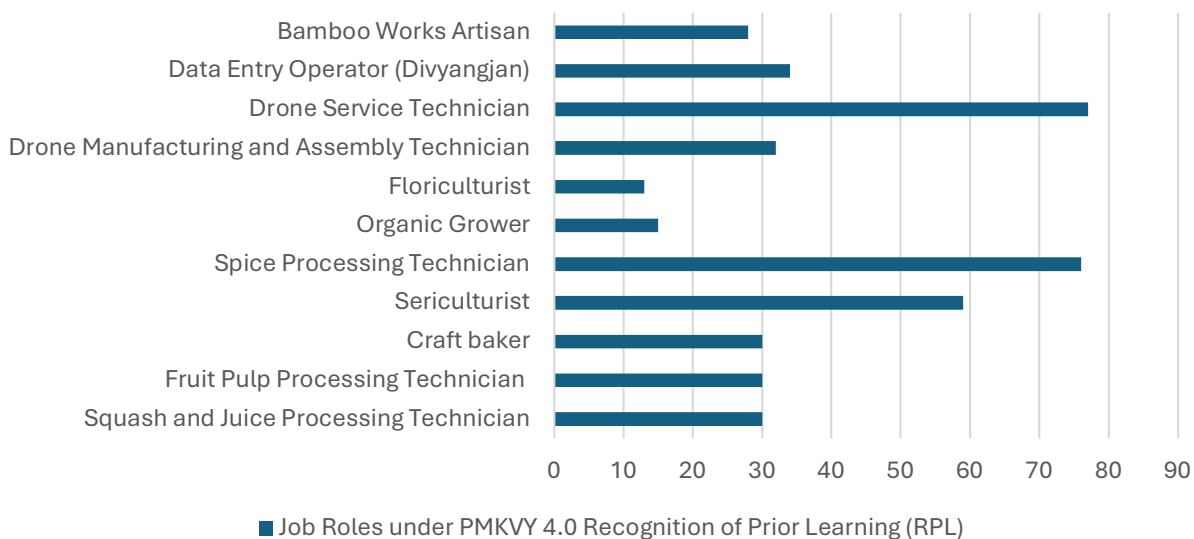
नेक्टर द्वारा पूर्व शिक्षण कार्यान्वयन की मान्यता की मुख्य विशेषताएं:

- उम्मीदवार कवरेज:
  - आरपीएल घटक के अंतर्गत लगभग 2,450 उम्मीदवारों को लक्षित किया गया था।
  - इन क्षेत्रों में कृषि, हस्तशिल्प और अन्य पारंपरिक एवं उद्योग-प्रासंगिक क्षेत्र शामिल थे।
- कार्यान्वयन का तरीका:
  - 2023-24 में आयोजित आरपीएल शिविरों के माध्यम से 240 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।
  - 2024-25 के दौरान उद्योग परिसर में आरपीएल के तहत 2,210 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया, जिससे वास्तविक कार्य वातावरण में कौशल पहचान संभव हो सकी।

### पीएमकेवीवाई 4.0 लघु अवधि प्रशिक्षण के अंतर्गत नौकरी की भूमिकाएँ (मेघालय और मिजोरम)



### पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत नौकरी की भूमिकाएँ (मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड)

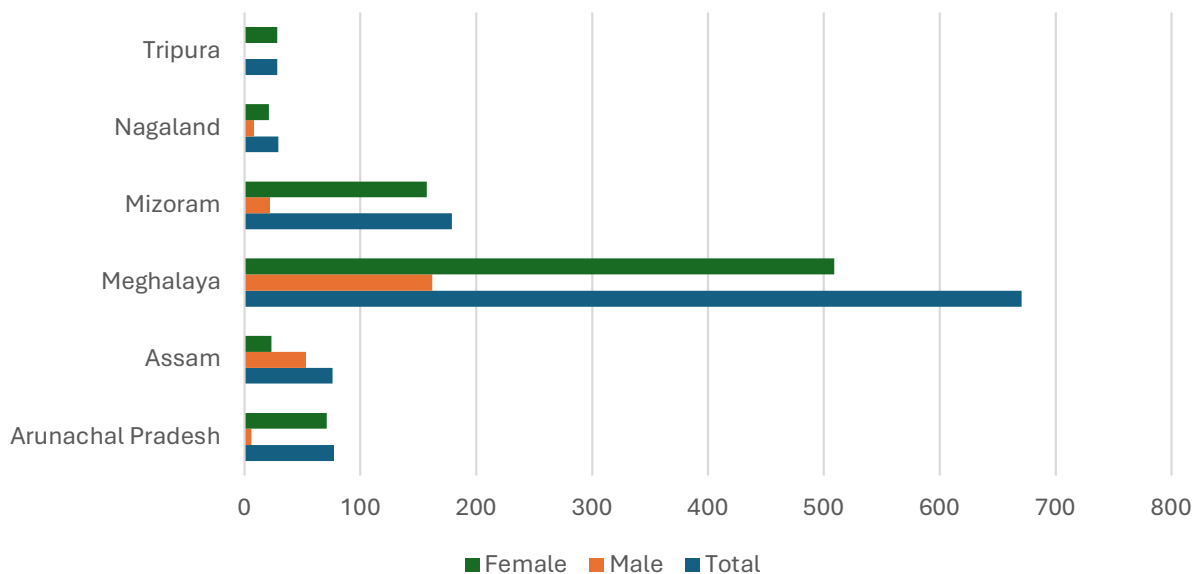




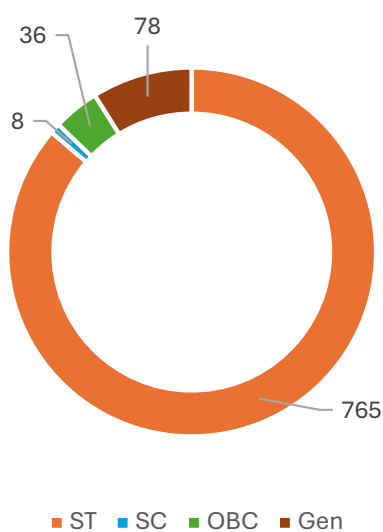


चित्र: विभिन्न नौकरी भूमिकाओं पर पीएमकेवीवाई अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) चित्र

## पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत लाभार्थी वितरण



## पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत लाभार्थियों का सामाजिक श्रेणी वितरण











चित्र: विभिन्न नौकरी भूमिकाओं पर पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल)

नेक्टर - बीसीडीआई, त्रिपुरा

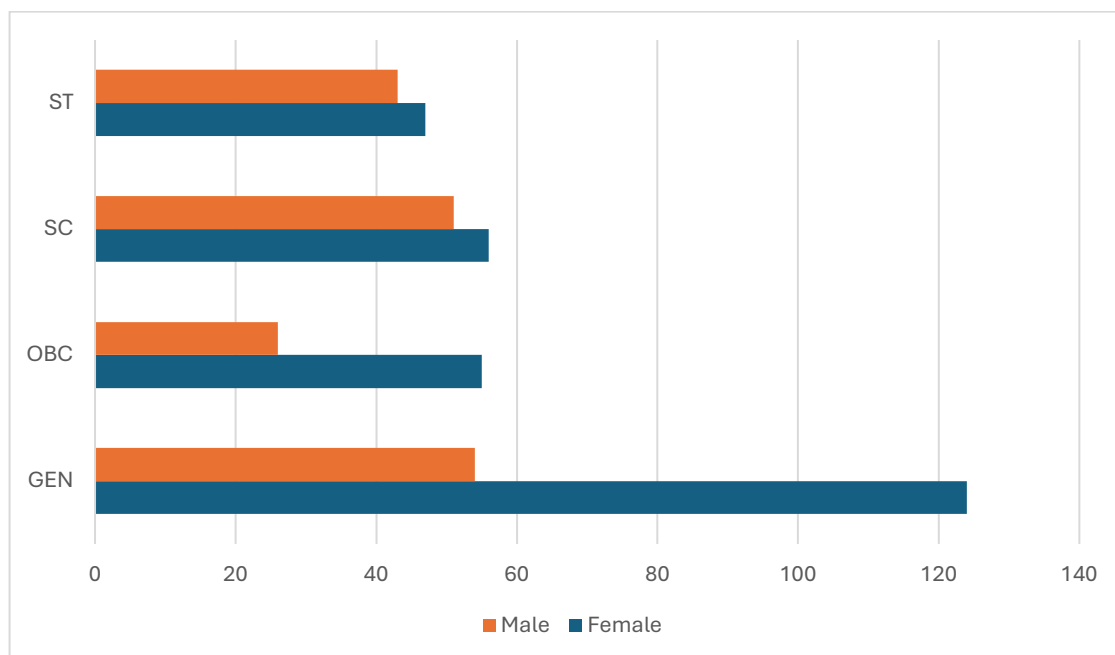
स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने के लिए, त्रिपुरा में 2024 और 2025 के बीच बांस पर केंद्रित क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इन पहलों को नेक्टर, त्रिपुरा बांस मिशन, इंडिया एक्जिम बैंक, त्रिपुरा जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ और भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम एस एम ई) जैसे संगठनों का समर्थन प्राप्त था। अगरतला स्थित बांस एवं बेंत विकास संस्थान (बी सी डी आई) इनमें से कई कार्यक्रमों का मुख्य स्थल रहा।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बांस प्रसंस्करण, उत्पाद विकास और डिज़ाइन नवाचार में व्यावहारिक कौशल प्रदान करना और साथ ही जलवायु परिवर्तन शमन में बांस की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। प्रतिभागियों में स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्प केंद्रों के सदस्य, बांस

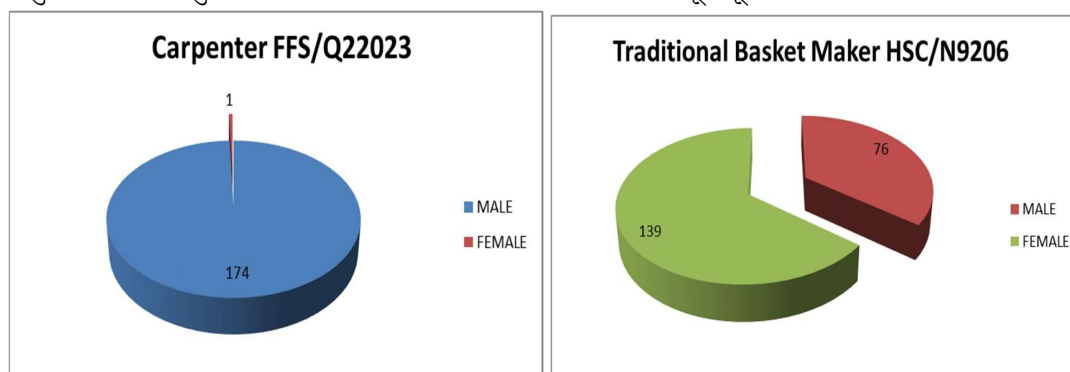
मिशन के अधिकारी और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षु भी शामिल थे, जो एक स्थायी संसाधन के रूप में बांस में स्थानीय और वैश्विक रुचि को दर्शाते हैं।

मुख्य बिन्दु :

- कुल आयोजित कार्यक्रम: 8 (दोहराए गए बैचों सहित)
- प्रशिक्षित कुल प्रतिभागी: 439 से अधिक लोग (अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित)
- प्रायोजक और साझेदार: नेक्टर, त्रिपुरा बांस मिशन, इंडिया एक्जिम बैंक, त्रिपुरा जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ, डीएसटीई
- प्रमुख स्थान: बीसीडीआई, अगरतला (प्राथमिक प्रशिक्षण स्थल)
- फोकस क्षेत्र: बांस उपयोगी उत्पाद, बोतल निर्माण, आभूषण डिजाइन, प्राथमिक प्रसंस्करण, जलवायु परिवर्तन शमन जागरूकता।



इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त, बीसीडीआई वर्तमान में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की पीएम विश्वकर्मा योजना (पीएमवीकेवाई) के तहत एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। इस पहल के तहत, बीसीडीआई बांस की टोकरी के निर्माण और बढ़ईगिरी जैसे पारंपरिक शिल्पों में निरंतर, उच्च-गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण विरासत कौशल को संरक्षित और बढ़ावा देने, कारीगरों की आजीविका में वृद्धि करने और क्षेत्र के सतत विकास में योगदान देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। व्यावहारिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करके, बीसीडीआई व्यक्तियों को सशक्त बनाने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और समुदाय के भीतर लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास में सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।







### भूस्थानिक प्रभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण

नेक्टर ने अपने भू-स्थानिक प्रभाग के माध्यम से उत्तर पूर्व में प्रौद्योगिकी क्षमता को मज़बूत करने के लिए विविध और प्रभावशाली प्रशिक्षण और जनसम्पर्क कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रारंभ की है, जो व्यावहारिक कौशल और उद्योग की तैयारी पर केंद्रित है। ये पहल



डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का प्रत्यक्ष समर्थन करती हैं, साथ ही वंचित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी प्रसार के नेक्टर के मिशन को भी पूरा करती हैं। अग्रणी प्रौद्योगिकियों को समझने और शैक्षणिक शिक्षा को उद्योग की ज़रूरतों से जोड़कर, नेक्टर के कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में बढ़ोत्तरी हेतु क्षेत्र की नवाचार क्षमता को उजागर करने में सहायता कर रहे हैं।

नेक्टर ने उत्तर पूर्व में सभी शैक्षणिक स्तरों के छात्रों के बीच ड्रोन प्रौद्योगिकी, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और एआई/एमएल को लोकप्रिय बनाने के लिए व्यापक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ साझेदारी में, नेक्टर ने ड्रोन असेंबली और सेवा तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया। 150 छात्रों ने यह प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिससे ड्रोन कंपनियों, सेवा फर्मों, स्टार्ट-अप्स और मानचित्रण और निरीक्षण सेवाओं में स्वरोजगार के लिए नौकरियों के द्वार खुल गए हैं।

- 1,000 छात्र शामिल हुए, जिसमें रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ड्रोन-आधारित डेटा अधिग्रहण और एआई/एमएल अनुप्रयोगों पर विशेषज्ञ वार्ता, लाइव प्रदर्शन और बातचीत शामिल थी।
- 250 स्कूली छात्रों ने ड्रोन तकनीक और यूएस क्षेत्र में करियर के रास्ते समझाने के लिए सरलीकृत मॉड्यूल का उपयोग करते हुए आउटरीच सत्रों में भाग लिया।
- 50 इंजीनियरिंग छात्रों को सीआईटी, कोकराझार में लाइव उड़ान सत्रों सहित तकनीकी ड्रोन घटकों, उड़ान संचालन और सुरक्षित एसओपी पर प्रशिक्षण दिया गया।
- असम डाउनटाउन विश्वविद्यालय, असम में 30 छात्रों ने भू-स्थानिक डेटा के बारे में सीखा
- कॉटन विश्वविद्यालय, प्राग्ज्योतिष कॉलेज, डिमोरिया कॉलेज और सेंट एंथोनी कॉलेज, शिलांग में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस पर 10 दिवसीय मोबाइल कैम्पस प्रशिक्षण, 80 छात्रों को लाभ पहुँचा रहा है, जो छात्रों को कृषि प्रौद्योगिकी, शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में करियर के लिए तैयार कर रहा है।













### नेक्टर द्वारा की गई विविध गतिविधियाँ एवं कार्यशालाएँ

नेक्टर द्वारा केंद्रीय बागवानी संस्थान, नागालैंड के प्रशिक्षुओं के लिए 12 से 14 जून, 2024 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह प्रदर्शन भ्रमण का आयोजन किया गया।



दिनांक 03 अगस्त, 2024 को मणिपुर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लाम्फेलपट, इम्फाल में नेक्टर के मणिपुर संपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया।



वाहोंग 90.0 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो परियोजना का मणिपुर के थौबल में उद्घाटन किया गया।



एनआईटी मेघालय और कॉटन विश्वविद्यालय में उद्यमिता के लिए प्लाज्मा प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला



दिनांक 14 अगस्त, 2024 को सेंट एंथोनी कॉलेज शिलांग के सहयोग से नेक्टर द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन किया गया।





डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के सहयोग से नेक्टर द्वारा 3 सितंबर, 2024 को डिजिटल परिवर्तन पर कार्यशाला आयोजित की गई।



दिनांक 17 और 18 सितंबर, 2024 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में "सामुदायिक रेडियो में लैंगिक समावेशन" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।





स्वच्छता ही सेवा 2024, विशेष अभियान के अंतर्गत नेक्टर द्वारा अनेक गतिविधियाँ की गई



माननीय संसदीय राजभाषा समिति की द्वितीय उप-समिति द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2024 को गुवाहाटी में नेक्टर कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया गया।





18 अक्टूबर, 2024 को उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (नेक्टर) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-अटारी) (जोन VI) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह और “पूर्वोत्तर भारत में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देने” के लिए मास्टर प्रशिक्षकों को स्मार्ट फोन वितरण



एसआईएल इंडिया 2024; महानिदेशक, माननीय सुश्री पिरेट हार्टमैन एस्टोनिया सरकार की क्षेत्रीय मामलों और कृषि मंत्री, एपीडा अध्यक्ष और नेक्टर के साथीगण



30.12.2024 को हिंदी कार्यशाला एवं हिंदी पखवाड़ा के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए



20.01.2025 को अन्ना विश्वविद्यालय के सहयोग से डाउनटाउन अस्पताल में नेक्टर "चिकित्सा उपकरणों के अंशांकन" पर कार्यशाला आयोजित की गई।



सेंट एडमंड्स कॉलेज, शिलांग में शिक्षकों के लिए **स्टैम** पर कार्यशाला आयोजित की





नेक्टर और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मणिपुर के बीच समझौते पर हस्ताक्षर



दिनांक 17 फरवरी 2025 को भारत टेक्स 2025 के दौरान नेक्टर और CSB- CMERTI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर



नेक्टर और भट्टदेव विश्वविद्यालय के बीच , असम 28.02.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर



श्रीमती पंकजा मुंडे और श्रीमती विनीता सिंघल महाराष्ट्र सरकार की प्रधान सचिव ने 18.2.2025 को बीसीडीआई त्रिपुरा में बांस पर जानकारी दी ।



सेसांग मिजोरम में जैविक अपशिष्ट खाद सुविधा का उद्घाटन, जिसमें लाभार्थियों को वसुंधरा जैविक कार्बन परीक्षण किट का वितरण भी शामिल है, नेक्टर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मिजोरम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों और कृषि विभाग, मिजोरम सरकार के बाहरी विशेषज्ञ सदस्य के साथ किया गया ।





13.3.2025 को माननीय श्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा उमसावली, मेघालय में शिलान्यास समारोह का उद्घाटन किया गया ।





2024 -2025 के दौरान अनेक समाचार पत्रों में नेक्टर की खबरों की झलक

7/11/24, 11:06 AM      Jongksha on air: Community radio station launched | Highland Post

About    Advertise    Privacy & Policy    Contact    f    t    e    Thursday, July 11, 2024

VISIT HAWPHOR    **Highland Post**    BODY, OF MEGHALAYA

SPORTS    WRITER'S COLUMN    LETTERS TO THE EDITOR

Home > Meghalaya > East Khasi Hills

### Jongksha on air: Community radio station launched

by HP News Service    March 16, 2024    in East Khasi Hills



SHARES    74    VIEWS    f    t    e    in    e

<https://highlandpost.com/jongksha-on-air-community-radio-station-launched/>    1/9

7/11/24, 12:53 PM      NECTAR office inaugurated in Mizoram to enhance tech advancements - NECTAR office inaugurated in Mizoram to enhance tech advancements

Northeast    India Today    Malayalam    Business Today    BT Bazaar    Aaj Tak    Lallantop    Bangla    GNTV    Reader's Digest

Search Here...

News / Mizoram / NECTAR office inaugurated in Mizoram to enhance tech advancements

### NECTAR office inaugurated in Mizoram to enhance tech advancements

Mizoram Liaison Office of North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR) was inaugurated within the premises of the office building of the Directorate of Science by Vanlaldina Fana, Commissioner & Secretary, Planning and Programme Implementation Department.

ADVERTISEMENT

Jun 13, 2024,    Updated Jun 13, 2024, 10:35 AM IST    Follow us:    e

Mizoram Liaison Office of North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR) was inaugurated within the premises of the office building of the Directorate of Science by Vanlaldina Fana, Commissioner & Secretary, Planning and Programme Implementation Department.

Vanlaldina Fana said that Science and Technology is the backbone for the development of Mizoram and the state needs more and more development in the field and hoped that the office would be a blessing for Mizoram in the field of the applications of science and technology.

Dr. Arun Kumar Sarma, Director General, NECTAR presided over the inauguration function and presented the works and projects of NECTAR.

Also Read: Mizoram CM Lalduhoma inaugurates renovated maternity ward at Aizawl Civil Hospital

North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR) is an autonomous society, set up under the Department of Science & Technology, Government of India in 2012 with its headquarters at Shillong, Meghalaya.

<https://www.indiatoday.in/mizoram/story/nectar-office-inaugurated-in-mizoram-to-enhance-tech-advancements-1027365-2024-06-13>    1/5

7/11/24, 11:10 AM      Assam: NECTAR launches drone pilot training center in North East India to address job needs - Assam: NECTAR launches drone pilot training center in North East India to address job needs

Northeast    India Today    Malayalam    Business Today    BT Bazaar    Aaj Tak    Lallantop    Bangla    GNTV    Reader's Digest

Search Here...

News / Assam / Assam: NECTAR launches drone pilot training center in North East India to address job needs

### Assam: NECTAR launches drone pilot training center in North East India to address job needs

NECTAR's initiative aims to bridge the gap between demand and supply by providing comprehensive drone operation training at Jawaharlal Nehru College, Boko, starting from May 8.

ADVERTISEMENT

India TodayNE    Apr 21, 2023,    Updated Apr 21, 2023, 7:23 PM IST    Follow us:    e

North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR) has taken a significant step towards addressing the demand for skilled drone pilots in India by launching a new employment opportunity for unemployed youth in the North East. With an estimated one million government and private jobs in need of skilled drone pilots, NECTAR's initiative aims to bridge the gap between demand and supply by providing comprehensive drone operation training at Jawaharlal Nehru College, Boko, starting from May 8.

Tapan Dutta, the Principal of JN College Boko, expressed his enthusiasm for the collaboration with NECTAR, stating that the drone technology training center at their college will offer professional training for aspiring drone pilots, leading to DGCA (Director General of Civil Aviation) approved certification. He highlighted the importance of drone technology as a crucial skill in the 21st century and the potential for employment opportunities in the field.

Somnath, a professional drone pilot and trainer from NECTAR, explained that earlier there were no guidelines for drones, but the DGCA introduced new guidelines in 2021, allowing anyone who has passed 10th grade to become a

<https://www.indiatodayne.in/assam/story/assam-nectar-launches-drone-pilot-training-center-in-north-east-india-to-address-job-needs-546557-2023-04-21>    1/3

# The Assam Post

THE ASSAM POST ■ GUWAHATI EDITION ■ SATURDAY, NOVEMBER 30, 2024

## Inauguration of demo farm lab by nectar at Karbi Anglong

**Etso Teron, Karbi Anglong:** On Tuesday, Demo Farm Lab and Training Center under Prime Minister's Development Initiative for North East Region (PM-DevINE) scheme, was officially inaugurated by Dr. Arun Kumar Sarma (Director General, NECTAR). On this day, an interaction was held with the farmers to mark the inauguration of this Demo Farm Lab. The programme laid focus on the importance of Demo Farm Lab and its role in organic agriculture with an interaction session with all the Master Trainers and Trainee Farmers aimed to equip the farmers with the knowledge and skills necessary to train others in organic farming practices. During the event Android mobile phone was distributed among the Master Trainers of five selected clusters of Karbi Anglong. Another highlight of the programme is live demonstration of soil testing kit – Vasundhara (a technology transferred from Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai to NECTAR) to our farmers for testing soil organic carbon content and its pH.





## Training on promotion of 'scientific organic agriculture'

July 23, 2024



Prof. Akali Sema, PVC, NU &amp; PE, STINER-TFC with resource persons and Master Trainers at NU: SAS, Medziphema Campus.

Science and Technology Intervention in North-Eastern Region-Technology Facilitation Centre (STINER-TFC), NU:SAS, Medziphema Campus in collaboration with North East Centre for Technology and Reach (NECTAR) conducted five-day Master Trainer's Training Programme to Promote Scientific Organic Agriculture in North-East India at STINER-TFC, NU: SAS, Medziphema campus from July 15 to 19, 2024.

In a press release by STINER-TFC, Project Incharge, Prof. Akali Sema informed that the training was conducted under the PM-DevINE scheme funded by the Ministry of DoNER. The training brought together 20 Master Trainers from four implementing agencies i.e., ICCOA, KVSS, Sheel Biotech and Access Development Service.

STINER-TFC, Project Incharge highlighted that the objective of the training was to demonstrate various bio pesticide use, application processes, and discussing the importance of bio-control agents in organic farming and create organic clusters in North-East.

STINER-TFC, Project Incharge said that Research Associate, NECTAR, Dr. Sumita Upadhyaya, highlighted the importance of farm and organic farm lab designs and management. Assistant professor, Living Bible College, Dr. Otto Awoni, College demonstrated live bio pesticides and discussed plant protection in sustainable agriculture, showcasing indigenous preparations of bio pesticide like Neemastra and Agniastra. NU:SAS, Medziphema campus, Prof. L. Tongpang Longkumer provided detailed insights on organic farming inputs, economic and social benefits, and application methods.

## NECTAR Launches Organic Agriculture Project In Arunachal Under PM-DevINE Scheme

Arunachal Pradesh, June 5, 2025



Share Facebook Twitter YouTube Instagram

224 0

East Kameng/West Kameng, June 5, 2025 – In a significant step towards advancing organic agriculture in Arunachal Pradesh, the North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), an autonomous body under the Department of Science and Technology, Government of India, has initiated key interventions under the project "Promoting Scientific Organic Agriculture in the North East Region."

Funded by the Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER) under the PM-DevINE scheme, the project is being implemented in 15 clusters across East Kameng and West Kameng districts.

The PM-DevINE Organic Scheme aims to create a robust organic farming ecosystem throughout the Northeastern states by focusing on farmer training and capacity building, facilitating organic certification, establishing demonstrative farm labs at the cluster level, developing community seed banks, and creating a digital architecture using modern technologies such as UAVs. This digital system will integrate key components such as farmers' details, yield, soil characteristics, and more for data-driven decision-making. It also emphasizes market linkage of organic produce through e-marketing platforms and dedicated organic outlets.

The scheme envisages the establishment of 250 organic-certified clusters, each guided by a Master Trainer and involving 100 trainee farmers. The overall goal is to train 25,000 farmers across the Northeast, ensuring their produce is certified and connected to viable markets. The state-wise distribution of these clusters is as follows: Assam (75), Meghalaya (55), Tripura (50), Mizoram (20), Nagaland (20), Manipur (15), and Arunachal Pradesh (15).

In Arunachal Pradesh, the project targets 1,500 farmers across 15 clusters. The focus areas include scientific capacity building, land certification under the Participatory Guarantee System (PGS), and digital monitoring of progress.

To enhance field coordination and digital data management, 15 smartphones were distributed to Master Trainers in East and West Kameng districts. These devices will be used to track farming activities, collect field-level data, and ensure efficient communication among trainers, farmers, and agricultural experts to address on-ground challenges effectively.

Additionally, Master Trainers received training materials to support farmer education sessions within the clusters. These materials include modules on organic practices, composting techniques, and natural pest management—designed to strengthen grassroots knowledge on sustainable farming practices.

As part of the seed support initiative, buckwheat seeds were distributed in several clusters: four clusters in Shergaon, one in Jigaon, one in Membachur, and four clusters in Rupa and Thongre.

The distribution ceremony was graced by several senior NECTAR officials, including Shri Rakesh Kumar Samah (Chief Coordinator, Technical), Dr. Prabhat Borpuza (Regional Officer), Shri Pranjal Saikia (MIS Coordinator), Shri Dharmendra Kumar Jha (Senior Analyst), and Shri Bipul Sinha (Junior Analyst).

Share Facebook Twitter YouTube Instagram

224 0

## Climate trend prediction needs tech teeth: CM

By Our Reporter

**SHILLONG, Aug 2:** Chief Minister Conrad K. Sangma on Friday laid thrust on leveraging technology to have stronger models of predictability and analysing climate trends and monitoring mechanisms.

Addressing the inaugural function of a workshop for forest officials on "Forest Survey & Mapping for Meghalaya Using Hybrid System to Analyse Carbon Financing and Phyto-diversity Heat Map & Provisions of the BD Act (Amendment)" here, he spoke at length on the importance of the use of technology for data collection and usage, mapping and synchronizing the data collected.

"Using the data (collected) from different departments and observing the trends will allow government to make the right policies," Sangma said, adding that effective interventions will have a larger impact.

He said the implementation of the Biological Diversity Act and its 2023 amendment are important for Meghalaya, a state renowned for



its rich biodiversity and traditional knowledge.

"The provisions of the Act will enable us to protect our biological resources and associated traditional knowledge from exploitation and ensure that local communities benefit from the sustainable use of these resources," he added.

Sangma further stated that the goal of implementing the provisions of the Act in Meghalaya is to foster a

sustainable relationship with nature where conservation and development go hand in hand.

He expressed satisfaction over the results of a recent survey of the state's reserve forests, conducted using advanced aerial LiDAR and Hyperspectral imaging technologies.

"These cutting-edge methods have enabled an in-depth analysis of Meghalaya's reserve forest biodiversity, health and environmental

challenges," the CM said.

He said Meghalaya's new framework involves creating an inventory of its natural assets and assessing the economic value of its ecosystem services. The idea is to develop innovative financial tools and secure funding for conservation efforts.

"We aim to establish a new revenue model around nature conservation and climate action, ranging from carbon farming and regenerative agriculture to monetising ecosystem services of our forests," Sangma said.

He released the final report on "Forest Survey & Mapping for Meghalaya Using Hybrid System to Analyse Carbon Financing and Phyto-diversity Heat Map".

RS Gill, PCCF & HoFF, Dr. Anil Kumar Sarma, DCF, NECTAR, and Pravin Bakshi, Commissioner & Secretary, Forest & Environment and Chairman of Meghalaya Biodiversity Board were among dignitaries present.



## Assam News

**Assam: ISRO's 'Space on Wheels' Awareness Programme Held at Darrang College, Tezpur**

A significant awareness programme, a part of the ISRO ongoing "Space on Wheels" initiative was jointly organized by Vignan Bharti, North East Space Movement (NESM), NECTAR in collaboration with Assam State Commission for Protection of Child Rights ASCPCR and North East Space Application Centre (NESAC) in the auditorium of Darrang College, Tezpur.



Sentinel Digital Desk

Published on: 19 Sep 2024, 7:09 am

Tezpur: A significant awareness programme, a part of the Indian Space Research Organization's (ISRO) ongoing "Space on Wheels" initiative was jointly organized by Vignan Bharti, North East Space Movement (NESM), North East Centre for Technology Application Reach (NECTAR) in collaboration with Assam State Commission for Protection of Child Rights (ASCPCR) and North East Space Application Centre (NESAC) in the auditorium of Darrang College, Tezpur.

<https://www.sentinelassam.com/north-east-india-news/assam-news/assam-isro-space-on-wheels-awareness-programme-held-at-darrang-colleg...> 1/9

10/7/24, 2:39 PM

Shillong teachers given a crash course in advanced Science, Technology &amp; Maths Skills

Hubnews

Hubnews

**Shillong teachers given a crash course in advanced Science, Technology & Maths Skills**

By Hub Network September 23, 2024 376



Shillong, Sept 23: The North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), in collaboration with the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune and Smart Village Movement (SVM), Meghalaya, recently organized a one-day workshop titled "STEM - Mobilising Science and Technology-Based Learning for Schools."

Held at St. Edmund's College in Shillong, the workshop aimed to equip educators with innovative teaching techniques in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).

A total of 100 teachers from schools in Shillong and surrounding areas participated in the event, which focused on fostering inquiry-based learning, creativity, and curiosity among students.

<https://hubnetwork.in/shillong-teachers-given-a-crash-course-in-advanced-science-technology-maths-skills/>





The Sentinel  
of this land, for its people

## Pre-event of Metapoise V1.0 at Dibrugarh University



A CORRESPONDENT

**DIBRUGARH, Sept 4:** Dibrugarh University's Department of Computer Science and Engineering at DUIET, in collaboration with the Office of the Dean, Student Affairs, and North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR) hosted on Tuesday at a pre-

event for Metapoise v1.0.

The event titled, "Digital Transformation", featured distinguished speakers who highlighted key advancements in technology. Prof. Surajit Borkotokey, Dean, Student Affairs at Dibrugarh University, delivered the welcome address. Prof. Jiten Hazarika, Vice Chancellor of Dibrugarh Univer-

sity inaugurated the session.

Dr. Arun Kumar Sarma, Director General of NECTAR, discussed S&T interventions for Northeast India, while Guruprasad Poddar, AVP of Product Line Service Components, presented on Advanced Surface Technology. Sukdeb Barman, Application Engineer at Adroitec Information System Pvt. Ltd., captivated

the audience with insights on 3D Printing Technology and its role in Industry 4.0. Dr. Ganesh Khadanga, Scientist 'F' at the National Informatics Centre, explored the uses of Generative AI and Blockchain in industry and security.

Dhirendra Kumar from IoTech World Aviation introduced innovations like AGROBOT and AGRINET, focusing on agri-entrepreneurship. Rajendra Jena, Chief Geomatics Officer at NECTAR, provided insights into the applications of drone technology.

The event also included hands-on demonstrations by Sukdeb Barman on 3D printing, Dhirendra Kumar on agricultural drones, and Sattyam, Geomatics Officer at NECTAR, alongside Nitin Sharma, drone pilot and Senior Analyst at NECTAR, on drone data acquisition and mapping.

The session concluded with a vote of thanks from Dr. Kaushik Das, Assistant Professor at the Department of CSE, DUIET.

Guwahati English Edition Edition  
Sep 05, 2024 Page No. 5  
Powered by: erelego.com

10/21/24, 2:38 PM

To promote organic farming, NECTAR gives away smartphones to farmers | The Shillong Times

The Shillong Times

# The Shillong Times

ESTABLISHED 1945

MEGHALAYA

To promote organic farming, NECTAR gives away smartphones to farmers

By: By Our Reporter October 20, 2024

## To promote organic farming, NECTAR gives away smartphones to farmers

By Our Reporter

**SHILLONG, Oct 19:** As part of its project, 'Promoting Scientific Organic Cultivation in Northeast India', NECTAR distributed smartphones to farmers from various districts of Meghalaya.

According to a statement, the project, sanctioned by the Ministry of DoNER under the PMDevINE scheme, aims to create 250 organic-certified clusters across the Northeast.

In Meghalaya, the initiative includes establishing 55 farm labs across all districts in collaboration with Meghalaya State Rural Livelihoods Society (MSRLS) and the Bio Resources Development Centre (BRDC).

"55 lead farmers were earlier trained as master trainers by BRDC who will manage the demo farm labs and train 100 farmers in the respective clusters for organic farming," the statement said.

In a bid to support digital agriculture and the management of information systems,

smartphones were distributed to the master trainers during a programme at NECTAR's Shillong Office on Friday.

During the programme, Director of ICAR-ATARI, Dr. AK Mohanty, emphasised reducing the use of chemical fertilisers for long-term agricultural benefits.

He also stressed the importance of bio-stimulant and bio-control startups with rigorous lab and field trials.

The programme also saw farmers engaged in one-on-one interactions with scientists, including Prof. Pranab Dutta from CPGS-CAU, Umiam, who shared his expertise in organic farming in Meghalaya and discussed local solutions for local challenges.

On the other hand, NECTAR Director General, Dr. Arun K. Sarma, expressed concern over inefficient market linkages between farmers and consumers and assured that the project would address this issue, benefiting 25,000 farmers across the Northeast.

By Our Reporter

**SHILLONG, Oct 19:** As part of its project, 'Promoting Scientific Organic Cultivation in Northeast India', NECTAR distributed smartphones to farmers from various districts of Meghalaya.

According to a statement, the project, sanctioned by the Ministry of DoNER under the PMDevINE scheme, aims to create 250 organic-certified clusters across the Northeast.

In Meghalaya, the initiative includes establishing 55 farm labs across all districts in collaboration with Meghalaya State Rural Livelihoods Society (MSRLS) and the Bio Resources Development Centre (BRDC).

"55 lead farmers were earlier trained as master trainers by BRDC who will manage the demo farm labs and train 100 farmers in the respective clusters for organic farming," the statement said.

In a bid to support digital agriculture and the management of information systems, smartphones were distributed to the master trainers during a programme at NECTAR's Shillong Office on Friday.

During the programme, Director of ICAR-ATARI, Dr. AK Mohanty, emphasised reducing the use of chemical fertilisers for long-term agricultural benefits.

He also stressed the importance of bio-stimulant and bio-control startups with rigorous lab and field trials.

The programme also saw farmers engaged in one-on-one interactions with scientists, including Prof. Pranab Dutta from CPGS-CAU, Umiam, who shared his expertise in organic farming in Meghalaya and discussed local solutions for local challenges.

On the other hand, NECTAR Director General, Dr. Arun K. Sarma, expressed concern over inefficient market linkages between farmers and consumers and assured that the project would address this issue, benefiting 25,000 farmers across the Northeast.

<https://theshillongtimes.com/2024/10/20/to-promote-organic-farming-nectar-gives-away-smartphones-to-farmers/>

1/1



**INDIA  
TODAY NE**
**PM-DevINE initiative: Demo farm lab inaugurated to boost organic farming in northeast**


<https://www.indiatodayne.in/assam/story/pm-devine-initiative-demo-farm-lab-inaugurated-to-boost-organic-farming-in-northeast-1128491-2024-11-28>


**The Sentinel**  
*of this land, for its people*
**Assam: NECTAR Inaugurates Demo Farm Lab At Karbi Anglong**


<https://www.sentinelassam.com/north-east-india-news/assam-news/assam-nectar-inaugurates-demo-farm-lab-at-karbi-anglong>

**EastMojo**
**Assam's Karbi Anglong gets new demo farm lab**


<https://www.eastmojo.com/assam/2024/11/28/assams-karbi-anglong-gets-new-demo-farm-lab/>

**NORTH EAST  
MONITOR**  
*News, Views and Analysis from North East*
**PM-DevINE initiative: Demo farm lab inaugurated to boost organic farming in northeast**


<https://northeastmonitor.com/2024/11/28/pm-devine-initiative-demo-farm-lab-inaugurated-to-boost-organic-farming-in-northeast/>

**Training module on GIS, Remote Sensing under way**

The vital role of GIS and remote sensing in addressing pressing environmental challenges such as climate change, urbanization, disaster management, and resource planning underscored

**STAFF REPORTER**

**GUWAHATI, Jan 28:** The Cotton University in collaboration with the North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR) organized a comprehensive 10-day training module on Geospatial Information Systems (GIS) and Remote Sensing recently. The training, hosted at the Physics department's conference room, brings together students, researchers, academicians, and professionals eager to enhance their technical expertise in geospatial technologies.

According to a press release, the inaugural programme commenced with a warm welcome and felicitation of the chief guest, the Director General of NECTAR, Dr. Arun Sharma and the guest of honour, the Vice-Chancellor of Cotton University, Prof. Ramesh Ch. Deka.

The ceremony was led by Sattiyam Tripathi and Nikita Gogoi of NECTAR. The Registrar of Cotton University, Dr. Arindam Gogoi, delivered the welcome address, acknowledging the collaborative efforts of host institutions in organizing the programme.

The director of the Centre for Clouds and Climate Change Research (CCCCR), Cotton University, Dr. Rahul Mahanta presented an overview of the training programme.

He underscored the vital role of GIS and remote sensing in addressing pressing environmental challenges such as climate change, urbanization, disaster management, and resource planning.

Vice-chancellor Prof. Deka expressed pride in hosting the training module, emphasizing the importance of equipping participants with state-of-the-art knowledge and tools to contribute effectively to regional and national development.

Director general of NECTAR, Dr. Sharma delivered the keynote speech focusing on the transformative potential of geospatial technologies in enhancing policy decisions and sustainable development.

He commended Cotton University for its dedication to building capacities in this critical field and highlighted NECTAR's ongoing efforts to promote technological advancements in Northeast India.

Running from January 21 to January 30, 2025, the training

programme provides a blend of theoretical knowledge and practical applications.

The programme will feature expert lectures, hands-on sessions with advanced geospatial software, and case studies illustrating the unique environmental and developmental challenges. Participants will receive certifications upon successful completion.

Speaking on the occasion, the Director of CCCR, Dr. Mahanta said, "The collaboration between Cotton University and NECTAR underscores our commitment to fostering technological advancements and capacity building. GIS and remote sensing are not just tools but transformative technologies that can shape the future of sustainable development in Northeast India."

This training module is the first in a series of 12 programmes planned by the 2025-26 financial year. With two programmes scheduled every quarter, the programme aims to ensure that students from across the Northeast region, both from urban and rural colleges, have access to this transformative initiative.

The chief guest of the event, Dr. Arun Sharma, director general (DG) of NECTAR, delivered the keynote address, highlighting the crucial role of GIS and remote sensing in global and regional development. In his keynote address, the director general of NECTAR provided a comprehensive overview of how GIS and remote sensing have transformed modern research, decision-making, and governance.

"The world today is witnessing rapid advancements in geospatial technology. GIS and remote sensing are no longer confined to specialized fields but have become indispensable tools in multiple domains - including climate monitoring, disaster management, resource mapping, and urban planning," he said.

"For regions like Northeast India, which face unique environmental and socio-economic challenges, the application of these technologies can be a game-changer. From improving agricultural productivity and biodiversity conservation to better disaster preparedness and infrastructure planning, GIS and remote sensing provide a data-driven approach to decision-making. Training programmes like these are essential for ensuring that students, researchers, and professionals gain the necessary skills to contribute meaningfully to India's technological growth and environmental resilience," he added.

The special secretary to the Government of Assam and director of Assam State Space Application Centre, Prof. R. Raju, shared his perspectives on the growing importance of geospatial technologies in governance, environmental management, and sustainable development.

**Training module on GIS, remote sensing held at Dimoria College**

The mobile campus course is designed to equip students, researchers, and professionals with practical expertise in GIS, remote sensing, digital image processing, and cartography

**STAFF REPORTER**

**GUWAHATI, Feb 19:** A 10-day training module on GIS and remote sensing, jointly organized by the Centre for Clouds and Climate Change Research (CCCCR), Cotton University and the North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), Shillong, was held at Dimoria (Autonomous) College.

The mobile campus course is designed to equip students, researchers, and professionals with practical expertise in GIS, remote sensing, digital image processing, and cartography.

The vice-chancellor of Cotton University, Prof. R. Deka, inaugurated the event, emphasizing the university's commitment to fostering research-driven education and technological skill development in the Northeast region.

The chief guest of the event, Dr. Arun Sharma, director general (DG) of NECTAR, delivered the keynote address, highlighting the crucial role of GIS and remote sensing in global and regional development.

In his keynote address, the director general of NECTAR provided a comprehensive overview of how GIS and remote sensing have transformed modern research, decision-making, and governance.

"The world today is witnessing rapid advancements in geospatial technology. GIS and remote sensing are no longer confined to specialized fields but have become indispensable tools in multiple domains - including climate monitoring, disaster management, resource mapping, and urban planning," he said.

"For regions like Northeast India, which face unique environmental and socio-economic challenges, the application of these technologies can be a game-changer. From improving agricultural productivity and biodiversity conservation to better disaster preparedness and infrastructure planning, GIS and remote sensing provide a data-driven approach to decision-making. Training programmes like these are essential for ensuring that students, researchers, and professionals gain the necessary skills to contribute meaningfully to India's technological growth and environmental resilience," he added.

The special secretary to the Government of Assam and director of Assam State Space Application Centre, Prof. R. Raju, shared his perspectives on the growing importance of geospatial technologies in governance, environmental management, and sustainable development.

He provided an expert analysis of how space-based technologies and remote sensing applications are being integrated into policy frameworks for effective governance.

On the sidelines of the programme, the director of the Centre for Clouds and Climate Change Research, Cotton University, Dr. Rahul Mahanta, emphasized the comprehensive nature of the training module and its potential to empower future professionals in geospatial sciences.

The 10-day mobile campus course covers an extensive range of topics, ensuring a balance of theoretical knowledge and practical skills. Following the training, participants will undergo assessments, culminating in a certification ceremony recognizing their expertise in GIS and remote sensing technologies.

The special secretary to the Government of Assam and director of Assam State Space Application Centre, Prof. R. Raju, shared his perspectives on the growing importance of geospatial technologies in governance, environmental management, and sustainable development.

The special secretary to the Government of Assam and director of Assam State Space Application Centre, Prof. R. Raju, shared his perspectives on the growing importance of geospatial technologies in governance, environmental management, and sustainable development.

The special secretary to the Government of Assam and director of Assam State Space Application Centre, Prof. R. Raju, shared his perspectives on the growing importance of geospatial technologies in governance, environmental management, and sustainable development.

The special secretary to the Government of Assam and director of Assam State Space Application Centre, Prof. R. Raju, shared his perspectives on the growing importance of geospatial technologies in governance, environmental management, and sustainable development.

The special secretary to the Government of Assam and director of Assam State Space Application Centre, Prof. R. Raju, shared his perspectives on the growing importance of geospatial technologies in governance, environmental management, and sustainable development.

The special secretary to the Government of Assam and director of Assam State Space Application Centre, Prof. R. Raju, shared his perspectives on the growing importance of geospatial technologies in governance, environmental management, and sustainable development.

The special secretary to the Government of Assam and director of Assam State Space Application Centre, Prof. R. Raju, shared his perspectives on the growing importance of geospatial technologies in governance, environmental management, and sustainable development.



### AdtU hosts workshop on Antibioqram, Audiometer Devices, and Calibration with NECTAR, Anna University

Date- 21st Jan 2025



Assam down town University, in collaboration with North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), Anna University Chennai, and down town hospital, successfully hosted a one-day hands-on workshop and brainstorming session focused on "Antibioqram, Audiometer Devices, and Calibration".

The event aimed to enhance the knowledge and practical skills of participants in key areas of medical diagnostics and device calibration. It brought together a diverse group of experts, academicians, and medical professionals from across the city.

The workshop was inaugurated by Dr. N.C. Talukdar, Vice Chancellor of AdtU, along with key speakers including Mrs. Mayurakshi Dutta, Executive Director of down town Hospital, Dr. Abhijit Dutta, Dean of Paramedical Science at AdtU, Dr. Shilo Singh, Associate Dean of the Institute of Paramedical Studies at AdtU, Dr. Arun Kumar Sarma, Director General of NECTAR, Dr. Pooja Das from NECTAR, and experts from Anna University. Paramedical faculty and students from AdtU also participated in the session.

The event featured sessions on three critical topics: Antibioqram, a tool for determining antibiotic resistance patterns; Audiometer Devices, equipment for hearing tests; and Device Calibration, ensuring accuracy and reliability in medical equipment. Dr. N.C. Talukdar, Vice Chancellor, AdtU, highlighted the importance of collaborative efforts in improving healthcare standards, especially in Northeast India.

Dr. M. Sasikala from Anna University delivered a comprehensive lecture on combating antibiotic resistance, emphasizing the critical role of antibiograms. Dr. S. Muttan demonstrated the latest advancements in audiometer technology, showcasing calibration procedures essential for accurate hearing assessments, alongside Dr. K. Shankaran and Dr. Rohit Radhakrishnan, who contributed expertise from their respective fields.



Quality Council of India



Driving Quality for the North East India

QCI Secretary-General, Shri Chakravarthy T. Kannan, Dr. A. Raj (CEO NBQP), and Shri Subroto Ghosh (Head P3ID) met with Dr. Arun Kumar Sarma, Director General of NECTAR, an autonomous body under the Department of Science and Technology, Government of India, to discuss the pivotal role of quality in driving social and economic development in the North Eastern Region.

The discussion centered on leveraging technology to empower communities, institutions, and people, ensuring inclusive growth and sustainable progress in the region.



Kannan Chakravarthy | Dr. Aishwarya Raj | Subroto Ghosh | Dr. Arun Kumar Sarma | North East Centre for Technology Application and Reach | NBQP - National Board for Quality Promotion



ত্রিপুরা সরকার  
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিদপ্তর

\*\*\*\*\*

সং-২৬৭৯  
আগারতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে কর্মশালা  
বাঁশ চাষের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন  
প্রশমিত করা সম্ভব : পরিবেশমন্ত্রী



‘জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বাঁশের ভূমিকা’ বিষয়ে এক কর্মশালা আজ লিচুবাগানস্থিত বাঁশ অ্যান্ড কেইন ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিসিডিআই)-এর কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেস দেববার্মা। অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে রাজ্যের অর্থনৈতিক বাবস্থা ও পরিবেশের উপর বাঁশের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ে পরিবেশমন্ত্রী বলেন, বাঁশ ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি অনন্য বনজ সম্পদ। প্রচুর পরিমাণে বাঁশ চাষের মাধ্যমে রাজ্যের জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমিত করা সম্ভব।

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরার মাটি বাঁশ উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট ভালো। বাঁশ অর্থনৈতিক দিক দিয়েও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাঁশকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরার জনগণ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হচ্ছেন। কর্মশালায় বাগত বক্তব্য রাখেন বিসিডিআই-এর ইনার্চার্জ ড. অভিনব কান্ত। কর্মশালায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব ড. শশী কুমার, ইনার্চার্জ অব রুইমেট চেঞ্জ সেল সুশান্ত বণিক। একদিন ব্যাপী কর্মশালায় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়, টিআইটি ও কৃষি মহাবিদ্যালয় থেকে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

\*\*\*\*\*

### Workshop highlights bamboo's role in climate change mitigation

Agartala, Feb 11, 2025, TRIPURATIMES Desk

Agartala, Feb 11: The Forest Minister Animesh Debbarma on Tuesday emphasized the importance of bamboo cultivation in combating climate change at a one-day workshop titled "The Role of Bamboo in Climate Change Mitigation" at the Bamboo and Cane Development Institute in Lichubagan. The event was attended by officials from the Science and Technology Department, including the secretary, along with students from various colleges.



Addressing the gathering, Debbarma stressed the need to raise awareness about climate change and promote carbon-neutral practices to restore environmental balance. "We are making efforts to help people understand the mitigation process, and bamboo cultivation plays a crucial role in this," he said.

The workshop explored various strategies to enhance bamboo cultivation and its potential to absorb carbon dioxide efficiently. Experts discussed how large-scale bamboo plantations could serve as a sustainable solution for reducing carbon footprints.

With Tripura's favorable climate for bamboo growth, officials highlighted the need for policy support and community participation to maximize its benefits. The event also included discussions on innovative cultivation techniques to expand bamboo production in the state.



#### GET IN TOUCH

40, Akhaura Road, Agartala 799 001, Tripura, INDIA.

Administrative Section: 0361-2329507

News Section: 0361-2329560

tripuratimesdigital@gmail.com

FOLLOW US



#### IMPORTANT NEWS



4 THE ASSAM TRIBUNE, GUWAHATI

## Training module on GIS, remote sensing begins at Dimoria College

STAFF REPORTER

GUWAHATI, Feb. 11: A 10-day training module on GIS and remote sensing, jointly organized by the Centre for Cloud and Climate Change Research (CCCCR), Cotton University, and the North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), Shillong, began at Dimoria (Autonomous) College on Monday.

This mobile campus course is designed to equip students, researchers, and professionals with practical expertise in GIS, remote sensing, digital image processing, and cartography.

Cotton University Vice-Chancellor Professor RC Deka inaugurated the event, emphasising the university's commitment to fostering research-driven education and technological

skill development in the North East region.

NECTAR Director General (DG) Dr Arun Kumar Sharma, the chief guest, delivered the keynote address, highlighting the crucial role of GIS and remote sensing in global and regional development.

In his address, Dr Sharma provided a comprehensive overview of how GIS and remote sensing have transformed modern research, decision-making, and governance.

"The world today is witnessing rapid advancements in geospatial technology. GIS and remote sensing are no longer confined to specialized fields but have become indispensable tools in multiple domains - including climate monitoring, disaster management, resource mapping, and urban planning," he said.

"For regions like North

East India, which face unique environmental and socio-economic challenges, the application of these technologies can be a game-changer.

Dr Sharma shared his perspectives on the growing importance of geospatial technologies in governance, environmental management, and sustainable development.

He provided an expert analysis of how space-based technologies and remote sensing applications are being integrated into policy frameworks for effective governance, recognizing their potential in GIS and remote sensing technologies.

On the sidelines of the programme, the Director of

the Centre for Cloud and Climate Change Research at Cotton University, Dr Rahul Mahanta, emphasised the comprehensive nature of the training module and its potential to empower future professionals in geospatial sciences.

The 10-day mobile-campus course covers a wide range of topics, ensuring a balance of theoretical knowledge and practical skills. Following the training, participants will undergo assessments, culminating in a certification ceremony recognizing their expertise in GIS and remote sensing technologies.

AGM of Assam Financial Corporation held

## Farmers' Mobilization & Awareness Programme organised by NECTAR under PM-DevINE Scheme in Nihoto Village

Dimapur: North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), an autonomous institute under the Department of Science and Technology (DST), Government of India, with its headquarters in Shillong, conducted a Farmers' Mobilization and Awareness Programme on 17th March, 2025. The programme was held in Nihoto Village of Dimapur district in Nagaland where representatives from eight villages participated. It was part of the PM-DevINE project "NECTAR Livelihood Improvement project (Multi State) - A Value Chain on Utilization of Banana Pseudo Stem for Value-Added Products", which is being implemented by NECTAR. Under this scheme, NECTAR constructed a Common Facility Centre (CFC) in Kakibolong village, Chumukedima in Nagaland. This project is focused on creating sustainable livelihoods and rural entrepreneurship by encouraging the utilization of Banana Pseudo-stem by converting it into various marketable products, like Extraction of fibre from banana pseudo stem, preparing non-woven fabrics, preparation of organic liquid nutrient using banana pseudo stem and various types of hand-made paper from banana fibre. The training was conducted by Consortium for Training, Research and Development (CTRD), Guwahati with support from SDAO Phekphong, Kohima. The programme also received valuable insights from SDAO Phekphong, Kohima, and progressive farmer Kintho S. Rotokha and officials from NECTAR. They guided farmers on best agricultural practices and emphasized the importance of supporting the Common Facility Centre (CFC) for the collective benefit of the community. This initiative is expected to boost rural entrepreneurship, reduce agricultural



waste, and promote sustainable industrial development in North East India. The North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR) is an autonomous body under the Department of Science and Technology (DST), Government of India. It was established to leverage cutting-edge technologies for the socio-economic development of the North Eastern Region (NER). NECTAR primarily focuses on applying advanced technologies in key sectors such as agriculture, healthcare, infrastructure, environment, and disaster management to enhance the quality of life and promote sustainable growth in the region. One of NECTAR's main objectives is to bridge the technology gap between research institutions and local communities by facilitating the application of scientific innovations. The organization promotes the use of geospatial technology, drone-based solutions, bamboo applications, and bio-resources to create livelihood opportunities and improve resource

ing, value addition in medicinal plants, and promoting bio-energy solutions. NECTAR collaborates with universities, research institutes, and industry experts to implement projects that address region-specific challenges. In addition to technology-driven initiatives, NECTAR also conducts skill development programs and capacity-building workshops to empower local communities, artisans, and entrepreneurs. By integrating technology with traditional knowledge systems, the organization plays a crucial role in fostering innovation-led growth in the North East. With a vision to transform the region into a hub of technological excellence, NECTAR continues to explore new-age solutions to drive economic development, environmental sustainability, and improved living standards for the people of North East India.

## Inauguration of CFC under PM-DevINE Scheme at Chumoukedima

Nagaland: The North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), an autonomous institute under the Department of Science and Technology, Government of India, inaugurated a Common Facility Centre (CFC) at New Chumoukedima village, Chumoukedima, Nagaland. The facility has been established under the Ministry of DoNER's PM-DevINE scheme as part of the "NECTAR Livelihood Improvement Project - A Value Chain on Utilization of Banana Pseudo-stem for Value-Added Products," which aims to promote sustainable livelihoods, skill development, and value addition through the efficient utilization of agricultural waste in the entire North East India. The event was graced by Shri Chanchal Kumar, Secretary, Ministry of DoNER, as the Chief Guest. Several other dignitaries from central and state departments, including senior officials from the Ministry of DoNER, Government of Nagaland, and representatives from developmental institutions, were also present and expressed their support for the initiative. Former minister of Nagaland, Doshevi Y. Sema was also present in the event. Another key highlight of the event was the formal launch of an organic biofertilizer derived from banana pseudostem sap - a product developed under the same project to provide eco-friendly fertilizer alternatives for farming communities. This initiative not only promotes circular economy but also directly supports soil health and sustainable agriculture practices in the region. Dr. Arun Kumar

Sharma, Director General, NECTAR, delivered a detailed presentation showcasing the broader objectives of the PM-DevINE project and NECTAR's portfolio of livelihood-oriented technological interventions across the North-east. He highlighted how this specific project addresses a critical gap in agricultural waste management by converting banana pseudostem - typically discarded as waste into different useful and marketable products, including natural fiber, biodegradable sheets, and handmade paper. He emphasized that this model offers both environmental and economic benefits and can be replicated across other regions and crops with similar challenges. Another important milestone marked during the ceremony was the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between NECTAR and The Entrepreneurs' Association (IEA) based in Nagaland, formalizing

their collaboration for implementation and operation of the CFC. The MoU outlines joint responsibilities for technology demonstration, community mobilization, training, and enterprise development. The Entrepreneurs' Association is a grassroots development group with extensive local experience in fostering entrepreneurship, having helped thousands of farmers and more than 18,000 first-generation business owners in the area. The establishment of this CFC is a step in leveraging region-specific resources and technologies to enhance rural livelihoods, entrepreneurship, and sustainable waste management. As one of twelve such centers planned under the PM-DevINE initiative, it reflects the government's commitment to integrated development in the North Eastern Region through targeted infrastructure, innovation, and community partnerships. Another important project under the Prime Minister's Development Initiative for North East Region (PM-DevINE) scheme supported by the Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER) is "Promoting Scientific Organic Agriculture in NE India" which is an initiative by North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR). The aim of the project is to create 250 organic certified clusters (75 in Assam, 55 in Meghalaya, 50 in Tripura, 20 in Mizoram, 20 in Nagaland, 15 in Arunachal Pradesh and 15 in Manipur) with capacity building of 250 Master Trainers and 25000 Trainee Farmers.

## Cotton University, NECTAR and St. Anthony's College Collaborate to conduct Geospatial Learning

Shillong: Unlocking the Future of Geospatial Technologies: NECTAR Launches 10-Day Mobile Campus GIS and Remote Sensing Training Program in Shillong, Meghalaya. In a groundbreaking initiative to empower students, researchers, and professionals with essential geospatial skills, the North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), in collaboration with Cotton University and St. Anthony's College, Shillong, has launched the fourth batch of its highly anticipated 10-day Mobile Campus-based GIS and Remote Sensing training program. This dynamic training, aimed at honing practical skills and expertise in GIS, remote sensing, digital image processing, and cartography, commenced today at St. Anthony's College. The Geology Department of St. Anthony's College, in association with NECTAR, has spearheaded this training program, designed to equip participants with hands-on experience and in-depth knowledge in cutting-edge geospatial technologies. This initiative serves as a vital platform for developing the skill set necessary for tackling regional challenges in the Northeast, particularly in the face of difficult terrain of Meghalaya and other parts of the region. Dr. Arun Kumar Sharma, Director General of NECTAR, inaugurated the training program with an inspiring address to the students. He emphasized the significance of this opportunity for students to dive into the world of geospatial applications through expert-led practical sessions and advanced software tools. Dr. Sharma also highlighted NECTAR's unwavering commitment to advancing geospatial research in the Northeast, underscoring the role of GIS and remote sensing in addressing regional issues such as environmental management, disaster control, and resource mapping. Stated "The world is experiencing a rapid evolution in geospatial technology, with GIS and remote sensing transforming not only research and decision-making but also governance. These technologies are crucial for addressing climate challenges, enhancing disaster preparedness, managing resources, and

supporting sustainable urban planning," said Dr. Sharma during his keynote speech. "For regions like Northeast India, with its unique environmental and socio-economic challenges, the adoption of geospatial tools can be a game-changer. This training program plays a crucial role in fostering a data-driven approach to solving the region's issues." Dr. Sharma also encouraged students and faculty to engage with NECTAR's geospatial infrastructure and contribute their innovative ideas to furthering research in this vital sector. He assured participants that NECTAR remains committed to expanding geospatial research programs, bridging the gap between theoretical knowledge and

practical application in the region. The event is graced by the Principal of the College Fr. Acaudius Puvion by his warm welcome address, urging students to explore the expertise facilities of NECTAR and Shri Rajendra Jena, Chief Geomatics Officer highlighted the objective of this unique off-campus program of NECTAR with meticulously designed to the comfort of students and curriculum in synchronized manner towards the practical applications. Dr. Colin Z. Renihill, Advisor (Technical), NECTAR also joined the event and discussed about the future collaboration on faculty development programs for better learning ecosystem in the sector of Geospatial Technology Application through the initiative of St. Anthony's College. On the sidelines of the program the Director of the Centre for Cloud and Climate Change Research, Cotton University, Dr. Rahul Mahanta who coordinates and oversees the whole program in the region, shares an inspiring message to participants.

practical application in the region. The event is graced by the Principal of the College Fr. Acaudius Puvion by his warm welcome address, urging students to explore the expertise facilities of NECTAR and Shri Rajendra Jena, Chief Geomatics Officer highlighted the objective of this unique off-campus program of NECTAR with meticulously designed to the comfort of students and curriculum in synchronized manner towards the practical applications. Dr. Colin Z. Renihill, Advisor (Technical), NECTAR also joined the event and discussed about the future collaboration on faculty development programs for better learning ecosystem in the sector of Geospatial Technology Application through the initiative of St. Anthony's College. On the sidelines of the program the Director of the Centre for Cloud and Climate Change Research, Cotton University, Dr. Rahul Mahanta who coordinates and oversees the whole program in the region, shares an inspiring message to participants.

practical application in the region. The event is graced by the Principal of the College Fr. Acaudius Puvion by his warm welcome address, urging students to explore the expertise facilities of NECTAR and Shri Rajendra Jena, Chief Geomatics Officer highlighted the objective of this unique off-campus program of NECTAR with meticulously designed to the comfort of students and curriculum in synchronized manner towards the practical applications. Dr. Colin Z. Renihill, Advisor (Technical), NECTAR also joined the event and discussed about the future collaboration on faculty development programs for better learning ecosystem in the sector of Geospatial Technology Application through the initiative of St. Anthony's College. On the sidelines of the program the Director of the Centre for Cloud and Climate Change Research, Cotton University, Dr. Rahul Mahanta who coordinates and oversees the whole program in the region, shares an inspiring message to participants.

practical application in the region. The event is graced by the Principal of the College Fr. Acaudius Puvion by his warm welcome address, urging students to explore the expertise facilities of NECTAR and Shri Rajendra Jena, Chief Geomatics Officer highlighted the objective of this unique off-campus program of NECTAR with meticulously designed to the comfort of students and curriculum in synchronized manner towards the practical applications. Dr. Colin Z. Renihill, Advisor (Technical), NECTAR also joined the event and discussed about the future collaboration on faculty development programs for better learning ecosystem in the sector of Geospatial Technology Application through the initiative of St. Anthony's College. On the sidelines of the program the Director of the Centre for Cloud and Climate Change Research, Cotton University, Dr. Rahul Mahanta who coordinates and oversees the whole program in the region, shares an inspiring message to participants.

practical application in the region. The event is graced by the Principal of the College Fr. Acaudius Puvion by his warm welcome address, urging students to explore the expertise facilities of NECTAR and Shri Rajendra Jena, Chief Geomatics Officer highlighted the objective of this unique off-campus program of NECTAR with meticulously designed to the comfort of students and curriculum in synchronized manner towards the practical applications. Dr. Colin Z. Renihill, Advisor (Technical), NECTAR also joined the event and discussed about the future collaboration on faculty development programs for better learning ecosystem in the sector of Geospatial Technology Application through the initiative of St. Anthony's College. On the sidelines of the program the Director of the Centre for Cloud and Climate Change Research, Cotton University, Dr. Rahul Mahanta who coordinates and oversees the whole program in the region, shares an inspiring message to participants.

practical application in the region. The event is graced by the Principal of the College Fr. Acaudius Puvion by his warm welcome address, urging students to explore the expertise facilities of NECTAR and Shri Rajendra Jena, Chief Geomatics Officer highlighted the objective of this unique off-campus program of NECTAR with meticulously designed to the comfort of students and curriculum in synchronized manner towards the practical applications. Dr. Colin Z. Renihill, Advisor (Technical), NECTAR also joined the event and discussed about the future collaboration on faculty development programs for better learning ecosystem in the sector of Geospatial Technology Application through the initiative of St. Anthony's College. On the sidelines of the program the Director of the Centre for Cloud and Climate Change Research, Cotton University, Dr. Rahul Mahanta who coordinates and oversees the whole program in the region, shares an inspiring message to participants.

practical application in the region. The event is graced by the Principal of the College Fr. Acaudius Puvion by his warm welcome address, urging students to explore the expertise facilities of NECTAR and Shri Rajendra Jena, Chief Geomatics Officer highlighted the objective of this unique off-campus program of NECTAR with meticulously designed to the comfort of students and curriculum in synchronized manner towards the practical applications. Dr. Colin Z. Renihill, Advisor (Technical), NECTAR also joined the event and discussed about the future collaboration on faculty development programs for better learning ecosystem in the sector of Geospatial Technology Application through the initiative of St. Anthony's College. On the sidelines of the program the Director of the Centre for Cloud and Climate Change Research, Cotton University, Dr. Rahul Mahanta who coordinates and oversees the whole program in the region, shares an inspiring message to participants.

practical application in the region. The event is graced by the Principal of the College Fr. Acaudius Puvion by his warm welcome address, urging students to explore the expertise facilities of NECTAR and Shri Rajendra Jena, Chief Geomatics Officer highlighted the objective of this unique off-campus program of NECTAR with meticulously designed to the comfort of students and curriculum in synchronized manner towards the practical applications. Dr. Colin Z. Renihill, Advisor (Technical), NECTAR also joined the event and discussed about the future collaboration on faculty development programs for better learning ecosystem in the sector of Geospatial Technology Application through the initiative of St. Anthony's College. On the sidelines of the program the Director of the Centre for Cloud and Climate Change Research, Cotton University, Dr. Rahul Mahanta who coordinates and oversees the whole program in the region, shares an inspiring message to participants.

practical application in the region. The event is graced by the Principal of the College Fr. Acaudius Puvion by his warm welcome address, urging students to explore the expertise facilities of NECTAR and Shri Rajendra Jena, Chief Geomatics Officer highlighted the objective of this unique off-campus program of NECTAR with meticulously designed to the comfort of students and curriculum in synchronized manner towards the practical applications. Dr. Colin Z. Renihill, Advisor (Technical), NECTAR also joined the event and discussed about the future collaboration on faculty development programs for better learning ecosystem in the sector of Geospatial Technology Application through the initiative of St. Anthony's College. On the sidelines of the program the Director of the Centre for Cloud and Climate Change Research, Cotton University, Dr. Rahul Mahanta who coordinates and oversees the whole program in the region, shares an inspiring message to participants.

## Farmers Mobilization & Awareness Programme held in Serchhip

Serchhip: In a continued effort to bring technology and value-added opportunities closer to grassroots communities, a Farmers' Mobilization and Awareness Programme was organized on 11th April 2025 at the Serchhip Press Club, Mizoram. The event was conducted by North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), Shillong an autonomous institute under the Department of Science and Technology, Government of India. The programme witnessed the participation of 50 local farmers and stakeholders, including 37 women and 13 men, reflecting strong community interest and notable female participation. Key attendees included Mr. Kapilana Pachau, Journalist, Editor of Serchhip Times, and Chairman of Zawlpu Serchhip FPC; and Mr. Lawmhliha Ralte, Correspondent, Doordarshan Kendra (DDK), Serchhip District. The session focused on sensitizing farmers to the potential of banana pseudostem processing, covering key topics such as sustainable banana cultivation practices, the significance and properties of the pseudostem, advantages of banana fiber, stages of fi-

ber extraction, water usage, and emerging business opportunities. Participants were also introduced to the project that NECTAR is implementing titled "A Value Chain on Utilization of Banana Pseudo Stem for Value-Added Products" under the PM-DevINE Scheme funded by the Ministry of DoNER. Under this project, NECTAR is constructing a Common Facility Centre (CFC) in Serchhip for extraction of fibre from banana pseudo stem and other value-added products and banana-based vegan leather. This program has generated immense interest among the farmers in the zero-waste system. This awareness program supports the main goals of the PM-DevINE scheme helping farmers grow stronger, encouraging development that includes everyone, and bringing modern facilities closer to villages across the North Eastern Region.



TAR is implementing titled "A Value Chain on Utilization of Banana Pseudo Stem for Value-Added Products" under the PM-DevINE Scheme funded by the Ministry of DoNER. Under this project, NECTAR is constructing a Common Facility Centre (CFC) in Serchhip for extraction of fibre from banana pseudo stem and other value-added products and banana-based vegan leather. This program has generated immense interest among the farmers in the zero-waste system. This awareness program supports the main goals of the PM-DevINE scheme helping farmers grow stronger, encouraging development that includes everyone, and bringing modern facilities closer to villages across the North Eastern Region.





### Vegan Leather Revolution in Northeast India: From Agro-Waste to Sustainable Growth

by [Anurag Singh](#) • June 9, 2025

#### Short Summary

CSIR-NIIST has signed an MoU with NECTAR to establish vegan leather production units in Meghalaya and other Northeastern states. This initiative will transfer a sustainable, agro-residue-based leather technology, empowering farmers, MSMEs, and women's self-help groups. The aim is to boost local entrepreneurship, create jobs, reduce agro-waste, and align with Atmanirbhar Bharat and Make in India objectives.

### Introduction

Have you ever wondered what becomes of all that pineapple leaf, banana stem, or rice straw waste strewn across farms? What if I told you it could end up as vegan leather bags, shoes, or car interiors? Intrigued? Let's dive in.

Under a new collaboration between CSIR-NIIST and NECTAR, India's Northeast is about to witness a groundbreaking transformation. We're not just talking about experimenting with plant-based materials — we're talking about setting up full-fledged manufacturing units that empower local communities while championing sustainability. Ready for the deep dive?

### 1. What Is Vegan Leather and Why It Matters

Traditional leather production relies on animals and toxic chemicals — tanning processes often involve chromium, which is harmful to both people and the environment. Vegan leather, in contrast, is plant-based. CSIR-NIIST has pioneered a method to convert agro-residues like pineapple leaves, banana stems, and rice straw into biodegradable leather that's durable, water-resistant, and heat-proof.

## Cotton University, NECTAR and St Anthony's College collaborate to conduct Geospatial Learning in Shillong

### 10-Day Training Module on GIS and Remote Sensing Inaugurated at St Anthony's college



**GUWAHATI, April 9:** In a groundbreaking initiative to empower students, researchers, and professionals with essential geospatial skills, the Northeast Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), in collaboration with Cotton University and St Anthony's College, Shillong, has launched the fourth batch of its highly anticipated 10-day Mobile Campus-based GIS and Remote Sensing training program. This dynamic training, aimed at honing practical skills and expertise in GIS, remote sensing, digital image processing, and cartography, commenced from Wednesday at St Anthony's College.

The Geology Department of St Anthony's College, in association with NECTAR, has spearheaded this training program, designed to equip participants

with hands-on experience and in-depth knowledge in cutting-edge geospatial technologies. This initiative serves as a vital platform for developing the skill set necessary for tackling regional challenges in the Northeast, particularly in the difficult terrains of Meghalaya and other parts of the region.

Arun Kumar Sarma, Director General of NECTAR, inaugurated the training program with an inspiring address to the students. He emphasized the significance of this opportunity for students to dive into the world of geospatial applications through expert-led practical sessions and advanced software tools. Sarma also highlighted NECTAR's unwavering commitment to advancing geospatial research in the Northeast, underscoring the role of GIS and remote sensing in addressing regional issues such as environmental man-

agement, disaster control, and resource mapping.

"The world is experiencing a rapid evolution in geospatial technology, with GIS and remote sensing transforming not only research and decision-making but also governance. These technologies are crucial for addressing climate challenges, enhancing disaster preparedness, managing resources, and supporting sustainable urban planning," said Sarma during his keynote speech.

Sarma also encouraged students and faculty to engage with NECTAR's geospatial infrastructure and contribute their innovative ideas to furthering research in this vital sector. He assured participants that NECTAR remains committed to expanding geospatial research programs, bridging the gap between theoretical knowledge and practical application in the region.

The event is graced by the Principal of the College Fr. Arcadius Puwein by his warm welcome address, urging students to explore the expertise facilities of NECTAR and Shri Rajendra Jena, Chief Geomatics Officer highlighted the objective of this unique off-campus program of NECTAR with meticulously designed to the comfort of students and curriculum in synchronised more towards the practical applications. Dr. Colin Z. Renthlei, Advisor (Technical), NECTAR also joined the event and discussed about the future collaboration on faculty development programs for better learning ecosystem in the sector of Geospatial Technology Application through the initiatives of St Anthony's college.

## Ulongcaif Jima

Ulong 10, MEGHALAYA REGIONAL NATIONAL INTERNATIONAL ARTICLES EDITO 2025

Home » Meghalaya

### Pynlong jing'ialang ka St. Anthony's College na ka bynta ki samla pule BSc

Ka jingthmu ba thymmai ha ka pule puthi lyngba ka jingiatrellang jong ka North East Center for Technology Application and Reach (NECTAR). ka Cotton University bad ka St Anthony's College Shillong, ka la jing'ialang halor ka "Mobile Campus-Based Geospatial Training Program on GIS and Remote Sensing" na ka bynta ki samla pule BSc (final year) jong ka Geology ha St. Anthony's College.

Posted on: Satong 9, 2025



Shillong, Taiong 08

Ka jingthmu ba thymmai ha ka pule puthi lyngba ka jingiatrellang jong ka North East Center for Technology Application and Reach (NECTAR), ka Cotton University bad ka St Anthony's College Shillong, ka la jing'ialang halor ka "Mobile Campus-Based Geospatial Training Program on GIS and Remote Sensing" na ka bynta ki samla pule BSc (final year) jong ka Geology ha St. Anthony's College.

Ia kane ka prokram la pynlong ha ka 8 tarik mynta u bnei ha Noel Conference Hall, St. Anthony's College, Shillong ha kaba la iadon lang u Director General, NECTAR, Dr. Arun Kumar Sarma, Sh. Rajendra Jena, Dr. Collin Z Renthlei, Satyram Tripathi, Roshni Rai bad ka Nikita Gogoi.

Ia sdang ia kane ka prokram da ka jingken ai khublei na u Dr. Viji Walling, HoD ka nat Geology, bad bud sa ka jingken pile na u Rev. Fr. u Dr. Arcadius Puwein SDB. Ka jingken sdang ba la ai da u Rajendra Jena uba la pypaw ia ka jingthmu bad ka jingdonkam jong ka jingbit ha ka idi jong ki built stad lyngba ka prokram ai jinghikal shaphang ka khyndew kaba la pynshong nongrim ha ki jaka pule ba laid lyngba jong ka jaka pule ba la tyrwa da ka NECTAR.

U Dr. Arun Kumar Sarma u la ai ia ka jingken da kaba pynpaw kurno kine ki prokram ki lah ban ai ka rynsan ym tang ban lyntiew ia ka jingpyrikhat kaba jylliew bad ki jingbit ba treikam, hynrei ban pynroi ruh ia ka jingiatrellang haddeng ki nonglashim bynta, ha kaba kut ban pynhreh ia ki na ka bynta ki jingeh ba shisha lyngba ki jingpule ia ki jingila kiba lah ban pynmih hadien habud.

## NECTAR launches new initiative in East and West Kameng



**EAST KAMENG, Jun 6:** A major initiative to promote scientific organic farming has been launched in Arunachal Pradesh's East Kameng and West Kameng districts. The North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), an autonomous body under the Department of Science and Technology, is implementing the project under the PM-DevINE scheme funded by the Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER).

The project aims to

support 1,500 farmers across 15 selected clusters in the two districts. The focus is on building farmer capacity, providing organic certification, setting up demonstration farms, creating community seed banks, and using digital tools like drones to monitor crop health and farm activities.

As part of the launch, 15 smartphones were distributed to Master Trainers in East and West Kameng. These devices will help them collect real-time data from the fields and communicate directly

with experts and farmers. Trainers also received educational materials covering topics like composting, pest control, and other organic practices to support farmer learning.

To kickstart seed support under the programme, buckwheat seeds were distributed to several clusters — including four in Shergaon, one each in Jigaon and Membachur, and four more in Rupa and Thongre.

Officials from NECTAR, including Rajesh Kumar Samah (Chief Coordinator), Dr. Prab-

hat Borpuzari (Regional Officer), Pranjal Saikia (MIS Coordinator), Dharmendra Kumar Jha (Senior Analyst), and Bipul Sinha (Junior Analyst), attended the distribution programme and interacted with the trainers.

The project is part of a larger goal to develop 250 organic-certified clusters and train 25,000 farmers across the Northeast. In Arunachal Pradesh, demonstration farm labs and training centres are also being set up to offer hands-on experience in sustainable farming.



**Correspondent** men highlighting strong banana cultivation practices for the extraction of banana

The initiative under PM-DevINE aims to empower farmers, bridge technological gaps in rural areas, and foster inclusive development across the North Eastern region.

The initiative highlights the growing importance of drone technology in boosting agricultural productivity and enhancing modern security systems, thereby preparing students for future careers in these evolving sectors.

## 91



and connections. ... an earlier memorandum dated December 14, 2023. ... level continues to rise, the ducks and chickens.

## Drone Technology Training Programme held in Tamulpur

A CORRESPONDENT

**GORESWAR, May 31:** A Drone Technology Training Programme was conducted at Tamulpur Higher Secondary School on Friday by Yuvaan Educative LLP, in collaboration with the North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR).

The initiative aimed to empower students of classes 9 to 12, pursuing vocational education in elective subjects such as "Agriculture" and "Private Security," under the centrally sponsored scheme aligned with the National Skill Qualification Framework (NSQF), implemented by Samagra Shiksha, Government of Assam.

The training programme was inaugurated by Jahirul Islam, Inspector of Schools, Baksa district. In his inaugural address, he emphasized the importance of integrating advanced technologies into vocational education to align with modern industry demands and improve students' livelihood opportunities.

The technical session was led by Satyam Tripathy, Senior Geomatics Officer of NECTAR, who provided comprehensive insights into drone technology and its applications in agriculture—such as crop monitoring and spraying—as well as in security for surveillance and reconnaissance.

The training combined theoretical sessions with live demon-

strations, giving students hands-on experience with this cutting-edge technology. Students appreciated the practical approach, recognizing the importance of blending classroom learning with real-world applications.

This programme is part of Yuvaan Educative LLP's broader mission to equip students in Assam's government schools with industry-relevant skills and exposure to emerging technologies.

The initiative highlights the growing importance of drone technology in boosting agricultural productivity and enhancing modern security systems, thereby preparing students for future careers in these evolving sectors.



**CFC for banana fibre extraction inaugurated at Chumoukedima**

implemented by IEA with offer livelihood solutions to through banana waste to numerous farmers and rural communities in the vicinity of the plant and the state and abroad that it is the first of its kind in the North East region.

IEA, CEO, Neichute Doulo, thanked NECTAR for setting up the CFC and praised Dr. Arun Kumar Sarma's leadership for driving key initiatives in the region. He also thanked chief minister Dr. Nipphui Riu for his NagaKi City vision, mentioning that CFC was the first factory under this framework. He believed the area would grow into an economic hub and shared that IEA had begun coordinating with nearby villages for raw material sourcing and production linkages.

Dignitaries who also spoke at the meeting included Dr. M. Chuba Ao, Professor, Nagaland University, Dr. Akali Sema, and former minister.

During the program, NECTAR also provided the farmers with training materials and the Vasundhara Soil Organic Testing Kits. Around 200 farmers from around the state attended the event.

**Dignitaries felicitated at the inaugural programme.**

**DIMA PUR:** Common Facility Centre (CFC) for Banana Fibre Extraction at Chumoukedima supported by NECTAR - North East Centre for Technology Application and Reach with The Entrepreneurs Associates (IEA) as the implementing agency was inaugurated on June 11 at Chumoukedima.

The inaugural was graced by secretary, ministry of DoNER, Chanchal Kumar, as chief guest and chairman of MARCOFED, Dr. M. Chuba Ao as guest of honour.

Officials from NECTAR, led by director general Dr. Arun Kumar Sarma, attended the inauguration ceremony.

Speaking at the program, Chanchal Kumar expressed his excitement at the CFC launch, saying it would inspire many more such projects in the region. He highlighted that under PM DevINE, several initiatives are underway for regional development. He said that the CFC will strengthen both the state and the region's resilience.

Dr. Sarma highlighted the government of India's plans under the Ministry of DoNER to support farmers by turning waste into wealth. He informed that CFC, implemented by IEA with offer livelihood solutions to through banana waste to numerous farmers and rural communities in the vicinity of the plant and the state and abroad that it is the first of its kind in the North East region.

IEA, CEO, Neichute Doulo, thanked NECTAR for setting up the CFC and praised Dr. Arun Kumar Sarma's leadership for driving key initiatives in the region. He also thanked chief minister Dr. Nipphui Riu for his NagaKi City vision, mentioning that CFC was the first factory under this framework. He believed the area would grow into an economic hub and shared that IEA had begun coordinating with nearby villages for raw material sourcing and production linkages.

Dignitaries who also spoke at the meeting included Dr. M. Chuba Ao, Professor, Nagaland University, Dr. Akali Sema, and former minister.

During the program, NECTAR also provided the farmers with training materials and the Vasundhara Soil Organic Testing Kits. Around 200 farmers from around the state attended the event.

**India's immense progress towards becoming a semiconductor hub; market size reached ₹4+ lakh crore in 2024**

**Optical Fibre Cable length reached 42+ lakh route KM; 2.14 lakh Gram**

## NECTAR launches new initiative in East and West Kameng



**EAST KAMENG, Jun 6:** A major initiative to promote scientific organic farming has been launched in Arunachal Pradesh's East Kameng and West Kameng districts. The North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), an autonomous body under the Department of Science and Technology, is implementing the project under the PM-DevINE scheme funded by the Ministry of Development of North Eastern Region (MDONER).

The project aims to

support 1,500 farmers across 15 selected clusters in the two districts. The focus is on building farmer capacity, providing organic certification, setting up demonstration farms, creating community seed banks, and using digital tools like drones to monitor crop health and farm activities.

As part of the launch, 15 smartphones were distributed to Master Trainers in East and West Kameng. These devices will help them collect real-time data from the fields and communicate directly

with experts and farmers. Trainers also received educational materials covering topics like composting, pest control, and other organic practices to support farmer learning.

To kickstart seed support under the programme, buckwheat seeds were distributed to several clusters—including four in Shergaon, one each in Jigaon and Membachur, and four more in Rupa and Thongre.

Officials from NECTAR, including Rakesh Kumar Samra (Chief Coordinator), Dr. Prab-

hat Borpurzi (Regional Officer), Pranjal Saikia (MIS Coordinator), Dharmendra Kumar Jha (Senior Analyst), and Bipul Sinha (Junior Analyst), attended the distribution programme and interacted with the trainers.

The project is part of a larger goal to develop 250 organic-certified clusters and train 25,000 farmers across the Northeast. In Arunachal Pradesh, demonstration farm labs and training centres are also being set up to offer hands-on experience in sustainable farming.

## NECTAR launches organic agriculture project in Arunachal under PM-DevINE scheme

PM-DevINE Organic Scheme aims to create a robust organic farming ecosystem



**ITANAGAR:** A significant step towards advancing organic agriculture in Arunachal Pradesh, the North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), an autonomous body under the Department of Science and Technology, Government of India, has initiated key interventions under the project "Promoting Scientific Organic Agriculture in the North East Region."

Facilitated by the Ministry of Development of North Eastern Region (MDONER) under the PM-DevINE

scheme, the project is being implemented in 15 clusters across East Kameng and West Kameng districts. The PM-DevINE Organic scheme aims to create a robust organic farming ecosystem throughout the Northeastern states by focusing on farmer training and capacity building, facilitating organic certification, establishing demonstration farm labs at the cluster level, developing community seed banks, and creating a digital architecture using modern technologies such as UAVs.

The digital system will integrate key components such as farmers' details, yield, soil characteristics, and more for data-driven decision-

making. It also emphasizes market linkage of organic produce through e-marketing platforms and dedicated organic outlets. The scheme envisages the establishment of 250 organic-certified clusters, each guided by a Master Trainer and involving 100 trainee farmers. The overall goal is to train 25,000 farmers across the Northeast, ensuring their produce is certified and connected to viable markets. The state-wise distribution of these clusters is as follows: Assam (75), Meghalaya (25), Tripura (20), Mizoram (20), Nagaland (20), Manipur (15), and Arunachal Pradesh (15).

In Arunachal Pradesh, the project targets 1,500 farmers across 15 clusters. The focus areas include scientific capacity building, land certification under the Participatory Guarantee System (PGS), and digital monitoring of progress.

To enhance field coordination and digital data management, 15 smartphones were distributed to Master Trainers in East and West Kameng districts. These devices will be used to track farming activities, collect field-level data, and ensure efficient communication among trainers, farmers, and agricultural experts to address on-ground challenges effectively.

Additionally, Master Trainers received training materials to support farmer education sessions within the clusters.

These materials include modules on organic practices, composting techniques, and natural pest management—designed to strengthen grassroots knowledge on sustainable farming practices.

As part of the seed support initiative, buckwheat seeds were distributed in several clusters: four clusters in Shergaon, one in Jigaon, one in Membachur, and four clusters in Rupa and Thongre.

The distribution ceremony was graced by several senior NECTAR officials, including Shri. Rakesh Kumar Samra (Chief Coordinator, Technology), Shri. Prabhat Borpurzi (Regional Officer), Shri. Pranjal Saikia (MIS Coordinator), Shri. Dharmendra Kumar Jha (Senior Analyst), and Shri. Bipul Sinha (Junior Analyst).



# Common facility centre under PM-DeVINE scheme opened in Nagaland

HT Correspondent

DIMA PUR, June 11: The North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), an autonomous institute under the Union science and technology department, inaugurated a Common Facility Centre (CFC) for banana fibre extraction at New Chumoukedima village under Chumoukedima district on Wednesday.

The centre aims to promote sustainable livelihoods, skill development, and value addition through efficient utilisation of agricultural wastes.

The facility has been established under the ministry of DoNER's PM-DeVINE scheme as part of the 'NECTAR Livelihood Improvement Project - A Value Chain on Utilisation of Banana Pseudostem for Value-Added Products'.

Chanchal Kumar, secretary, Ministry of DoNER, attended the opening ceremony as the chief guest.

A key highlight of the event was the formal launch of an organic biofertilizer derived from banana pseudostem sap - a product developed under the same project to provide eco-friendly fertiliser alternatives for farming communities.

This initiative not only promotes circular economy but also directly supports soil health and sustainable agriculture practices in the region.

In his presentation, Arun Kumar Sarma, director general, NECTAR, showcased the broader objectives of the PM-DeVINE project and NECTAR's portfolio of livelihood-oriented technological interventions across Northeast.

He highlighted how this specific project addresses a critical gap in agricultural waste management by converting banana pseudostem - typically discarded as waste into different useful and marketable products, including natural fibre, biodegradable sheets, and hand-made paper.

He emphasised that this model offers both environmental and economic benefits and can be replicated across other regions and crops with similar challenges.

Another important milestone marked during the ceremony was the signing of a MoU between NECTAR and The Entrepreneurs' Associate (IEA) based in Naga-

land, formalising their collaboration for implementation and operation of the common facility centre.

The programme also includes distribution of training material and Visundhara soil organic testing kits to beneficiary farmer from Nagaland.

**REPAIRS TO RAILWAY HOSPITAL**

**E-Tender Notice No.: LMG/Engg/46 of 2025 Dated: 06-06-2025.** E-Tenders are invited by the undersigned for the following works:

**Name of work:** Repairs to Railway Hospital outdoor unit, blood bank unit, X-Rayroom, Auditorium and Other miscellaneous work & repair to pipe lines including provision of alternative connection to the newly constructed Quarters in the jurisdiction of ADEN/IV/Lumding. **Tender Value:** ₹1,80,87,306.44/- **Earnest Money:** ₹2,40,400/- **Date & Time of closing of E-Tenders:** 15:00 hrs. of 03-07-2025 & opened at 15:00 hrs. of 04-07-2025. The complete information with the tender documents of above e-tender will be available upto 15:00 hrs. of 03-07-2025 in the website [www.meps.gov.in](http://www.meps.gov.in)

**CPWM (W), Lumding**  
**NORTHEAST FRONTIER RAILWAY**  
Bokakhat, Assam

The Shillong Times

English

# The Shillong Times

ESTABLISHED 1945

MEGHALAYA | News Alert

## NECTAR conducts workshop on STEM for teachers

By: By Our Reporter September 23, 2024

Shillong, Sept 23: As a precursor to the North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR) larger initiative, the establishment of a STEM Hub in Shillong, which aims to provide a collaborative space for students, teachers, and researchers to work together in addressing education challenges, the NECTAR on Monday conducted a one-day workshop on STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) for teachers.

The workshop, held in collaboration with the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune, and Smart Village Movement (SVM), Meghalaya, was held at St. Edmund's College, Shillong.

The event, titled "Mobilising Science and Technology-Based Learning for Schools," saw the participation of 100 teachers from Shillong and nearby areas. The goal was to bridge the gap between urban and rural education by promoting inquiry-based learning and hands-on approaches in STEM education.

The workshop introduced teachers to innovative pedagogical techniques, including hands-on mathematics, interactive science projects, and app-based simulations.

Swapnil Tembe, IAS, Additional Secretary of the Education Department and Director of School Education & Literacy, attended the event as the chief guest. Other notable attendees included Dr. Collin Z. Renthlei, Technical Advisor, NECTAR, and Dr. Chaitanya Mungi, Project Coordinator, STEM Ready, IISER Pune, along with experts from NECTAR, IISER, and SVM.

## EastMojo

Assam

## Assam: College-level drone training launched for the first time

This initiative aims to equip individuals from North-East India, particularly Assam, with skills to meet 21st-century demands

by Team EastMojo  
June 26, 2024



Assam food delivery | Northeast India travel experiences

## Plasma Technology For Entrepreneurship Concluded By NECTAR In Collaboration With AIC

12 mins · 27 AUG 16, 2024

Image 1/24



North East center for Technology Application and Reach conducted a one day awareness programme on 6th August 2024 for students and startups on plasma Technologies for Entrepreneurship in collaboration with AIC-IPR plasmatech innov Foundation IPR Gandhinagar (An Atal incubation center of Institute of Technology (NT) Meghalaya in Shillong) A total of 80 participants including students Faculties and Entrepreneurs had participated in the awareness programme.

The programme was graced by prof Pinakeswar Mahanta Director of NIT Meghalaya, Dr Arun Kumar Sarma, Director General of NECTAR and Dr Niraj Jamnappara, Head AIC-IPR sonapur. The program enlighten the opportunities and prospects of using plasma Technique for successful technology based enterprise. It coverage topics related to plasma technology and case studies on how patenting could help them safeguard innovations. The access to plasma Technology and applications in the North East region was also elaborately discussed.

**Government of India**  
**Press Information Bureau**

About Us · Press Releases · Gallery · Explaners · Media Facilitation · Archives · Fact Check Unit

Home · All Press Release · Press Releases Details

All Ministry

28 July 2025

**Prime Minister's Office**

- Chief Minister of Assam meets Prime Minister

**Ministry of Coal**

- Enhancement of Coal Production
- Critical Minerals in Coal Mine Waste and Coal Ash
- Revised SHAKTI Policy

**Ministry of Communications**

- Union Minister Shri Jyoti Basu M. Scindia Reviews ESNL's Performance, Emphasizes Customer Experience and Revenue Generation

**Ministry of Heavy Industries**

- The Ministry of Heavy Industries organizes a Special Lecture Session to commemorate the 125th Birth Anniversary of Dr. Syama Prasad Mukherjee

**Ministry of Science & Technology**

**75 Azadi Ka Amrit Mahotsav**

**Bioplastics from cassava boosting local economy in Nagaland**

Posted On 24 JUL 2024 3:43PM by PIB Delhi

Small holder farmers from 19 villages in Mokochung district of Nagaland are setting an example in replacing plastics with compostable bioplastic bags made from Cassava starch.

Efforts of the Government to ban single use plastic has made limited impact mainly due to lack of alternative lightweight materials that can replace the widely used plastics.

In order to address this challenge North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR) has supported an initiative to manufacture Compostable Bioplastics Bag from Cassava Starch (Manihot esculenta).

Ecostarch, a Nagaland based MSME, has set up a facility to manufacture bioplastic bags from Cassava plant in Mokochung, Nagaland and is mobilizing farmers within 10-40 km range of the production facility to take up Cassava farming. The farmers have already started with the plantation of materials and in about a year it will be ready for harvest.

**NorthEast** · India Today · Aaj Tak · GNTV · Laitumop · Business Today · Bangla · Malayalam · BT Bazaar · Harper's Bazaar

Search Here...

News / Lifestyle / NECTAR and AIC-IPR Plasmatech host awareness programme on Plasma Technologies for Entrepreneurship at Cotton University

**NECTAR and AIC-IPR Plasmatech host awareness programme on Plasma Technologies for Entrepreneurship at Cotton University**

North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR) recently conducted a one-day awareness programme for students and startups on "Plasma Technologies for Entrepreneurship" in collaboration with AIC - IPR Plasmatech Innovation Foundation, IPR, Gandhinagar (An Atal Incubation Centre of Institute for Plasma Research, DAE, supported by AIM-NITI Aayog Sudmerson Hall, Cotton University, Guwahati. A total of 60 participants including Students, Faculties and Entrepreneurs had participated in the awareness programme.

ADVERTISEMENT

**India TodayNE**  
Aug 08, 2024  
Updated Aug 08, 2024, 11:12 PM IST

North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR) recently conducted a one-day awareness programme for students and startups on "Plasma Technologies for Entrepreneurship" in collaboration with AIC - IPR Plasmatech Innovation Foundation, IPR, Gandhinagar (An Atal Incubation Centre of Institute for Plasma Research, DAE, supported by AIM-NITI Aayog Sudmerson Hall, Cotton University, Guwahati. A total of 60 participants including Students, Faculties and Entrepreneurs had participated in the awareness programme.

The program was graced by Prof. Ramesh Chandra Deka, Vice Chancellor of Cotton University; Dr Arun Kumar Sarma, Director General of NECTAR and Dr. Nirav Jamnappara, Head, AIC - IPR Plasmatech Innovation along with other officials and experts from NECTAR, and CPP-IPR, Sonapur.



**The Interview World**

ACQUISITION | 5 min read

## NECTAR: Transmuting North East into a Hub of Economic Marvel

YIW | August 29, 2024



The **North East Center for Technology Application and Reach (NECTAR)**, an autonomous society under the Department of Science & Technology, Government of India, is headquartered in Shillong, Meghalaya. The Centre is dedicated to harnessing and leveraging advanced frontier technologies from central scientific departments and institutions.

NECTAR's mission is to lead the way in fostering, nurturing, and delivering sustainable technology applications for public and social good. The organization aims to extend the benefits of technology to people, communities, institutions, and governments, thereby promoting equitable and inclusive social and economic development in the North Eastern Region of India.

In an exclusive conversation with **The Interview World** at the **STTA Global Education Conference**, hosted by the **Seth Anandram Jaiswal Group of Educational Institutions**, Dr. Anur Kumar Samra, Director General of NECTAR, highlighted the organization's core mandate. He outlined key programs aimed at driving economic development in the North East, emphasized NECTAR's role in improving the economic conditions and livelihoods of the region's people, and provided insights into capacity-building initiatives. Here are the key takeaways from his enlightening interview.

Education

## Inauguration of "STEM Education Lab" and "Vasundhara Soil Organic Carbon Detection Laboratory cum Manufacturing Unit"

North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), an autonomous institute under the department of Science and Technology, Government of India, inaugurated the following two programs jointly at NECTAR Headquarters in Shillong

Deepak Verma • January 31, 2025 • 312 • 1 minute read



EXERCISE DRONE PRAHAAR- INDIAN ARMY DEMON

News / Meghalaya / Meghalaya: STEM lab, soil testing facility launched to advance education and sustainable farming

## Meghalaya: STEM lab, soil testing facility launched to advance education and sustainable farming

NECTAR in Meghalaya has launched initiatives to boost STEM education and organic farming. The STEM Lab and soil testing kits aim to empower students and farmers.

ADVERTISEMENT

**India Today NE**  
Jan 31, 2025,  
Updated Jan 31, 2025, 5:15 PM IST

Meghalaya's North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), under the Department of Science and Technology, Government of India, jointly inaugurated two programmes at the NECTAR Headquarters, in Shillong, aiming to enhance education and agriculture in the region.

A transformative 'STEM Education Lab' has been established to empower students with hands-on learning in science and technology, while a 'Mini Laboratory' for soil testing kits supports sustainable organic farming across Northeast under the PM-DevINE project.

The STEM Lab developed in NECTAR Headquarters, in collaboration with the Smart Village Movement (SVM), Meghalaya, Curiosity Gym, Mumbai and Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune marks a transformative step towards advancing STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) education in Meghalaya. It aims to create a holistic environment to empower students from around 100 schools in Shillong with STEM components like Electronics, Robotics, 3D printing, among others.

**The Shillong Times**

English

# The Shillong Times

ESTABLISHED 1945

MEGHALAYA | News Alert

## STEM Education Hub to benefit farmers, students: Wahlang

By: By Our Reporter January 31, 2025

Shillong, Jan 31: State Chief Secretary DP Wahlang on Friday inaugurated STEM Education Hub and Soil Organic Carbon Detection lab at NECTAR office, Survey of India campus.

He said that these initiatives one for helping the farmers and the other the students will immensely benefit the State.

Talking about the STEM Education lab, he said Class 9 students are learning coding which is path breaking as usually coding is at under graduate level and they are developing robotics state-of-the-art technology here at the school level.

Stating that this will ensure that the students will go to a different level altogether, he said the project director has been asked to ensure that the STEM lab is spread across hundreds of schools so that the students will benefit.

On Soil Organic Carbon Detection lab, he said checking the carbon contents of the soil will be very helpful to all the farmers in the State.

Pointing out that this is the first initiative from file to field, he said, "This is very important that we have to take this transformation and make sure that the farmers not only see during the capacity building programmes and trainings but also see what is happening in the field".

"It is very important to know and map the soil content what is there how much nutrients, carbon, the content of the soil of which crop," he added.

Meanwhile, Founding member and CEO of Curiosity Gym who is partnering with NECTAR, Girish Nair informed that the when the whole world is moving technology, this effort is to provide access to school students especially in rural and semi urban areas to have this activity based learning and they are doing that through STEM Education hub lab.

According to him, this initiative is to help spread science and technology learning across the State.

He informed that currently they are working with two schools and they want to expand to another 20 schools for which the identification process is underway.

The inaugural courses are being provided free of cost for those schools who have registered with NECTAR. There will also be workshops organised for the schools.







# Hub news

NEWS INNOVATION

## Shillong teachers given a crash course in advanced Science, Technology & Maths Skills

By Hub Network September 23, 2024 0 1436



Shillong, Sept 23: The North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR), in collaboration with the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune and Smart Village Movement (SVM), Meghalaya, recently organized a one-day workshop titled "STEM – Mobilising Science and Technology-Based Learning for Schools."

Held at St. Edmund's College in Shillong, the workshop aimed to equip educators with innovative teaching techniques in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).

A total of 100 teachers from schools in Shillong and surrounding areas participated in the event, which focused on fostering inquiry-based learning, creativity, and curiosity among students.



1 Aug 27°C 2 Aug 27°C 3 Aug 26°C Imphal 28 Jul 25°C

## Meghalaya: Foundation Stone Laid For NECTAR's Permanent Campus In Shillong

BNE News Desk, March 13, 2025



Technology Northeast Meghalaya Top Stories

Spread the love

Shillong: The [North East Centre for Technology Application and Reach \(NECTAR\)](#), an autonomous institute under the [Department of Science and Technology \(DST\)](#), Government of India, has officially laid the foundation stone for its permanent campus at Umsawl, Shillong, Meghalaya.

The ceremony was graced by Union Minister of State (Independent Charge) for the Ministry of Science & Technology and Earth Sciences, as well as Minister of State in the Prime Minister's Office, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Atomic Energy, and Department of Space, Arun Kumar Samma, Director General of NECTAR, along with senior officials from NECTAR, DST, and various state and central government organisations also attended the event.

This milestone marks a significant step in NECTAR's commitment to fostering innovation, technological advancement, and sustainable development in Northeast India. The construction of the new NECTAR office is expected to be completed within two to three years, with operations set to commence soon after.

ALSO READ: [Unlocking Export Potential Of Coconut In Assam: CDR Official Shares Insights](#)

The initiative aligns with NECTAR's vision to become a leading centre for technology application and outreach, ensuring the delivery, sustainability, and widespread use of technology for public and social good. The centre aims to bridge technological gaps by benefiting communities, institutions, and governments, contributing to the equitable and inclusive socio-economic development of the Northeast.

← [India's Retail Inflation Drops To Seven-Month Low In February](#)

[Priva Hair appointed as HUL RM and CEO](#) →

Related News



Ministry of Science & Technology

## Northeast to Become India's Next Saffron Hub, NECTAR to Lead Agri-Tech Revolution: Dr. Jitendra Singh

NECTAR's New Campus to Boost Innovation as Union Minister Calls for Northeast's Tech-Driven Growth

Dr. Jitendra Singh Lays Foundation Stone for NECTAR Permanent Campus, Highlights Northeast's Transformational Growth

Posted On: 13 MAR 2025 5:31PM by PIB Delhi

Union Minister of State (Independent Charge) for Science and Technology, Earth Sciences and Minister of State for PMO, Department of Atomic Energy, Department of Space, Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said here today that Mission Saffron initiative, which since 2021 has expanded saffron cultivation across Sikkim, Arunachal Pradesh, and Meghalaya. Large-scale cultivation is now underway in Menchukha (Arunachal Pradesh) and Yaksom (Sikkim), with plans to extend to Nagaland and Manipur, making the Northeast India's next saffron hub after Jammu and Kashmir's Pampore. The initiative strategically utilizes uncultivated land, enhancing agricultural potential without disrupting existing crops.

The Minister highlighted the government's ambitious plans to turn the Northeast into India's next saffron hub, as he laid the foundation stone for the new permanent campus of the North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR) in Shillong. He emphasized that the region's rapid transformation under Prime Minister Narendra Modi's leadership has opened new opportunities for technological and agricultural advancements.



Ministry of Science &amp; Technology

## A DST institute, NECTAR showcases Innovative Aerostatic Drone for Enhanced Surveillance and Disaster Management

Posted On: 22 APR 2025 3:54PM by PIB Delhi

Forest surveillance, wildlife monitoring, border and disaster surveillance in the North East, may soon be much easier -- thanks to the Aerostatic Drone developed with support from North East Centre for Technology Application and Reach (NECTAR).

NECTAR, an autonomous body under Department of Science and Technology, Government of India organized a live demonstration of the technology developed by Airbotix Technologies, Gurgaon.

It is the first of its kind in India, designed with high endurance and aero-statically stable capabilities to deploy for forest surveillance, wildlife monitoring, border and disaster surveillance application. Aerostatic drones are aerial platforms that derive their lift from both buoyancy and aerodynamics.

This makes them very energy efficient making them a better alternative for tethered drones. Aerostatic drones are silent as they do not require constant thrust to stay afloat, making them cost-effective and versatile solution for providing persistent surveillance.

The aerostatic drone provides a silent aerial platform that can persistently stay afloat for surveillance with an endurance of over 4 hours. The system is designed to be modular and could be integrated with any ground vehicle or can be installed at any site. The drone can be utilized for a variety of use cases such as wildlife monitoring, forest surveillance, crowd monitoring, border security and disaster surveillance to name a few.

The flexibility to equip the drone with both day and night camera as well as any other payload such as telecommunication relay and anti-drone payload. The Day and Night Vision Camera cameras further enhances its utility, especially in tracking monitoring forests for illegal activities such as poaching, smuggling and logging, as well as by providing support for security operations along borders.

Participants from various organizations interacted with Airbotix Technology about the drone's technical capabilities. The Drone has features related to surveillance using thermal imaging and detection capabilities.

Officials from the CRPF showing a keen interest in how the drone could enhance their operations, particularly in border surveillance and security in challenging terrains. The ability of the drone to operate in both daylight and low-visibility conditions using thermal cameras could be a significant asset for security personnel.



*Fig: Aerostatic Drone for Enhanced Surveillance and Disaster Management*

The drones could play a crucial role in monitoring forest health and wildlife populations, enabling conservationists to track animal movements and assess habitat conditions without disturbing the ecosystem as they are silent. In military and security contexts, aerostatic drones are employed for ISR missions, providing real-time data and situational awareness, which enhances strategic planning and operational effectiveness. Furthermore, as they have very little metal components, they are practically invisible to the RADAR.

Aerostatic drones can serve as temporary communication relays in remote areas or during emergencies, ensuring connectivity where traditional infrastructure may be lacking or compromised. Aerostatic drones can also be integrated into systems designed to detect unauthorized drone activity, enhancing security measures at sensitive locations such as airports and military bases.

During public events, these drones could assist law enforcement by monitoring crowd behavior, helping to ensure safety and manage potential disturbances effectively. Moreover, they can be utilized to monitor traffic conditions in urban areas, providing valuable data for traffic management systems and aiding in the reduction of congestion through real-time information dissemination.

The officials from Brahmaputra Board expressed their keenness to use the aerostatic drone for disaster management and for monitoring civil construction such as roads.

The Aerostatic Drone is expected to be a game-changer in its field, with its versatility and high-performance features setting a new standard for unmanned aerial vehicle technology in India.

\*\*\*

NKR/PSM

(Release ID: 2123451)

Read this release in: Urdu , Hindi , Tamil







**NECTAR** @NECTAR\_DST · Sep 17, 2024  
Swachhata Hi Seva (SHS) 2024 pledge taking ceremony at NECTAR Office, Guwahati Biotech Park.

#SwachhataHiSeva  
#SpecialCampaign4



DSTIndia and 2 others

31

**NECTAR** @NECTAR\_DST · Sep 27, 2024  
Distribution of "ATATA" (Aquatic Trash Avoiding Tool and Accessories) to sanitation workers by NECTAR, an autonomous body under DST, Gol, under the campaign #SwachhataHiSeva2024 #SpecialCampaign4



DSTIndia and 2 others

60

**NECTAR** @NECTAR\_DST · Sep 26, 2024  
Waste to Art Competition organized by NECTAR, an autonomous body under DST, Gol, in its headquarters under the campaign #SwachhataHiSeva2024 #SpecialCampaign4



DSTIndia and 2 others

24

**NECTAR** @NECTAR\_DST · Sep 25, 2024  
Awareness Rally organized by NECTAR, an autonomous body under DST, Gol, under the campaign #SwachhataHiSeva2024 #SpecialCampaign4



DSTIndia and 2 others

18

**NECTAR** @NECTAR\_DST · Sep 27, 2024  
Distribution of Safety Gears and Kits to Sanitation Workers of Shillong Municipal Board by NECTAR, an autonomous body under DST, Gol, under the campaign #SwachhataHiSeva2024 #SpecialCampaign4



DSTIndia and 2 others

30

**NECTAR** @NECTAR\_DST · Sep 24, 2024  
Mass scale cleanliness drive at NECTAR, an autonomous body under DST, Gol, under the campaign #SwachhataHiSeva2024 #SwachhataLakshitEkayi #SpecialCampaign4



DSTIndia and PMO India

24





NECTAR @NECTAR\_DST · Sep 24, 2024

NECTAR, an autonomous body under DST organized a One Day Workshop on "STEM Education for Teachers", in collaboration with IISER, Pune and Smart Village Movement, Meghalaya at St. Edmund's College, Shillong on 23rd Sep 2024. A total of 100 Teachers participated in the Workshop



DSTIndia and 4 others



89



NECTAR @NECTAR\_DST · Aug 14, 2024

NECTAR, an autonomous body under DST, GOI, conducted National Space Day, 2024 in collaboration with St. Anthony's College, Shillong. Activities like demonstration of Drones, Essay, Quiz and Poster competitions were held. More than 200 students participated in the event.



DSTIndia and 2 others



79



NECTAR @NECTAR\_DST · Sep 19, 2024

Preventive Health Checkup for Sanitation Workers under #swachhatahisevacampaign #SpecialCampaign4 #SafaiMitraSuraksha at NECTAR, an autonomous body under DST.



DSTIndia and 2 others



27



NECTAR @NECTAR\_DST · Dec 2, 2024

Inauguration of NECTAR Stall at India International Science Festival (IISF) 2024, in IIT Gh by Hon'ble Minister Shri Jitender Singh, Minister of Science and Technology & Minister of Earth Sciences; and Prof. Abhay Karandikar, Secretary, Department of Science and Technology, GOI.



Abhay Karandikar and 2 others



35



NECTAR @NECTAR\_DST · Jul 11, 2024

A groundbreaking 5 day Innovative Academic Research Connect & Immersion Program, was organized by Jio Institute in collaboration with NECTAR, from 1st to 5th July at the Jio Institute, Mumbai. This unique initiative brought together PhD & MSc students from diverse fields.



Dr Jitendra Singh and 2 others



39



NECTAR @NECTAR\_DST · Aug 5, 2024

Wahong 90.0 MHz Community Radio, a project supported by NECTAR, an autonomous body under DST, Govt of India, was inaugurated on 3rd August 2024 in Thoubal, Manipur



DSTIndia and 2 others



31





**NECTAR** @NECTAR\_DST · Aug 8, 2024

NECTAR, an autonomous body under DST, GOI, conducted a 1 day awareness program on 6th & 8th Aug 2024, on "Plasma Technologies for Entrepreneurship" in collaboration with AIC – IPR Plasmatech Innovation Foundation, IPR, Gandhinagar, NIT, Meghalaya & Cotton University, Guwahati.



DSTIndia and 2 others



760



**NECTAR** @NECTAR\_DST · Aug 5, 2024

NECTAR, an autonomous body under DST, Govt. of India, inaugurated its Manipur liaison office at the Manipur Khadi & Village Industries Board, Lamphelpat, Imphal on 3rd August 2024



DSTIndia and 2 others



22



**NECTAR** @NECTAR\_DST · Aug 1, 2024

NECTAR, an autonomous body under DST, Govt. of India conducted a 5 day Master Trainer Training Program from 26-30 July, 2024 on "Promoting Scientific Organic Agriculture for Northeastern states" under the PM-DevINE scheme in collaboration with Krishi Vigyan Kendra, West Kameng.



DSTIndia and 2 others



30



**NECTAR** @NECTAR\_DST · Aug 14, 2024

National Flags distributed to staffs in NECTAR, an autonomous body under DST, GOI on account of Har Ghar Tiranga Campaign.



PMO India and DSTIndia

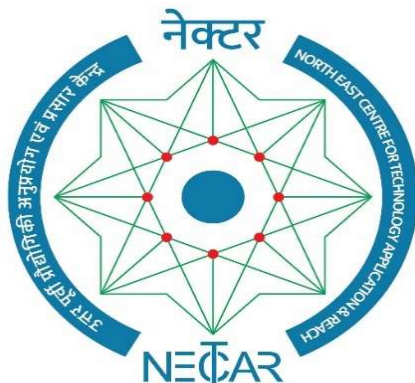


42





उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केन्द्र (NECTAR)  
मेघालय, शिलांग – 793001



लेखा परीक्षण प्रतिवेदन  
वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने पर

आर. एम. कोठारी एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

**96**, द्वितीय तल, जी.एन.बी. रोड, सिलपुखुरी, एस.बी.आई. ईवनिंग ब्रांच के पास,  
गुवाहाटी – **781003**

फोन नंबर: **+91 88225 53345**

ईमेल: **RMKCO.GHY@GMAIL.COM**



## आर. एम. कोठारी एंड कम्पनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

### स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,  
सदस्य,  
उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र  
(नेक्टर)

### वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (नेक्टर) ("संस्था के रूप में संदर्भित") के वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र, आय और व्यय का विवरण, समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्त एवं भुगतान खाता और वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ जिसमें लेखा नीतियों का महत्वपूर्ण सारांश भी शामिल है की लेखा परीक्षा की है।

### अभिमत का आधार

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों (एस ए एस) के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों को हमारे प्रतिवेदन में वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन के लिए उन मानकों के अंतर्गत लेखापरीक्षक की दायित्व खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम वित्तीय विवरणों के बारे में अपने लेखा परीक्षा के लिए अपेक्षित आचार नीति के साथ - साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप इस केंद्र से स्वतंत्र (संबंधित नहीं) हैं, और इन अपेक्षाओं के अनुरूप हमने अपने अन्य नैतिक दायित्वों का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा के लिए हमने जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### वित्तीय विवरणों के मामले में प्रबंधन का दायित्व

प्रबंधन का दायित्व है कि सोसायटी द्वारा अपने उपनियम (उपविधि) के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करवाए, जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सोसायटी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन के बारे में सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस दायित्व में सोसायटी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कानून के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग, तर्कसंगत एवं और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान तैयार करना; तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित किए जा रहे हों, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए सुसंगत हो तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण सूचना की गलत प्रस्तुति से मुक्त हों।

### वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा दायित्व, अपने लेखापरीक्षण में इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत देना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों से यह अपेक्षा की जाती है कि हम इन वित्तीय विवरणों की सामग्री की यथार्थता के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का आयोजन करें और इसे निष्पादित करें ताकि वित्तीय विवरण समग्र रूप में सूचना की गलत प्रस्तुति से मुक्त हों।

एक लेखापरीक्षा में राशियाँ और वित्तीय विवरण में दर्शाए गए तथ्यों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें किसी जालसाजी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की सामग्री संबंधित गलत बयानी जो खतरे का मूल्यांकन भी शामिल होता है। इन खतरों के



मूल्यांकन के लिए लेखापरीक्षक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है जो कि सोसाइटी द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित हों ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन किया जा सके जो कि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों लेकिन यह इकाई आंतरिक नियंत्रण के प्रभाव पर अपनी राय देने के उद्देश्य से ना हों। एक लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखानीतियों की उपयुक्तता के मूल्यांकन के साथ - साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं और हमें अपनी लेखापरीक्षा पर अभिमत देने का आधार प्रदान करते हैं।

### अभिमत

इस रिपोर्ट के अनुलग्नक -1 के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।
- ख) हमारा अभिमत है, सोसायटी द्वारा लेखा पुस्तकों को विधि के अनुसार उचित रूप से बनाए रखा गया है।
- ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा बहियों के अनुरूप हैं ।
- घ) हमारे विचार में, हमें दी गई जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त लेखा, अनुसूचियाँ तथा उन पर की गई टिप्पणियाँ सही एवं निष्पक्ष स्थिति को प्रदर्शित करते हैं :-
  - i. तुलन-पत्र के संबंध में, सोसायटी के कार्यों के लिए 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति; तथा
  - ii. आय एवं व्यय खाते के संबंध में, इसी तिथि को समाप्त लेखांकन वर्ष के लिए आय से अधिक व्यय

**आर. एम. कोठारी एंड कम्पनी**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या:000143C

हस्ता /-

**(सीए हर्ष अग्रवाल)**

साझीदार (Partner)

सदस्यता संख्या: 315605

यूडीआईएन: 25315605BMKREZ6056

स्थान : गुवाहाटी

दिनांक : 14.06.2025

लेखा परीक्षा विश्लेषण - अनुलग्नक -1**1. बैलेंस पुष्टि की अनुपलब्धता:**

लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 31/03/2025 तक देनदारों, लेनदारों तथा टीडीए ऋण बकाया से संबंधित पक्षों से कोई भी बैलेंस पुष्टि प्राप्त नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ऐसे सभी खातों के बैलेंस अपुष्ट एवं अप्रत्ययित बने हुए हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में यह भी देखा गया है कि संस्था ने संबंधित पक्षों के विरुद्ध पहले ही कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

**2. टीडीए बकाया के विरुद्ध कानूनी स्थिति:**

लेखा परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि विभिन्न टीडीए ऋण मध्यस्थत एवं अन्य कानूनी प्रक्रिया में लंबित हैं। संस्था को आवश्यक कदम उठाकर इन्हें यथाशीघ्र सुलझाना चाहिए। 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कुल 75 मामले कानूनी कार्यवाही में हैं, जिनमें से 30 मामले मध्यस्थता में तथा अन्य 45 मामले धारा 138 के अंतर्गत लंबित हैं।

**3. लंबे समय से पड़ी हुई इन्वेंट्री बिना NRV आकलन के:**

यह देखा गया कि ₹28,74,229.27 की इन्वेंट्री लंबे समय से स्टॉक में पड़ी हुई है। तथापि, प्रबंधन द्वारा 31/03/2025 तक इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू (NRV) का आकलन नहीं किया गया। NRV मूल्यांकन के अभाव में यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि इन्वेंट्री को लागत या NRV में से जो भी कम हो, उस पर प्रदर्शित किया गया है या नहीं, जैसा कि लागू लेखा मानकों (AS-2 आदि) के अंतर्गत अपेक्षित है। यदि वास्तविक प्राप्ति मूल्य वहन मूल्य से कम है, तो इससे वित्तीय विवरणों में इन्वेंट्री और लाभप्रदता का अधिक आकलन हो सकता है।

**4. GST प्रावधानों का अनुपालन न होना - TDS Deductor के रूप में पंजीकरण न कराना:**

लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संस्था ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) की धारा 51 के अंतर्गत पंजीकरण नहीं कराया है, जो उन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है जिन्हें GST के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती (TDS) करनी होती है। एक deductor के रूप में संस्था पर यह दायित्व था कि वह निर्धारित सीमा से अधिक कर योग्य आपूर्ति पर TDS काटे और उसे नियत समय सीमा के भीतर सरकार के पास जमा करे।

GST के अंतर्गत TDS Deductor के रूप में पंजीकरण न कराना एवं संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न करना वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन है। इसके कारण संस्था पर ब्याज, जुर्माना और अन्य कानूनी परिणाम लागू हो सकते हैं, साथ ही यह संस्था की वैधानिक जिम्मेदारियों और विक्रेता अनुपालन को प्रभावित कर सकता है।

**5. लेखा परीक्षण के दौरान TDS में अनियमितताएँ:**

**TDS डिफॉल्ट:** वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित ₹79,510/- का TDS भुगतान लंबित/अदत्त है।

**6. वित्तीय वर्ष 2025-25 हेतु प्रोफेशनल टैक्स (PT) की आंशिक कटौती एवं अप्रमाणित भुगतान:**

लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-25 के लिए कर्मचारियों से आंशिक रूप से प्रोफेशनल टैक्स (PT) काटा गया है, किंतु इसे अब तक संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकरण के पास जमा नहीं किया गया है।

**7. मेघालय सरकार से भूमि आवंटन/लीज़ की स्थिति को लेकर अनिश्चितता:**

लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संस्था को उपयोग हेतु मेघालय सरकार द्वारा एक भू-खंड उपलब्ध कराया गया है। किंतु संस्था यह पुष्टि करने में असमर्थ रही कि यह भूमि औपचारिक रूप से आवंटित की गई है या लीज़ पर दी गई है। साथ ही, इसकी पुष्टि हेतु कोई सहायक दस्तावेज़ जैसे आवंटन पत्र, लीज़ अनुबंध या स्वामित्व पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया।

**8. चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत लंबे समय से लंबित शेष राशि:**

चालू परिसंपत्तियों की अनुसूची के परीक्षण के दौरान ₹48,61,091/- की ऐसी कई शेष राशियाँ पहचानी गईं जो लंबे समय से स्थिर हैं अथवा समायोजित नहीं की गई हैं।

**9. वित्तीय वर्ष 2025-25 में कार्यकारी परिषद (EC) एवं वित्त समिति (FC) की बैठक आवश्यकताओं का अनुपालन न होना:**

संस्था के प्रशासनिक ढाँचे के अनुसार:



- कार्यकारी परिषद (EC) की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार, अर्थात् वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाना अनिवार्य है।
- वित्त समिति (FC) की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित की जानी आवश्यक है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2025-25 में केवल एक EC बैठक और एक FC बैठक ही आयोजित की गई, वह भी 31.07.2025 को।

10. वित्तीय वर्ष 2021-22 (06.08.2021 से प्रभावी) के दौरान, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय, डीसी (हस्तशिल्प) श्री शांतमनु द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा नेक्टर के बीच एक अनुबंध संपादित किया गया, जिसके माध्यम से बाँस एवं बेंत विकास संस्थान (BCDI) का परिचालन एवं प्रबंधन नियंत्रण नेक्टर को सौंपा गया। इसका उद्देश्य त्रिपुरा, पूर्वोत्तर तथा भारत के अन्य भागों में विविध प्रकार की आजीविका को समर्थन देने हेतु बाँस प्रौद्योगिकी के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करना था। यह प्रावधान प्रारंभिक रूप से तीन वर्षों की अवधि के लिए किया गया, जिसे आगे बढ़ाकर अगले तीन वर्षों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया।

बीसीडीआई का परिचालन एवं प्रबंधन नियंत्रण प्राप्त करने के बाद, नेक्टर ने इसकी गतिविधियों को एक परियोजना के रूप में प्रारंभ किया। दिनांक 31.03.2025 एवं 31.03.2025 की स्थिति तक इसकी वित्तीय संक्षिप्त जानकारी नीचे प्रस्तुत की गई है तथा उसे नेक्टर के वित्तीय विवरणों में विधिवत् सम्मिलित किया गया है।

राशि लाख रु. में

विशिष्ट	चालू वर्ष 31.03.2025	विगत वर्ष 31.03.2025
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्राप्त कुल अनुदान	87.93	105.67
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए खर्च की गई कुल राशि	89.49	101.89
<b>अधिशेष</b>	<b>(1.56)</b>	<b>3.78</b>
कॉर्पस/पूँजीगत निधि	164.87	164.87
वर्तमान देयताएं	11.53	33.85
<b>कुल</b>	<b>176.40</b>	<b>198.72</b>
नकद और बैंक शेष	72.72	97.18
अन्य संपत्तियां एफ/ए एवं सीए	103.68	101.54
<b>कुल</b>	<b>176.40</b>	<b>198.72</b>

उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र  
लेखा परीक्षा टिप्पणियों के जवाब “अनुलग्नक -1”

लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर बिंदुवार उत्तर नीचे दिए गए हैं :-

1. सभी देनदार / लेनदारों को उनके टी.डी.ए ऋण बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए ईमेल भेजा गया। इसपर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। नेक्टर ने टी.डी.ए के अधिकांश डिफॉल्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
2. लगभग सभी टीडीए ऋण चुककर्ताओं के विरुद्ध मध्यस्थता शुरू कर दी गई है। कुछ मामलों में पुनर्भुगतान के नए पुनर्नर्धारण पर हस्ताक्षर किए गए हैं और पुनर्नर्धारण के बाद पीडीसी प्राप्त हुई है। अन्य मामलों में पक्षकारों ने उनके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज होने के बाद बकाया राशि का भुगतान करना शुरू कर दिया है।
3. कुछ स्टॉक आइटम्स नेक्टर के अन्य स्थानों पर पड़े हैं। अधिकांश वस्तुएँ बाँस आधारित हैं, जिन्हें NECTAR/BCDI की बाँस से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग करने की योजना है। **नेट रियलाइज़ेबल वैल्यू (NRV)** का आकलन वर्तमान में प्रक्रिया में है।
4. GST के अंतर्गत TDS Deductor के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है तथा CGST अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5. ₹79,510/- की TDS डिफॉल्ट राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 से संबंधित है। इस संबंध में आवश्यक अनुपालन किया जाएगा।
6. नेक्टर ने हाल ही में 23.01.2025 से प्रभावी प्रोफेशनल टैक्स पंजीकरण प्राप्त किया है। 01.02.2025 से प्रोफेशनल टैक्स की कटौती प्रारंभ कर दी गई है। वर्तमान में प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान संबंधित विभाग के साथ समन्वय प्रक्रिया में है।
7. नेक्टर को भूमि लीज़ के आधार पर आवंटित की गई है तथा मेघालय सरकार से लीज़ अनुबंध प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।
8. आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है तथा वसूली की प्रक्रिया जारी है।
9. एक कार्यकारी परिषद की बैठक आयोजित की गई। दूसरी बैठक EC सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण आयोजित नहीं हो सकी।
10. बीसीडीआई की सभी गतिविधियों को डीसी (हस्तशिल्प) कपड़ा मंत्रालय और नेक्टर के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार किया जाता है।



उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र  
31 मार्च, 2025 को यथास्थिति तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)

राशि रु. में

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	विगत वर्ष
निकाय पूंजीगत निधि और देयताएं			
निकाय / पूंजीगत निधि	अनुसूची 1	1,102,122,502.54	1,105,391,028.83
आरक्षित और अधिशेष			
उदृष्टि / विन्यास निधि	अनुसूची 2	(13,91,7809.00)	1,21,05,868.00
सुरक्षित ऋण और उधार			
असुरक्षित ऋण और उधार			
अस्थगित ऋण देयताएं			
चालू देयताएं और प्रावधान	अनुसूची 3	28,285,853.75	25,823,327.91
कुल		<b>1,116,490,547.29</b>	<b>1,143,320,224.74</b>
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां (निवल)	अनुसूची 4	275,264,048.00	278,678,002.45
निवेश उदृष्टि / विन्यास निधि से		-	-
निवेश - अन्य		-	-
चालू परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम इत्यादि	अनुसूची 5	841,226,499.29	864,642,222.29
कुल		<b>1,116,490,547.29</b>	<b>1,143,320,224.74</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	अनुलग्नक ए		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**आर. एम. कोठारी एंड कम्पनी**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या:000143C

हस्ता /-

(सीए हर्ष अग्रवाल)

भागीदार

सदस्यता संख्या:315605

यूडीआईएन : 25315605BMKREZ6056

दिनांक 14.06.2025

गुवाहाटी

हस्ता /-

लेखा प्रबन्धक

(नेक्टर)

हस्ता /-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

(नेक्टर)

हस्ता /-

महानिदेशक

(नेक्टर)

**उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र**  
**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा**

राशि रु. में

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	विगत वर्ष
<b>आय</b>			
प्रचार गतिविधियों से आय	अनुसूची 6	15,945,562.00	17,549,246.00
अनुदान / सहायता	अनुसूची 7	132,984,783.00	151,984,810.00
शुल्क / अभिदान	अनुसूची 8	25,040.00	83,500.00
निवेशों से आय		-	-
रायल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय		-	-
अर्जित ब्याज	अनुसूची 9	14,551,424.02	14,250,424.00
अन्य आय (भागीदार अंशदान सहित)	अनुसूची 10	3,853,268.01	7,962,988.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / (ह्रास) और प्रगतिपरक कार्य	अनुसूची 11	-	-
<b>कुल (क)</b>		<b>167,360,077.03</b>	<b>191,830,968.00</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	अनुसूची 12	54,676,988.00	52,216,488.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	अनुसूची 13	46,503,910.81	42,115,518.07
अनुदान, सहायता आदि पर खर्च (परियोजना खर्च)	अनुसूची 14	57,073,501.00	85,111,330.00
ब्याज		-	-
पूर्व अवधि का व्यय	अनुसूची 15	1,510,696.00	2,189,129.00
मूल्य ह्रास (वर्ष के अंत में कुल जोड़)	अनुसूची 4	21,396,522.43	22,908,449.34
<b>कुल (ख)</b>		<b>181,161,618.24</b>	<b>204,540,914.41</b>
व्यय पर आय के आधिक्य के कारण शेष (क-ख)			
आय पर व्यय के अधिक्य के कारण शेष (ख-क)		(13,801,541.21)	(12,709,946.41)
बांस और बैत विकास संस्थान बीसीडीआई का अधिशेष		(155,794.33)	378,233.69
निकाय / पूंजीगत निधि को अंतरित अधिशेष के रूप में शेष			-
निकाय / पूंजीगत निधि को अंतरित घाटे के रूप में शेष		(13,957,335.54)	(12,331,712.72)

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**आर. एम. कोठारी एंड कम्पनी**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या:000143C

हस्ता /-

(सीए हर्ष अग्रवाल)

भागीदार

सदस्यता संख्या:315605

यूडीआईएन : 25315605BMKREZ6056

दिनांक 14.06.2025

गुवाहाटी

हस्ता /-

लेखा प्रबन्धक

(नेक्टर)

हस्ता /-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

(नेक्टर)

हस्ता /-

महानिदेशक

(नेक्टर)



**उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र**  
**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्त एवं भुगतान**

राशि रु. में					
प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
1 प्रारम्भिक शेष		1	व्यय		
क नकदी			क स्थापना खर्च		52,290,178.00
ख बैंक में जमा			ख प्रशासनिक खर्च	54,588,401.00	
i) चालू खाते में			ग बिक्री खर्च	50,508,071.00	45,801,853.44
ii) जमा खाते में	224,153,764.99	104,483,150.00	2 विभिन्न परियोजनाओं से निधियों के बदले भुगतान	-	-
iii) बचत खाते में	111,124,434.00	271,788,348.06	क खुद की परियोजनाओं पर खर्च	-	-
			प्रौद्योगिकियों का डिलेवरी एन्ड सर्विसेज़	14,230,799.00	16,945,180.00
2 प्राप्त अन्तुदान			राज्य सरकार को प्रौद्योगिकी सहायता	1,610,903.00	1,440,000.00
क भारत सरकार से	161,000,000.00	391,100,000.00	प्रौद्योगिकी निर्णय में राज्य सरकार को सहायता	-	4,044,429.00
ख भारत सरकार से- शिड प्रोजेक्ट	1,646,025.00	-	टेक्नोलॉजीज़-परामर्श परियोजनाएं	40,539.00	234,500.00
ग भू-स्थानिकपरियोजना	19,593,894.00		प्रौद्योगिकियों का विकास - अन्तुदान	23,434,194.00	27,525,052.00
घ PM-DeVINE परियोजना (डोनर)	121,504,500.00	33,046,601.00	प्रौद्योगिकी - विस्तार समेकन	8,632,001.00	16,268,737.00
ड एमबीबी-मैचालय		122,668,207.00	प्रौद्योगिकी विकास सहायता -	510,000.00	8,753,250.00

परियोजना	81,575,385.00				ऋण							
च सीएसआर-परियोजना	400,000.00				घरेलू परियोजनाएं (शहद मिशन और केसर)	5,459,583.00				4,988,362.00		
छ नेरामैक-सीबीबीओ	8,330,000.00	11,025,000.00			नेरामैक-सीबीबीओ	4,536,470.00	58,454,489.00			13,529,698.00		93,729,208.00
ज राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड - एनबीबी	7,336,000.00											
3 निवेशों से आय												
क उद्विष्ट / विन्यस्तनिधि से	-	-										
ख निजी निधियों से	-	-										
4 प्राप्त ब्याज												
क बैंक जमा पर	12,758,070.00	6,585,568.00			(बी) निर्धारित परियोजनाओं पर खर्च							
ख ऋण अग्रिम आदि पर	4,350,223.00	7,747,701.00			क) एसडीआर नागालैंड और मेघालय पुलिस के लिए अनुदान	-				-		
ग ऋण अग्रिम आदि	-	-			ख) टॉस प्रोजेक्ट के लिए अनुदान	-						
घ एचबीए अग्रिम पर ब्याज	-	-			ग) बांस प्रोजेक्ट के लिए अनुदान	-	-			7,931,351.00		-
ड आयकर वापसी पर ब्याज	2,154.00	-			घ) भू-स्थानिक परियोजना					10,414,019.00		
च दंडात्मक ब्याज	-	-			ड) PM-DeVine परियोजना (डॉनर)	5,106,882.00				48,792,245.00		
5 अन्य आय (विवरण दें)	-	-			च )एमबीबी-मेघालय परियोजना	160,676,608.00				110,878,171.00		
					छ) शिड प्रोजेक्ट	93,978,059.00						
						1,417,075.00				11,076,922.00		



					ज)HGH प्रोजेक्ट		-			3,994,023.00		
					झ)NLM प्रोजेक्ट		564,000.00			3,950,000.00		
					सीएसआर-परियोजना		42,981.00					
					राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड एनबीबी"		153,839.00	211,406.00	3,621,400.00	265,407,005.00	197,036,731.00	
					अन्य रसीद (आरटीआई)	3	-	-				
					विविध प्राप्तियां	क	2,928.44	53,200.00	10,088,466.00	34,495,944.00	-	
					अन्य रसीदें	ख	109,210.00	294,825.70		204,400,000.00	238,895,944.00	
					गेस्ट हाउस शुल्क	4	351,121.00	853,156.00	3,967,058.00	14,055,524.00		
						क			14,175,437.00	1,421,421.00		
									2,738,059.00	-	-	
6	उधार ली गई राशि				एनबीबी" परियोजना के तहत खर्च न की गई राशि भारत सरकार को वापस कर दी गई		-	-	242,600.00	17,156,096.00	1,421,421.00	
7	अनुबंध के लिए प्राप्त अग्रिम- जेएके मशीनरी						-	-				
					वित्त प्रभार (व्याज)	5			-	14,843.21	13,089.07	

				6	अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)				
8	कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)								
क	भागीदार अंशदान	451,623.00	873,150.00			ईएमडी-रिफंड और अन्य	375,500.00	630,000.00	
ख	टीडीए से वापसी	8,180,695.00	5,585,332.00			कर्मचारियों को अग्रिम	9,500.00	759,961.00	
ग	प्राप्त पाठियों से से प्राप्त राशि - पुनः आबंटन	10,409,576.00	3,556,225.00			जीएसटी	447,231.00	277,701.00	1,667,662.00
घ	व्यय के विरुद्ध प्राप्त राशि	404,625.00	-			आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए अग्रिम	-	-	
ड	परियोजना अग्रिम से वापसी	10,896,748.00	6,583.00				-	-	
च	आयकर से वापसी	310,346.00	16,224.00			सुरक्षा जमा राशि			1,491,921.00
छ	कर्मचारियों से वापसी	919,930.00	615,099.00			देय पक्षों को भुगतान			
ज	सीपीएफ और ईएमडी-प्राप्त	1,109,500.00	130,000.00	7	अंत शेष				
झ	एचजीएच प्रदर्शनी निधि प्राप्त हुई	-	7,781,920.00	क	हस्तगत रोकड़				
	देय राशि से वापसी	555,900.00	-	ख	बैंक बैलेंस				
		-			i) चालू खातों में		-	-	
					ii) जमा खातों में	212,977,426.48		224,153,764.99	
					iii) बचत खाते में	114,431,894.00	327,409,320.48	111,124,434.00	335,278,198.99
	कुल	788,425,980.69	967,626,206.50		कुल		788,425,980.69		967,626,206.50

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार



आर. एम. कोठारी एंड कम्पनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म पंजीकरण संख्या:000143C

हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-
(सीए हर्ष अग्रवाल)	लेखा प्रबन्धक	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	महानिदेशक भागीदार	(नेक्टर)
(नेक्टर)	(नेक्टर)			
सदस्यता संख्या:315605				
यूडीआईएन : 25315605BMKREZ6056				
दिनांक 14.06.2025				
गुवाहाटी				

## उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

राशि रु. में

अनुसूची 1 - निकाय पूंजीगत निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
नेक्टर		
आद्य शेष (प्रारंभिक शेष)	1,105,391,028.83	885,873,308.55
व्यय पर आय अधिक्य		
जोड़ : TDA का समायोजन	-	750,000.00
जोड़ : डीएसटी से प्राप्त पूंजी निधि	28,000,000.00	238,500,000.00
घटाएँ: आस्थगित राजस्व अनुदान	(3,150,970.75)	(6,594,336.00)
घटाएँ: डीएसटी को फंड रिटर्न	(14,160,220.00)	(806,231.00)
कुल	1,116,079,838.08	1,117,722,741.55
आय से अधिक व्यय	(13,957,335.54)	(12,331,712.72)
कुल	1,102,122,502.54	1,105,391,028.83
समाप्ति के समय बकाया	1,102,122,502.54	1,105,391,028.83
अंतिम शेष	1,102,122,502.54	1,105,391,028.83

अनुसूची 2 रिज़र्व और अधिशेष	चालू वर्ष	गत वर्ष
ए) निधियों का प्रारंभिक शेष	45,917,336.00	45,917,336.00
बी) निधियों में वृद्धि		
दान/अनुदान		
क) अनुदान सीड परियोजना के लिए अनुदान	1,646,025.00	130,632.00
ख) पीएम डिवाइन परियोजना के लिए अनुदान	121,633,000.00	33,046,601.00
ग) भू-स्थानिक परियोजना के लिए अनुदान	19,827,174.00	226,449.00
घ) मेघालय एमबीबी परियोजना के लिए अनुदान	81,575,385.00	122,668,207.00
ड) सीएसआर परियोजना के लिए अनुदान	400,000.00	-
च) डीसी हैन्डिकैप्ट के लिए अनुदान	-	6,486,978.00
छ) नेरमैक सी बी बी ओ	-	50,644.00
ज) एन बी बी परियोजना के लिए अनुदान	7,336,000.00	-
फंड के कारण किए गए निवेश से आय	-	-
अन्य परिवर्धन (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (ए + बी)	244,523,452.00	208,526,847.00
सी) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय		
i) पूंजीगत व्यय	-	-
टॉस बांस और एसडीआर परियोजना व्यय	-	-
सीड परियोजना के लिए व्यय	1,100,072.00	7,343,540.00
पीएम डिवाइन परियोजना के लिए व्यय	71,721,717.00	36,456,377.00
ii) राजस्व व्यय		
क) टॉस बांस और एसडीआर परियोजना व्यय	-	7,931,351.00
ख) सीड परियोजना के लिए व्यय	2,870,059.00	3,873,288.00
ग) पीएम डिवाइन परियोजना के लिए व्यय	79,579,333.00	13,312,731.00
घ) भू-स्थानिक परियोजना के लिए व्यय	4,816,278.00	10,388,382.00
ड) मेघालय एमबीबी परियोजना के लिए व्यय	93,882,821.00	108,759,762.00
च) सीएसआर परियोजना	42,981.00	-
छ) एचजीएच प्रदर्शनी व्यय	-	4,405,548.00
ज) एनएलएम परियोजना व्यय	564,000.00	3,950,000.00
झ) एनबीबी परियोजना	3,864,000.00	-
कुल (सी)	258,441,261.00	196,420,979.00
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (ए+बी+सी)	(13,917,809.00)	12,105,868.00
नोट:		
1. प्रकटीकरण अनुदान से जुड़ी शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों के तहत किया जाएगा		
2. केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधि को अलग निधि के रूप में दिखाया जाना है और किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं किया जाना है		



उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र  
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

राशि रु. में

अनुसूची 3 वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान	चालू वर्ष	गत वर्ष
क.वर्तमान देयताएँ		
1.प्रतिग्रहण	-	-
2.विविध लेनदार		
क. माल के लिए	5,155,506.00	855,506.00
ख. अन्य	486,477.00	750,869.00
3.अग्रिम प्राप्ति		
भागीदार अंशदान देय	820,785.00	820,785.00
4.उपार्जित ब्याज पर देय नहीं	-	
क.सुरक्षित ऋण / उधार		-
ख.असुरक्षित ऋण / उधार		-
5.सांविधिक देयताएँ		
क.बकाया राशि	-	-
ख.अन्य : टीडीएस देय	1,371,348.00	1,440,397.00
ग.जीएसटी देय	78,036.00	16,660.00
घ.पेशेवर शुल्क देय	10,400.00	-
6. अन्य वर्तमान देयताएँ		
प्रशासनिक खर्च देय (अनुलग्नक-1)	1,873,147.00	1,478,140.00
स्थापना खर्च देय (अनुलग्नक-2)	4,187,727.00	4,107,730.00
बांस और बेंत विकास संस्थान बीसीडीआई	4,171,747.75	6,461,560.91
एसडीआर टेक्नोलॉजी	9,434,880.00	9,434,880.00
पूँजीगत अनुदान वापसी योग्य	-	-
<b>बयाना राशि</b>		
प्रतिभूति प्रतिधारण मुद्रा - आर एस सोफ्टेक	46,800.00	46,800.00
ओवीएन बायोएनर्जी प्रा. लिमिटेड, गुडगाँव	1,00,000.00	1,00,000.00
श्री ईजीनियर्स, हैदराबाद	1,00,000.00	1,00,000.00
देवा बाम्बू एण्ड एलाईड इंड., इम्फाल	5,000.00	5,000.00
ढंजाल मकेनिकल वर्क्स प्रा. लिमिटेड	1,00,000.00	1,00,000.00
प्रिंस कार्बन एण्ड चारकोल इंड.	5,000.00	5,000.00
आर.डी। इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन, कोलकाता	1,00,000.00	1,00,000.00
ई. एम. डी. देय	239,000.00	
<b>कुल (क)</b>	<b>28,285,853.75</b>	<b>25,823,327.91</b>
ख. प्रावधान		
1.कराधान के लिए	-	-
2.ग्रेच्युटी	-	-
3.अधिवर्षिता / पेंशन	-	-
4.संचित अवकाश वेतन / नकदीकरण	-	-
5.व्यापार आश्वासन / दावे	-	-
6.अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
<b>कुल (ख)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>28,285,853.75</b>	<b>25,823,327.91</b>

उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र  
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलना-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 4-अचल संपत्ति-अमृत		सकल ब्लॉक	अवमूल्यन							
अवमूल्यन की दर	वर्ष की शुरुआत में लागत / मूल्य 01.04.2024	वर्ष के दौरान परिवर्धन 01.04.2024 - 30.09.2024	वर्ष के दौरान परिवर्धन 01.10.2024 - 31.03.2025	वर्ष के दौरान कटौती01.04. 2024 - 31.03.2025	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन 31.03.2025	वर्ष 01.04.2024 की शुरुआत में	ओपनिंग बैलेंस पर 01.04.2024	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर 01.04.2024 - 30.09.2024	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर 01.10.2024 - 31.03.2025	वर्ष के लिए मूल्यहास
A. अचल संपत्ति										
1. भूमि										
2. भवन										
a) फ्रीहोल्ड भूमि पर		-	-	-	-	-	-	-	-	
b) लीजहोल्ड भूमि पर		-	-	-	-	-	-	-	-	
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर		-	-	-	-	-	-	-	-	
d) भूमि पर अधिसूचनाएं जो इकाई से संबंधित नहीं हैं		-	-	-	-	-		-	-	
ई) आंतरिक कार्य	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण	15%	28,521,994.59	-	-	28,521,994.59	8,221,317.38	3,045,101.59	-	-	3,045,101.59
4. वाहन	15%	889,675.00	-	-	889,675.00	625,856.29	39,572.81	-	-	39,572.81
5. फर्नीचर और फिक्स्चर	10%	10,528,590.41	1,348,386.00	172,914.00	12,049,890.41	3,683,620.73	684,496.97	134,838.60	8,645.70	827,134.83
6. कार्यालय उपकरण	15%	9,461,946.13	1,483,755.00	334,970.00	11,253,262.13	4,482,870.84	746,861.29	222,563.25	25,122.75	994,134.83
7. कंप्यूटर/बाह्य उपकरणों	40%	38,174,879.07	3,876,268.00	800,000.00	42,847,242.07	25,071,963.33	5,241,166.30	1,550,507.20	160,000.00	6,951,166.30
8. इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन		-	-	-	-	-	-	-	-	-



9. प्रत्येकालय प्रत्येक	100%	15,904.67	-	-	-	15,904.67	15,904.67	-	-	15,904.67	-	-
11. अमूर्त संपत्ति-वेबसाइट	25%	37,067,567.00	2,122,173.00	2,950,000.00	-	42,139,740.00	16,892,463.00	5,043,776.00	530,543.25	5,943,069.25	19,304,207.74	20,175,104.00
12. ज्ञान और सहायक उपकरण	40%	18,864,987.00	-	750,000.00	-	19,614,987.00	10,253,545.18	3,444,576.73	-	3,594,576.73	5,766,865.09	8,611,441.82
चार वर्ष का योग (क)		143,525,543.87	8,830,582.00	5,007,884.00	31,314.00	157,332,695.87	69,247,541.42	18,245,551.68	2,438,452.30	21,396,522.43	66,688,632.00	74,278,002.45
(ख) पूर्णित कार्य प्रगति पर है		204,400,000.00	-	4,175,416.00	-	208,575,416.00	-	-	-	-	208,575,416.00	204,400,000.00
कुल (A+B)		347,925,543.87	8,830,582.00	9,183,300.00	31,314.00	365,908,111.87	69,247,541.42	18,245,551.68	2,438,452.30	21,396,522.43	275,264,048.00	278,678,002.45

उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र  
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 5 वर्तमान आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. वर्तमान आस्तियाँ		
1.मालसूची		
क. भंडार एवं स्पेयर्स	-	-
ख. फुटकर औज़ार	-	-
ग. बिक्री के लिए माल		
तैयार माल	2,874,229.27	2,874,229.27
तैयार होने वाला माल		
कच्चा माल		
घ. सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो - एसडीआर	-	-
2. लेनदारी लेखे (प्रचार गतिविधियाँ)		
क. छह महीने से अधिक की अवधि का बकाया ऋण	24,831,388.54	25,180,388.54
ख. अन्य	1,976,134.00	3,814,417.00
3. नकदी शेष (चेक / ड्राफ्ट्स और अग्रदाय सहित)	-	-
4. बैंकों में जमाराशियाँ	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
चालू खातों में	-	-
जमा खातों में (अल्पावधि जमा)	114,431,894.00	111,124,434.00
बचत खातों में	212,977,426.48	224,153,764.99
बांस और बैत विकास संस्थान बीसीडीआई बचत खातों में	7,272,895.33	9,718,502.82
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
चालू खातों में	-	-
जमा खातों में (अल्पावधि जमा)	-	-
बचत खातों में	-	-
5. डाकघर बचत खाते	-	-
<b>कुल (क)</b>	<b>364,363,967.62</b>	<b>376,865,736.62</b>



## उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 5 वर्तमान आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	चालू वर्ष	गत वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियाँ		
1. ऋण		
क) प्रौद्योगिकी विकास सहायता ऋण	454,185,554.00	461,856,249.00
ख) स्टाफ और अन्य ऋण		
अ) स्टाफ : अग्रिम (अनुलग्नक-3)	4,083,461.00	5,076,961.00
आ) अन्य : गतिविधियों में संलग्न संस्थाएँ / इकाई के समान उद्देश्य		
इ) अन्य - सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम	-	-
ई) कर्मचारियों से वसूली	-	-
2. अग्रिम और अन्य मदों में नकदी में वसूली योग्य राशि या वस्तु रूप में या मूल्य रूप में प्राप्त		
अ) पूँजी खाते पर	-	-
आ) परियोजनाओं के लिए पूर्व भुगतान	-	-
इ) प्रतिभूति		
प्रतिभूति : ई-साइन सीडेक	100,000.00	100,000.00
प्रतिभूति : एम टी एन एल	1,500.00	1,500.00
प्रतिभूति : किराया टी डी सी गुवाहाटी	166,662.00	166,662.00
प्रतिभूति : कुतुब सर्विस स्टेशन	10,000.00	10,000.00
प्रतिभूति : नेक्टर गेस्ट हाउस	200,000.00	200,000.00
प्रतिभूति : बी.एस.एन.एल	2,499.00	2,499.00
प्रतिभूति : पानी की बोतल	3,000.00	3,000.00
प्रतिभूति : एस ओ आई, शिल्लोंग	236,700.00	236,700.00
प्रतिभूति : गैस शिल्लोंग	3,550.00	3,550.00
प्रतिभूति : एपीडीसीएल (बिजली)	537,060.00	537,060.00
प्रतिभूति : रिलायंस	3,536.00	3,536.00
प्रतिभूति : गेस्ट हाउस गुवाहाटी	200,000.00	2,00,000.00
प्रतिभूति : GBP गुवाहाटी	217,125.00	217,125.00
एमडी : कृषि भवन	-	5,00,000.00
ई) अन्य		
मध्यस्थता वसूली व्यय	54,313.00	54,313.00
टाईफेक से वसूली	911,796.00	911,796.00
दिवालियापन के लिए शुल्क	45,436.00	45,436.00
पूर्वभुगतान बीमा शुल्क	-	8,120.00
पूर्वभुगतान वार्षिक रखरखाव शुल्क	-	3,837.00
भू-राजस्व शुल्क	-	1,000.00
पूर्वभुगतान वेबसाइट रखरखाव	200.00	825.00
एसडीआर की स्थापना अरुणाचल प्रदेश	435,963.00	435,963.00
ए बी कम्पोजिट प्रा लिमिटेड	1,797,982.95	1,797,982.95
आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम (अनुलग्नक-5)	4,861,091.00	5,350,532.00
3. उपचित आय		
अ) उद्दिष्ट / अक्षय निधि पर निवेश से	-	-
आ) निवेश पर - अन्य		
इ) ऋण और अग्रिम पर		
ई) अन्य : उपचित ब्याज	2,931,028.00	5,197,827.00

4. दावे प्राप्त		
जी एस टी प्राप्त	5,380,891.72	4,543,665.72
टी डी एस (निर्धारण वर्ष 2025-26)	493,183.00	-
टी डी एस (निर्धारण वर्ष 2025-25)	-	3,10,346.00
कुल (ख)	476,862,531.67	487,776,485.67
कुल (क+ख)	841,226,499.29	864,642,222.29



## उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 6 प्रचार गतिविधियों से आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रचार गतिविधियों से आय		
क) तैयार माल का विक्रय/व्यापार	-	-
ख) कच्चे माल का विक्रय	-	-
ग) रद्दी का विक्रय	-	-
घ) फुटकर	-	-
2. सेवाओं से आय		
क) श्रम तथा प्रक्रमण संसाधन शुल्क	-	-
ख) व्यावसायिक / परामर्शदात्री सेवाएं	8,826,004.00	3,250,846.00-
ग) एजेंसी आदृत और दलाली	-	-
घ) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण / संपत्ति)	-	-
ड) अन्य (निर्दिष्ट करें)	869,558.00	48,400.00
च) नेरमेक प्रोजेक्ट प्राप्ति	6,250,000.00	14,250,000.00
<b>कुल</b>	<b>15,945,562.00</b>	<b>17,549,246.00</b>

अनुसूची 7 अनुदान / सब्सिडी	चालू वर्ष	गत वर्ष
अप्रतिसंहरणीय अनुदान और सब्सिडी प्राप्य		
1.केंद्र सरकार से अनुदान सहायता	-	-
सहायता अनुदान (सामान्य)	92,000,000.00	115,400,000.00
घटाएँ : सहायता अनुदान (सामान्य)	(15,217.00)	(129,165.00)
सहायता अनुदान (वेतन )	41,000,000.00	37,200,000.00
घटाएँ : सहायता अनुदान (वेतन)	-	(486,025.00)
2.राज्य सरकार से	-	-
3.सरकारी एजेंसी से	-	-
	-	-
4. संस्थानों / कल्याणकारी निकाय से	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
<b>कुल</b>	<b>132,984,783.00</b>	<b>151,984,810.00</b>

अनुसूची 8 शुल्क / अंशदान	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. आरटीआई प्राप्तियां	-	-
3. संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. प्रक्रिया शुल्क	-	-
5. अन्य (निविदा राशि)	25,040.00	83,500.00
<b>कुल</b>	<b>25,040.00</b>	<b>83,500.00</b>

उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र  
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंक से प्राप्त	10,563,004.00	6,833,785.00
ख) गैर-अनुसूचित बैंक से प्राप्त	-	-
ग) संगठनों से प्राप्त	-	-
घ) अन्य	-	-
2.बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंक से प्राप्त	3,986,266.02	7,416,639.00
ख) गैर-अनुसूचित बैंक से प्राप्त	-	-
ग) डाकघर बचत खातों से प्राप्त	-	-
घ) अन्य	-	-
3.ऋणों पर		
क) कर्मचारी / स्टाफ से	-	-
ख) अन्य (दीर्घावधि के अग्रिम पर)	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
क) दंडात्मक ब्याज	-	-
ख) आयकर रिफंड पर ब्याज	2,154.00	-
<b>कुल</b>	<b>14,551,424.02</b>	<b>14,250,424.00</b>



उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र  
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 10 अन्य आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.आस्तियों के विक्रय / निपटान से प्राप्त		
क) स्वामित्व आस्तियों से	-	-
ख) अनुदान के बिना अर्जित आस्तियाँ, निःशुल्क प्राप्ति से	-	-
2.निर्यात प्रोत्साहन वसूली से		
3.विविध सेवाओं से प्राप्त शुल्क से (HGH परियोजना)	-	1,294,942.00 -
4.विविध आय		
आस्थगित राजस्व अनुदान	3,150,970.75	6,594,336.00
अन्य प्राप्ति	594,195.26	25,710.00
उपयोगकर्ता शुल्क	-	48,000.00
नवीनीकरण लागत की वसूली	108,102.00	-
<b>कुल (क)</b>	<b>3,853,268.01</b>	<b>7,962,988.00</b>
भागीदार अंशदान		
कुल (ख)	-	-
परियोजना अनुदान से वापसी	-	-
कुल (ग)	-	-
कार्यशील पूँजी ऋण से वापसी		
कुल (घ)	-	-
<b>कुल (क)+(ख)+(ग)+(घ)</b>	<b>3,853,268.01</b>	<b>7,962,988.00</b>

अनुसूची 11 तैयार माल और तैयार होने वाले माल के स्टॉक में वृद्धि / (घटत)	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) शेषमाल		
तैयार माल	28,74,229.27	28,74,229.27
तैयार होने वाला माल	-	-
ख) घटाएँ : आरंभिक स्टॉक	-	-
तैयार माल	28,74,229.27	28,74,229.27
तैयार होने वाला माल	-	-
<b>निवल वृद्धि / (घटत) {क-ख}</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

अनुसूची 12 स्थापना व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.वेतन	48,040,244.00	45,489,777.00
2.भत्ते एवं अधिलाभ	732,426.00	784,207.00
3.भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	493,740.00	574,821.00
4.मजदूरी	172,113.00	636,018.00
5.कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवा निवृत्ति लाभ पर खर्च	-	-
6. कर्मचारी कल्याण खर्च	-	-
7.एनपीएस योगदान	4,419,548.00	4,104,442.00
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	569,245.00	441,751.00
शिक्षा शुल्क	229,512.00	162,000.00
ईपीएफ प्रशासनिक प्रभार	20,160.00	23,472.00
<b>कुल</b>	<b>54,676,988.00</b>	<b>52,216,488.00</b>

**उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र**  
**31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

अनुसूची 13 प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) मरम्मत और रखरखाव	255,214.00	886,702.00
ख) किराया, दरें और कर	2,150,430.00	4,191,900.00
ग) कार किराया प्रभार	455,575.00	1,076,619.00
घ) डाक एवं कूरियर प्रभार	184,415.00	55,108.00
ड) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	690,479.00	652,182.00
च) यात्रा व्यय (घरेलू)	2,641,659.00	2,769,638.00
छ) संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय	1,459,289.00	2,543,780.00
ज) बैठक खर्च	270,277.00	175,936.00
अ) लेखा परीक्षा शुल्क	153,000.00	119,250.00
झ) विज्ञापन खर्च	687,466.00	387,062.00
ञ) सवारी खर्च	205,720.00	148,565.00
ट) दूरभाष एवं संचार खर्च	130,140.00	170,398.00
ठ) इंटरनेट खर्च	1,362,431.00	1,377,057.00
ड) एंटी वायरस शुल्क	-	514,946.00
ढ) हिंदी कार्यक्रम व्यय	676,837.00	202,871.00
ण) लीगल तथा व्यावसायिक शुल्क	1,910,230.00	1,639,518.00
त) परीक्षण एवं स्थापना शुल्क	438,033.00	-
थ) मध्यस्थता का खर्च	1,079,638.00	382,500.00
द) सदस्यता तथा शुल्क	1,072,109.00	296,315.00
ध) वार्षिक रखरखाव शुल्क	62,143.00	12,750.00
न) शिपिंग और परिवहन	645,045.00	283,054.00
न) वेबसाइट शुल्क	29,694.00	161,630.00
प) प्रचार एवं प्रसार	515,222.00	465,467.00
फ) विविध कार्यालयी व्यय	1,955,653.00	937,935.00
ब) विद्युत	740,310.00	225,320.00
भ) बैंक शुल्क	16,468.81	13,089.07
म) समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ	64,256.00	53,986.00
य) प्रदर्शनी व्यय	13,557,852.00	3,588,576.00
र) मानदेय -गैर सरकारी सदस्य	189,297.00	226,234.00
र) सुरक्षा शुल्क	725,561.00	375,101.00
ल) अतिथि गृह रखरखाव व्यय	992,747.00	347,124.00
ळ) बीमा शुल्क	94,634.00	22,738.00
ळ) उपभोग योग्य वस्तुएं	315,462.00	574,990.00
व) एनसीएलटी केस शुल्क	2,892,117.00	7,602,768.00
श) नेक्टर कार्यालय शिलांग और क्वार्टर का नवीनीकरण	2,698,814.00	2,679,824.00
ष) गृह व्यवस्था शुल्क	1,132,251.00	886,209.00
ह) उपभोग योग्य वस्तुएं	457,302.00	166,416.00
त्र) परामर्श शुल्क/सेवा शुल्क	3,038.00	1,246.00
ज) ई-ऑफिस सेवा शुल्क	3,593,102.00	5,900,714.00
<b>कुल</b>	<b>46,503,910.81</b>	<b>42,115,518.07</b>



उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र  
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 14 अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) संस्थानों / संगठनों को दिया जाने वाला अनुदान		
अनुदान (अनुलग्नक 4)	47,581,436.00	66,451,315.00
ऋण	-	-
ख) संस्थानों / संगठनों को दी जाने वाली सहायिकी	9,492,065.00	18,660,015.00
<b>कुल</b>	<b>57,073,501.00</b>	<b>85,111,330.00</b>

अनुसूची 15 पूर्वगामी व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) कर		34,020.00
ख) विविध कार्यालय व्यय"	40,563.00	-
ग) टेक्सेस		-
घ) अन्य कार्यालय व्यय		12,400.00
ड) CRA व्यय		845.00
च) कार किराया व्यय		1,29,040.00
छ) कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	67,500.00	77,495.00
ज) समाचार पत्र पत्रिकाएँ		603.00
झ) दूरभाष व्यय	13,803.00	13,803.00
ञ) रखरखाव शुल्क	71,515.00	-
ट) शिलांग कार्यालय का किराया		1,044,000.00
ठ) मानदेय	2,500.00	-
ड) सुरक्षा शुल्क	1,31,736.00	-
ढ) यात्रा व्यय	2,45,536.00	-
ण) ग्रंट्स/टी	227,769.00	876,923.00
त) यातायात व्यय	3,858.00	-

था) इंटरनेट शुल्क	55,085.00	-
द) कूरियर एवं डाक शुल्क	11,062.00	-
द शुल्क एवं सदस्यता	24,000.00	-
ध) परियोजना व्यय	489,441.00	-
न) शिपिंग एवं परिवहन शुल्क	100,158.00	-
प) अनुवाद शुल्क	26,880.00	-
<b>कुल</b>	<b>1,510,696.00</b>	<b>2,189,129.00</b>



## उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र

## अनुलग्नक -1

## प्रशासनिक व्यय देय

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
वाहन व्यय देय	23,268.00	-
यात्रा व्यय देय (घरेलू)	97,973.00	-
चिकित्सा व्यय देय	7,249.00	-
लीगल तथा व्यावसायिक शुल्क देय	78,480.00	78,480.00
इंटरन स्टैंडपेंड देय	10,000.00	10,000.00
परियोजना कर्मचारियों के लिए देय वेतन	1,389,660.00	1,389,660.00
<b>कुल</b>	<b>1,873,147.00</b>	<b>1,478,140.00</b>

## अनुलग्नक -2

## स्थापना व्यय देय

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
एनपीएस योगदान देय	725,489.00	703,353.00
वेतन देय	3,445,790.00	3,327,093.00
QTR शुल्क देय	13,064.00	13,064.00
वेतन देय	3,384.00	64,220.00
<b>कुल</b>	<b>4,187,727.00</b>	<b>4,107,730.00</b>

## अनुलग्नक -3

## स्टाफ अग्रिम

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
<b>खुदरा रोकड़ अग्रिम</b>		
बी के मंथन		3,000.00
गेवीन वेंडरोफ		30,000.00
फेडलिया डींगदोह		20,000.00
भरत फुकन		20,000.00
अजित कुमार		20,000.00
राजदीप सिंह		20,000.00
सीमोन फुकन		20,000.00
<b>यात्रा अवकाश अग्रिम</b>		
देबरता गॉंगओई		62,000.00
डॉ कॉलिन रेनथेली		26,000.00
<b>एचबीए एडवांस</b>		
अंकित श्रीवास्तव	1,946,000.00	2,138,000.00
सोमनाथ नाथ	2,035,000.00	2,179,000.00

आधिकारिक अग्रिम एवं दौरा अग्रिम		
बी के मंथन	-	24000.00
मनोरंजन डेका	-	-
रवि सिंह	11,840.00	11,840.00
राकेश कुमार शर्मा	-	-
राम कुमार	-	16,000.00
अक्षय कुमार पट्टी	-	46,000.00
साइमन फुकन	-	100,000.00
वीरेंद्र कुमार यदाव	-	30,000.00
बिरेन्द्र कुमार शर्मा	-	30,000.00
ध्रुवज्योति बर्मन	9,500.00	-
रवि कुमार सिंह	81,121.00	81,121.00
डॉ कॉलिन रेनथेली	100,000.00	100,000.00
डॉ अभिनव कान्त	100,000.00	100,000.00
<b>कुल</b>	<b>4,083,461.00</b>	<b>5,076,961.00</b>



उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र		
		अनुलग्नक - 4
अनुदान		
विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
राज्य सरकार को निर्णय समर्थित प्रौद्योगिकी सहायता		
शहद परीक्षण प्रयोगशाला-दीमापुर (NBHM)	-	1,050,000.00
आईओटी आधारित नर्स कॉलिंग सिस्टम	-	-
मोबाइल क्लिनिक रोगी निगरानी प्रणाली	-	1,494,429.00
रोगी निगरानी प्रणाली	-	-
सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज-सेरछिप, मिजोरम	-	-
सौर ऊर्जा कोल्ड स्टोरेज की स्थापना-मेघालय	-	1,500,000.00
<b>कुल (A)</b>	-	<b>4,044,429.00</b>
राज्य सरकार को प्रौद्योगिकी सहायता		
पारंपरिक की आकृति डिजाइन और प्रतिकृति प्रणाली	-	1,440,000.00
स्टेम एजुकेशन लैब	1,610,903.00	
<b>कुल (बी)</b>	<b>1,610,903.00</b>	<b>1,440,000.00</b>
प्रौद्योगिकी परामर्श परियोजनाएं		
उत्पादों का भौतिक रसायन और शेल्फ जीवन मूल्यांकन-निफ्ट	-	234,500.00
आईआईटी दिल्ली द्वारा फूड बॉक्स और लिक्विड कंटेनर का विकास	40,539.00	-
<b>कुल (C)</b>	<b>40,539.00</b>	<b>234,500.00</b>

प्रौद्योगिकी अनुदान का विकास		
CSIR-CIMAP (सौर सुगंध आसवन का विकास)	-	374,645.00
कोम्बुचा-पारस बायोसाइंसेज का विकास	-	180,000.00
गमुसा लूम टाइप के लिए सॉफ्टवेयर का विकास		(6,583.00)
कपड़ा और फैशन का बुनियादी उन्नयन- आरकेएम	5,00,000.00	-
सीमांत किसानों के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली	-	-
कम लागत वाला जल उपचार संयंत्र-एनआईटी, मणिपुर	-	352,000.00
ट्यूलिप की खेती	-	265,230.00
मधुमक्खी पालन कॉलोनी	67,500.00	270,000.00
इमल्सफाइड मीट प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स		1,000,000.00
बोतलबंद गन्ना रस परियोजनाएँ	9,50,000.00-	-
अदरक और हल्दी प्रसंस्करण की स्थापना -कामरूप	3,36,000.00-	-
इलेक्ट्रिक स्मोकर-डीओ नाम के साथ धूम्रपान इकाई की स्थापना	1,51,800.00	303,600.00
	-	-
कम लागत उपयोगकर्ता के अनुकूल झाड़ू बाइंडिंग	160,000.00	640,000.00
वन सर्वेक्षण के लिए एयरोस्टेटिक ड्रोन	-	944,000.00
कृषि एकीकृत खेती सिक्किम	472,800.00	315,200.00
बायोडिग्रेडेबल लो-कॉस्ट किट (IIT-Delhi)	-	246,400.00
पारंपरिक कौना क्राफ्ट को उत्प्रेरित करना	1,376,160.00	-

इलिकियम ग्रिफिथी का विकास - मोन्यूल	-	1,380,000.00
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड-सीईएम का विकास	-	752,435.00
विकास तात्कालिक हाइपोक्लोराइट जेनरेटर-एम्प्रिकेयर	-	621,600.00
प्रशिक्षण/उत्पादन-बेल मेट यूनिट-आईआईटी गुव का विकास	264,416.00	-
डिमोरिया एरी क्लस्टर	160,000.00	320,000.00
मसाला एवं सुगंधित आसवन इकाई की स्थापना	-	1,077,000.00
लोटस फाइबर का निष्कर्षण और प्रसंस्करण	-	485,000.00
अनानास पत्ती फाइबर का निष्कर्षण-एनआईटी मेघा	-	506,352.00
स्वदेशी और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके रेशम उत्पादन विकास	3,99,380.00	-
रंगीन मोती उत्पादन-कपास यूनी में नवाचार	-	260,000.00
निष्कर्षण और उत्पादन के लिए तकनीकी पुनरोद्धार - इकोफाइबर	931,795.00	-
थर्मल इंजरी स्टो का उपयोग करते हुए एकीकृत नवाचार		264,224.00
कम्पोस्टेबल बायोप्लास्टिक-इकोस्टार्च का विनिर्माण		198,600.00
बहुउद्देशीय इको एंजाइम प्रोसेसिंग यूनिट (MEEPU)		1,180,620.00
पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ई-टूरिसम पोर्टल	1,919,707.00	-
मशरूम स्पॉन उत्पादन इकाई	328,000.00	-
फर्नीचर बनाने के लिए वेस्ट वुड का पुनर्चक्रण		250,000.00
हाथ और घर का बना चॉकलेट बनाने का संयंत्र स्थापित करना	-	555,600.00
सरसों प्रसंस्करण इकाई की स्थापना-डाटा परामर्श	-	852,000.00
उत्पाद विकास इकाई-एनईआर की स्थापना	-	500,000.00



रबर प्लांट की स्थापना-इचामती मेघालय	-	117,420.00
मिनी प्रोसेसिंग फिश फीड मिल की स्थापना	1,976,000.00	-
ग्रीनहाउस एक्वापोनिक खेती - शिलांग	1,589,600.00	-
ग्रीनहाउस में एंथूरियम और गुलाब की खेती	2,000,000.00	-
पूर्वोत्तर (NE) में चिकित्सा एवं फैशन परिधानों का विनिर्माण	950,000.00	-
झाग्रापार (असम) में दुग्ध प्रसंस्करण इकाई	690,000.00	-
पूर्वोत्तर (NE) में फल एवं सब्जियों हेतु मोबाइल प्रसंस्करण इकाई	2,624,596.00	-
कुक्कुट एवं मछली चारा निर्माण इकाई	548,000.00	-
बड़ी इलायची का उत्पादन	932,000.00	-
इमल् सीफाइड मांस उत् पाद परियोजनाएं	-	1,000,000.00
बायोडिग्रेडेबल कप और प्लेटों का निर्माण	-	511,098.00
अनानास छीलने प्रौद्योगिकी-यूकेबी	1,184,000.00	1,184,000.00
बेकरी उद्योग-परियोजना में गेहूं के आटे का प्रतिस्थापन	990,000.00	990,000.00
फ्रूट वाइन प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना	1,000,000.00	1,000,000.00
राजा मिर्च की खेती और प्रसंस्करण की स्थापना	-	1,000,000.00
नींबू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	500,000.00	2,000,000.00
माइक्रो काजू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	475,000.00	2,000,000.00
भाषा सह मल्टीमीडिया लैब की स्थापना	-	1,628,028.00
चाय प्रसंस्करण इकाई-मिजोरम की स्थापना	475,000.00	2,000,000.00
<b>कुल (D)</b>	<b>23,434,194.00</b>	<b>27,518,469.00</b>
<b>प्रौद्योगिकी वितरण और सेवाएं</b>		
माइक्रोबियल कंसोर्टियम द्वारा सहायता प्राप्त ऑर्गेनिक कंपोजिटिंग -	1,500,000.00	-

मिज़ोरम		
बांस बुनाई हस्तशिल्प - प्रशिक्षण	956,800.00	
समावेशी सतत और आय सृजन	651,152.00	651,152.00
आईआईटीडीसी, अगरतला में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	-	3,200,000.00
असमिया भाषा में मोबाइल स्किल डेवलपमेंट कोर्स	1,200,000.00	800,000.00
दृष्टिबाधित के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	3,39,000.00	1,356,000.00
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत डेयरी प्रौद्योगिकी पहल	935,292.00	-
बम्बू उत्पादों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	2,276,603.00
प्रशिक्षण पर हांड्स पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	(367,000.00)	367,000.00
कौशल विकास प्रशिक्षण-एनआईटी (आंध्र प्रदेश)	-	2,620,900.00
कौशल विकास शिक्षा कार्यक्रम-जीआईएस	4,324,075.00	-
केले के रेशे हथकरघा एवं हस्तशिल्प पर प्रशिक्षण-		327,500.00
सूक्ष्मप्रचार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम		162,035.00
एनईआर में तकनीकी-उद्यमिता को बढ़ावा देना		1,339,200.00
जीवन जीने के लिए हिंडेन संस्कृति एनईआर संगीत को जागृत करना		1,497,500.00
नागा भोजन का सुरक्षित, स्वच्छ और मानकीकृत उत्पादन	1,000,000.00	-
मशरूम से पौष्टिक सुपरफूड बनाना	-	958,800.00
सांस्कृतिक विरासत का डिजिटलीकरण और दस्तावेज़ीकरण	3,30,000.00	-
ड्रोन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम	420,220.00	938,490.00
टोफू मूल्य संवर्धन के माध्यम से आजीविका सृजन	225,000.00	450,000.00
जैविक खेती के लिए स्मार्ट एग्री एआई-संचालित मृदा पैरामीटर निगरानी	555,660.00	-

कुल (E)	13,863,799.00	16,945,180.00
प्रौद्योगिकी विस्तार और समेकन		
हाथी सेब पाउडर उत्पादन इकाई	1,900,000.00	-
कोको प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन	-	680,000.00
ग्रामीण किसानों का सशक्तिकरण: तकनीकी हस्तक्षेप आवश्यक	822,500.00	-
ग्रामीण किसानों की आजीविका में वृद्धि-	-	398,165.00
योगा मैट उत्पादन में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप एवं उन्नयन-सीमांग	-	1,469,243.00
क्विक मिश्रण और विनिर्माण के सुखाने के लिए संयंत्र	320,000.00	-
मौजूदा खाद्य सामग्री में वृद्धि।	-	2,000,000.00
ग्रीन ब्रिकेट एंटरप्राइज की स्थापना	997,391.00	997,391.00
सामुदायिक रेडियो (सीआरएस) की स्थापना	489,400.00	2,307,598.00
चाय उत्पादन इकाई-नागालैंड की स्थापना	381,210.00	1,524,840.00
एरी स्पून मिल की स्थापना	1,000,000.00	1,000,000.00
इको फ्रेंडली पेपर कप का बड़े पैमाने पर उत्पादन	970,000.00	970,000.00
आजीविका संवर्धन-एकीकृत स्पाइस प्रोसेसिंग-यूनिट	-	1,000,000.00
शाकाहारी चमड़े के उत्पादों का उत्पादन केला फाइबर	751,500.00	751,500.00
पारंपरिक नागा जनजातीय खाद्य उत्पादों को बढ़ावा	-	1,000,000.00
उपयोग करने योग्य उत्पादों के लिए लकड़ी की बर्बादी का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग	1,000,000.00	1,000,000.00



आरसी-कन्याका/सीआरई के विकास के लिए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन	-	1,170,000.00
<b>कुल (एफ)</b>	<b>8,632,001.00</b>	<b>16,268,737.00</b>
<b>अनुदान पर कुल व्यय (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)</b>	<b>47,581,436.00</b>	<b>66,451,315.00</b>
<b>अनुलग्नक - 5</b>		
<b>आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए अग्रिम</b>	<b>चालू वर्ष</b>	<b>गत वर्ष</b>
हरि ओम सेल्स एंड सर्विस	2,860,089.00	2,860,089.00
एस. पी. इंजीनियर्स	1,658,197.00	1,658,197.00
एफपीवी मॉडल इंटरनेशनल	83,667.00	83,667.00
आरसी बाजार	87,388.00	87,388.00
व्योम विस्टा	171,750.00	171,750.00
करुणेश एंटरप्राइजेज	-	489,441.00
<b>कुल</b>	<b>4,861,091.00</b>	<b>5,350,532.00</b>

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

## उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (नेक्टर)

1. सोसाइटी ने लेखांकन के प्रोद्भवन आधार को अपनाया है। वार्षिक खाते केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित एवं लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।
2. अचल संपत्तियाँ कम संचित मूल्यहास पर बताई गई हैं। परिसंपत्ति को उसके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने की कोई अन्य लागत और खरीद मूल्य का समावेश है।
3. अचल संपत्तियों पर मूल्यहास की गणना आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित की गई दरों के अनुसार क्रमागत हास विधि (डब्ल्यूडीवी)से किया गया है।
4. भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभों को अंशदान लाभ योजना के रूप में परिभाषित किया गया है और इस तरह के अंशदानों के देय होने पर उन्हें उस वर्ष के आय और व्यय विवरण में दर्शाया जाता है।
5. ग्रेच्युटी लाभ का हिसाब और भुगतान बीमांकित मूल्यांकन पद्धति के बिना सोसाइटी द्वारा की गई आंतरिक गणना के अनुसार किया जाता है।
6. माल-सूची मूल्य लागत मूल्य पर है अथवा शुद्ध वसूली मूल्य जो भी कम हो
7. विभिन्न परियोजनाओं के तहत जारी की गई राशि को उस वर्ष के व्यय के रूप में शामिल किया जाता है जिसमें भुगतान किया जाता है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि राशि का पूरी तरह से विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है या नहीं।
8. विभिन्न परियोजनाओं के तहत जारी की गई राशि को उस वर्ष के व्यय के रूप में देखा जाएगा जिसमें भुगतान इस तथ्य के बावजूद किया गया है कि क्या राशि पूरी तरह से विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग की गई है या नहीं।

**आर. एम. कोठारी एंड कम्पनी**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या:000143C

हस्ता /-

(सीए हर्ष अग्रवाल)

भागीदार

सदस्यता संख्या:315605

यूडीआईएन : 25315605BMKREZ6056

दिनांक 14.06.2025

गुवाहाटी

हस्ता /-

लेखा प्रबन्धक

(नेक्टर)

हस्ता /-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

(नेक्टर)

हस्ता /-

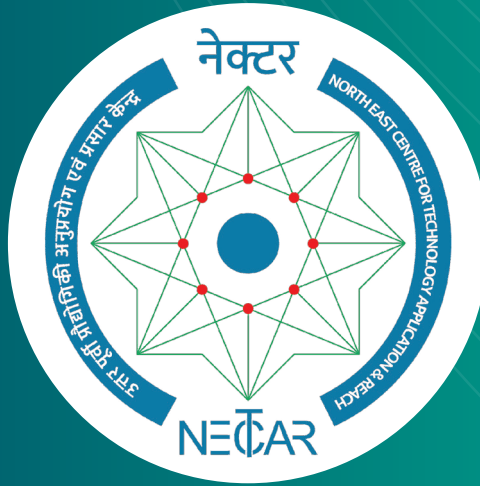
महानिदेशक

(नेक्टर)









## मुख्यालय :

- 📍 सर्वे ऑफ इंडिया कैम्पस,  
बोनी ब्रे एस्टेट,  
बारिक प्वाइंट,  
शिलांग - 793 001  
मेघालय
- ☎ 0364-2505034 (प्रशासनिक)  
2506085 (स्वागत)

## गुवाहाटी का पता :

- 📍 उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार  
केन्द्र (नेक्टर )  
प्रथम तल, गुवाहाटी बायोटेक पार्क,  
अमीनगांव, नामती जलाह,  
गुवाहाटी, असम – 781031

## नई दिल्ली कार्यालय का पता :

- 📍 द्वितीय मंजिल  
विश्वकर्मा भवन,  
शहीत जीत सिंह मार्ग,  
नई दिल्ली -110016
- ☎ 011-26566778 | 26513967

## आगरतला का पता :

- 📍 बांस एवं बेंत विकास संस्थान (बीसीडीआई)  
सी/ओ उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार  
केन्द्र (नेक्टर)  
'लिचुबागान, पी.ओ. - अगरतला सचिवालय  
अगरतला - 799010 (त्रिपुरा)